

5

के. वीरास्वामी

बनाम

भारत संघ और अन्य

25 जुलाई, 1991

[ बी. सी. राय, के. जगन्नाथ शेट्टी, ललित मोहन शर्मा, एम. एन. वेंकटचलैया और जे. एस. वर्मा ]

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947: एसएस. 2 , 5 ( 1 ) ( ई), 5 (2), 6 (1) (सी) - लोक सेवक-आर्थिक संसाधनों या संपत्ति का कब्जा आय के ज्ञात स्रोतों को विभाजित नहीं करता है-अधिवर्षिता के बाद अभियोजन-पिछली मंजूरी-चाहे आवश्यक हो।

उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश-चाहे 'लोक सेवक, अधिनियम के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी-अनुमोदन प्राधिकरण-कौन है। अनुमोदन प्राधिकरण-चाहे पदानुक्रम में ऊर्ध्वाधर रूप से बेहतर हो अभिलेख जिसमें लोक सेवक का पद मौजूद है।

सी. एल. ( ग ) एस। 6 ( 1 ) -चाहे उससे स्वतंत्र हो या अलग खंड (ए) और (बी)-सामान्य न्याय का नियम-की प्रयोज्यता।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता-चाहे उसके अनुप्रयोग से प्रभावित हो उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-न्यायालय द्वारा दिशा-निर्देश जारी करना। भारतीय दंड संहिता, 1860: एसएस. 19 , 21- " जज "-चाहे वह शामिल हो। उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश-चाहे लोक सेवक 'एस के तहत। 2 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। भारत का संविधान, 1950: अनुच्छेद 74,79,121,211,124,217,

2 18 - किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए कार्यवाही शुरू करने का प्रावधान चाहे किसी न्यायाधीश के आपराधिक अभियोजन को रोकने का आधार हो एस के तहत अपराध। 5 ( 1 ) ( ड ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता-निवारण के अनुप्रयोग का प्रभाव उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए भ्रष्टाचार अधिनियम, 1947। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: एसएस. 154 , 173 ( 2 ) , 173 ( 5 ) — एस के तहत लोक सेवक द्वारा किया गया अपराध। 5 ( 1 )

( ई ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947-के बारे में शिकायत-की जाँच आवश्यकताएँ-पुलिस रिपोर्ट/आरोप पत्र-सामग्री:

साक्ष्य अधिनियम, 1872: धारा 106-धारा 106 के तहत किया गया अपराध। 51 1 ) ( ई ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947-संपत्ति का कब्जा अस्वीकृत ज्ञात स्रोतों को विभाजित करें-चाहे तथ्य लोक सेवक के विशेष ज्ञान के भीतर हो-सबूत का बोझ-किस पर। शब्द और वाक्यांश: " संतोषजनक लेखा "-का अर्थ। वैधानिक व्याख्या: इजस्टेम जेनरिस का नियम-समझाया गया।

अपीलार्थी, एक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ एक शिकायत सी. बी. आई. में की गई थी, जिस पर एस. के तहत मामला दर्ज किया गया था। 5 ( 2 ) एस के साथ पढ़ें। 5 ( 1 ) ( ई ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 का 24.2.1976 पर पंजीकृत किया गया था। 28.2.1976 पर विशेष अदालत में एफ. आई. आर. दायर किया गया था।

न्यायाधीश। अपीलार्थी 9.3.1976 से छुट्टी पर चला गया और सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 8.4.1976 पर सेवानिवृत्त हो गया।

जांच का समापन एस के तहत आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने में हुआ। 173 ( 2 ) , क्र. विशेष न्यायाधीश के समक्ष 15.12.1977 पर अपीलार्थी के विरुद्ध पी. सी.

आरोप-पत्र में कहा गया है कि अपीलार्थी ने 1.5.1969 पर मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने के बाद धीरे-धीरे धन जमा करना शुरू कर दिया

संपत्ति और अपने नाम पर और अपनी पत्नी और दो बेटों के नाम पर आर्थिक संसाधनों और संपत्ति के कब्जे में था, जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख और मामले के पंजीकरण की तारीख के बीच की अवधि के लिए आय के अपने ज्ञात स्रोतों से असमान था, और इस तरह उसने धाराओं के तहत आपराधिक कदाचार का अपराध किया। 5 ( 1 ) ( ई ), एस के तहत दंडनीय। 5 ( 2 ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947। विशेष न्यायाधीश ने अपीलार्थी की उपस्थिति के लिए प्रक्रिया जारी की।

इस बीच, अपीलार्थी ने एस के तहत उच्च न्यायालय का रुख किया। 482 , क्र. पी. सी. उक्त आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए।

इस मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने की थी जो

2 ने आवेदन खारिज कर दिया: 1 बहुमत; लेकिन शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 132 (1) और 134 (1) (सी) के तहत एक प्रमाण पत्र प्रदान किया।

इस न्यायालय में अपील में अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं -

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने इस तरह के अभियोजन के लिए किसी लोक सेवक को हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के रूप में एस के तहत प्रावधान किया है। 6 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 अनिवार्य है और किसी न्यायाधीश को हटाने की शक्ति किसी एक व्यक्ति के अधिकार में निहित नहीं है, बल्कि 191 है।

संविधान के अनुच्छेद 124 (4) के तहत संसद के दोनों सदनों और राष्ट्रपति में निहित है कि संसद एस के उद्देश्यों के लिए मंजूरी देने वाला प्राधिकरण नहीं हो सकता है। 6 और यदि राष्ट्रपति को प्राधिकरण माना जाता है, तो वह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता है क्योंकि वह अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और कार्यपालिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप करके शक्ति का दुरुपयोग कर सकती है। 6 यह केवल उन मामलों में लागू होता है जहां लोक सेवक और उसे हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के बीच स्वामी और सेवक संबंध है, और जहां सार्वजनिक कार्यालयों का ऊर्ध्वाधर पदानुक्रम है और मंजूरी देने वाला प्राधिकरण जनता के किस कार्यालय में पदानुक्रम में ऊर्ध्वाधर रूप से श्रेष्ठ है।

जिस कर्मचारी के खिलाफ मंजूरी मांगी गई है वह मौजूद है; कि संविधान के अनुच्छेद 124 (4) द्वारा परिकल्पित तरीके को छोड़कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी वरिष्ठ न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ कोई अभियोजन शुरू नहीं किया जा सकता है; कि कोई भी कानून किसी लोक सेवक को ऐसा करने से मना नहीं करता है

उसके कब्जे में आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक संपत्ति है और ऐसा कब्जा केवल तभी अपराध बन जाता है जब लोक सेवक

इसके लिए जवाबदेह होने में असमर्थ; और यह कि लोक सेवक एक

जाँच अधिकारी द्वारा परिसंपत्तियों और आय के ज्ञात स्रोतों के बीच असंगतता की व्याख्या करने का अवसर और आरोप पत्र में ऐसा अभिकथन होना चाहिए, और यह उल्लेख करने में विफलता कि

आवश्यकता आरोप पत्र को दूषित कर देगी और इसे अमान्य कर देगी और, एस के तहत कोई अपराध नहीं। 5 ( 1 ) ( ड ) अधिनियम का निर्धारण किया जा सकता है।

प्रश्नों के बारे में: ( 1 ) चाहे वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या

सर्वोच्च न्यायालय एस के अर्थ में एक 'लोक सेवक' है। 2 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947; (2) क्या मुख्य न्यायाधीश सहित उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश या सर्वोच्च

न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के तहत किसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है; और (3) जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अपने पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी है ताकि वह प्राधिकारी धारा 1947 के प्रावधानों के तहत न्यायाधीश के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दे सके। 6 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947।

अपील को खारिज करते हुए, यह न्यायालय, पकड़ना: ( प्रति बहुमत-रे, शेड्टी, शर्मा और वेंकटचलैया,

जे जे)।

1. उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 'सार्वजनिक' होता है। सेवक 'एस के अर्थ के भीतर। 2 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 .

2. प्रमुख सहित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अभियोजन 192

न्यायाधीश, या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त करने के बाद शुरू किया जा सकता है, जैसा कि एस द्वारा परिकल्पित है। 6 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। पर वर्मा, जे. (असहमति) -

1. ( i) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश एक संवैधानिक पदाधिकारी होता है, भले ही वह एक सार्वजनिक पद धारण करता हो और उस अर्थ में वह

लोक सेवक की व्यापक परिभाषा में शामिल किया जा सकता है। लेकिन एक लोक सेवक जिसकी श्रेणी अभियोजन के लिए मंजूरी देने के लिए एस द्वारा परिकल्पित नहीं है। 6 अधिनियम के दायरे से बाहर है, अधिनियम के दायरे में आने का इरादा नहीं है।

1 ( ii) 1964 के संशोधन द्वारा संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर लागू नहीं होता है और

सुप्रीम कोर्ट।

( प्रति बहुमत-रे, शेड्टी और वेंकटचलैया, जे. जे.)

3.1 एस के उद्देश्य के लिए। 6 ( 1 ) ( ग) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति सक्षम प्राधिकारी हैं।

किसी उच्चतर न्यायालय के न्यायाधीश के अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी देना।

3.2 एस के तहत कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। 154, क्र. पी. सी. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या

उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जब तक कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को मामले में दोषी नहीं ठहराया जाता है।

3.3 यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश स्वयं इसके खिलाफ व्यक्ति हैं

जिनके खिलाफ आपराधिक कदाचार के आरोप प्राप्त होते हैं, सरकार उच्चतम न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश या न्यायाधीश से परामर्श करेगी।

3.4 अभियोजन के लिए मंजूरी देने के प्रश्न की जांच के चरण में इसी तरह का परामर्श होगा और इसकी आवश्यकता होगी।

यह आवश्यक और उचित है कि मंजूरी का प्रश्न भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के अनुसार निर्देशित किया जाए।

शर्मा। जे. (विपरीत)

इस बारे में कि न्यायाधीश के अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी देने का अधिकार वास्तव में कौन है, यह एक ऐसा मामला है जो तत्काल मामले में उत्पन्न नहीं हुआ था और जब यह सीधे सामने आएगा तो अंततः निर्णय लेना होगा। कैसे 193

कभी भी, कला के तहत हटाने के मुद्दे। 124 (4) संविधान और एस के तहत मंजूरी। 6 संसद से मंजूरी प्राप्त करने के लिए अधिनियम को जोड़ा जा सकता है।

वर्मा। जे. (असहमति)

3. अधिनियम की धारा 6 उच्च न्यायालयों या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर लागू नहीं होती है

उच्चतम न्यायालय और ऐसे संवैधानिक पदाधिकारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के दायरे में नहीं आते हैं।

प्रति बी. सी. रे, जे.

1. उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश आता है।

एस के तहत लोक सेवक की परिभाषा के भीतर। 2 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947. और वह अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी है। [ 223 ई-एफ ]

2.1 एक न्यायाधीश आपराधिक कदाचार करने के लिए उत्तरदायी होगा।

एस के अर्थ के भीतर। 5 ( 1 ) ( ई) अधिनियम के, यदि उसके कब्जे में उसके ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक आर्थिक संसाधन या संपत्ति है।

आय का जिसके लिए वह संतोषजनक रूप से लेखा नहीं दे सकता है। [ 217 बी]

2.2 उच्च न्यायालय का न्यायाधीश प्रो से मुक्त नहीं होगा।

अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपने पद के कार्यकाल के दौरान किए गए आपराधिक अपराधों के लिए प्रतिभूति। [ 223 एफ]

3.1 एक वरिष्ठ के न्यायाधीश के खिलाफ अभियोजन शुरू करने के लिए

एस के तहत आने वाले आपराधिक दुराचार के लिए न्यायालय। 5 ( 1 ) ( ई) अधिनियम के अनुसार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी अनिवार्य है। [ 217 सी-डी; 221 जी]

3.2 भारत के राष्ट्रपति के पास नियुक्त करने के साथ-साथ करने की भी शक्ति है

संविधान के अनुच्छेद 124 में दिए गए साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा देना और इससे पहले, वह न्यायाधीश की नियुक्ति करने और हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी होने के नाते, अनुच्छेद 124 के खंड (4) और (5) में परिकल्पित प्रक्रिया के अनुसार, धारा 124 के प्रावधानों के तहत न्यायाधीश के अभियोजन के लिए मंजूरी देने का अधिकार माना जा सकता है। 6 ( 1 ) ( c) अंदर

एस में दिए गए अपराधों के संबंध में। 5 ( 1 ) ( ड) अधिनियम। [ 225 जी-एच; 226 ए-बी]

3.3 एक न्यायाधीश को तुच्छ पक्ष से पर्याप्त रूप से बचाने के लिए

प्रतिभूति और अनावश्यक उत्पीड़न राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे जो [1991] 3 एस. सी. आर. के समक्ष रखी गई सभी सामग्रियों पर विचार करेंगे।

सुपर उसे और मामले में संतुष्ट होने के बाद संबंधित न्यायाधीश के खिलाफ अभियोजन शुरू करने या प्राथमिकी दर्ज करने की मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति को अपनी सलाह दें। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। [ 226 बी-सी]

यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय है कि यह एक उपयुक्त मामला नहीं है

संबंधित न्यायाधीश पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर राष्ट्रपति न्यायाधीश पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं देगा। यह संबंधित न्यायाधीश को अनावश्यक उत्पीड़न के साथ-साथ उसके खिलाफ तुच्छ अभियोजन से बचाएगा। [ 226 सी]

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मामले में, अध्यक्ष

डेंट उच्चतम न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करेगा जो वह उचित और उचित समझे और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या न्यायाधीशों द्वारा उसे दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। [ 226 डी]

3.4 तत्काल मामले में, अपीलार्थी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था

पद पर रहते हुए और सी. बी. आई. द्वारा उनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करने की तारीख को लोक सेवक बनना बंद कर दिया और इसलिए एस. के तहत कोई मंजूरी नहीं दी गई। 6 ( 1 ) ( ग) अधिनियम आवश्यक था। [ 227 ए; 228 सी]

आर. एस. नायक बनाम ए. आर. अंतुले, [1984] 2 एस. सी. आर. 495, संदर्भित।

4.1 उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश

न्यायालय एक संवैधानिक पदाधिकारी है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने और न्यायाधीश को प्रभावी ढंग से अपना कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए है।

एक न्यायाधीश के रूप में कर्तव्यों और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए, यहां तक कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के खिलाफ आई. एस. के संबंध में भी, उसे संविधान के अनुच्छेद 124 या अनुच्छेद 217 में अनिवार्य रूप से सन्निहित करके कार्यपालिका के नियंत्रण और प्रभाव से पूरी तरह से स्वतंत्र बनाया जाता है कि एक न्यायाधीश को केवल अनुच्छेद 124 के खंड (4) और (5) में निहित तरीके से ही अपने पद से हटाया जा सकता है। [ 222 बी-डी]

4.2 महाभियोग या संबोधन द्वारा हटाने की शक्ति, एक व्यक्ति के पास है

अच्छे व्यवहार के दौरान पद धारण करना, उच्च पद धारकों के लिए उनके कार्यकाल को आनंद के बजाय अच्छे व्यवहार में से एक बनाकर सुरक्षित की गई स्वतंत्रता का एक आवश्यक प्रतिरूप है। [ 224 डी-ई]

4.3 उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश केवल

संविधान के अनुच्छेद 124 (4) में स्पष्ट रूप से निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का पालन करने के बाद पारित राष्ट्रपति के आदेश द्वारा साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाया जाएगा। संसद के प्रत्येक सदन के अभिभाषण के बिना राष्ट्रपति की संख्या 195 नहीं है।

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई.

उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर उनके पद से हटाने का आदेश देने के लिए संविधान के तहत सशक्त। इसलिए, इस का भंडार शक्ति केवल राष्ट्रपति में नहीं है, बल्कि इसका प्रयोग अनुच्छेद में दिए गए तरीके से संसद के प्रत्येक सदन द्वारा एक संबोधन के बाद किया जाता है।

124 ( 4 ) . [ 218 बी-एच; 219 ए]

भारत संघ बनाम। सकलचंद, ए. आई. आर 1977 एस. सी. 2328 और एस. पी. गुप्ता

और ओआरएस। वी. भारत के राष्ट्रपति और अन्य, ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 149, का उल्लेख किया गया।

5. कोई स्वामी और सेवक संबंध या नियोक्ता नहीं है और

एक न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति के बीच कर्मचारी संबंध जिसमें संघ की कार्यकारी शक्ति संविधान के अनुच्छेद 53 के प्रावधानों के तहत निहित है। [ 222 ई]

6. इसके अनुरूप कुछ विधि विकसित करना आवश्यक है

भ्रष्टाचार और अधिग्रहण के गंभीर आरोपों या आय से अधिक संपत्ति के कब्जे के मामलों में मंजूरी का अनुदान, जिसके लिए न्यायाधीश संतोषजनक रूप से जिम्मेदार नहीं हो सकता है या संपत्ति का कब्जा न्यायाधीश की आय के स्रोतों के लिए अनुचित है। अन्यथा, यह उच्च पद की गरिमा, सम्मान और विश्वसनीयता और अखंडता पर एक गंभीर अवरोध पैदा करेगा जो एक वरिष्ठ न्यायाधीश रखता है जिसके परिणामस्वरूप जनता के आकलन में न्यायाधीशों के उच्च पद के लिए गरिमा और सम्मान का क्षरण होता है। [ 225 ई-एफ]

7.1 मुकदमा चलाने से पहले पूर्व मंजूरी देने का उद्देश्य

उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सहित एक लोक सेवक को न्यायाधीश को अनावश्यक उत्पीड़न और तुच्छ अभियोजन से बचाना है, विशेष रूप से न्यायाधीश को ऐसे मामले में निर्णय देने के लिए पक्षपातपूर्ण अभियोजन से बचाना है जो सरकार या उसके अधिकारियों के खिलाफ जाता है, हालांकि अच्छे कारणों और कानून के शासन के आधार पर। [ 226 डी-ई]

7.2 एक न्यायाधीश के खिलाफ तुच्छ अभियोजन शुरू नहीं किया जा सकता है

केंद्र सरकार या उसके किसी भी अधिकारी के खिलाफ निर्णय देना (इस तरह का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 124 के अर्थ के भीतर दुर्व्यवहार नहीं है। [ 226 जी-एच]

शमशेर सिंह और अनूर। वी. पंजाब राज्य, [1975] I एस. सी. आर. 814 और

जी. के. डाफ्टरी बनाम ओ. पी. गुप्ता, ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 1132, का उल्लेख किया गया।

पर शेट्टी, और वेंकटचलैया, जेजे।

[ 1991 ] 3 एस सी आर।

196

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1. एस के तहत परिभाषित "लोक सेवक" अभिव्यक्ति। 2 में से

भ्रष्टाचार निवारण अनुच्छेद, 1947 का अर्थ है एक लोक सेवक जैसा कि धाराओं में परिभाषित किया गया है। 21 , आई. पी. सी. की शुरुआत से ही आई. पी. सी. " प्रत्येक न्यायाधीश "एस के तहत परिभाषित लोक सेवक की श्रेणियों में एक स्थान पाता है। 21 और यह अभिव्यक्ति सभी न्यायाधीशों और सभी न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों को इंगित करती है। यह एक सामान्य शब्द है और अधिनियम में सामान्य शब्द को संकीर्ण रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। इसे व्यापक अर्थ प्राप्त करना चाहिए जब तक कि इसके विपरीत सकारात्मक संकेत न हो। अधिनियम में इस तरह का कोई संकेत नहीं है। इसलिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को 'लोक सेवक' की परिभाषा से अलग नहीं किया जा सकता है। [ 237 सी; 240 डी; 242 ए-बी]

2.1 लोक सेवक पर विशिष्ट अपराधों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

एस में लगाया गया। 5 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947, जब तक कि एस के तहत पूर्व मंजूरी न हो। 6 सक्षम प्राधिकारी से अभियोजन के लिए। [ 237 ई]

2.2 खंड (ग) की प्रयोज्यता के लिए दो आवश्यकताएँ हैं।

एस. 6 ( 1 ) उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश के लिए-न्यायाधीश को एक लोक सेवक होना चाहिए, और उसे अपने पद से हटाने के लिए एक सक्षम प्राधिकारी होना चाहिए। यदि इन दोनों आवश्यकताओं का पालन किया जाता है, तो एक न्यायाधीश अधिनियम के संचालन से बच नहीं सकता है। [ 240 बी-सी)

2.3 न्यायाधीशों के साथ ठीक उसी तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए जैसे कि

आपराधिक अपराध के संबंध में कोई अन्य व्यक्ति। केवल रिश्वत लेने या भ्रष्टाचार के अपराध के संबंध में आपराधिक अभियोजन के लिए मंजूरी की आवश्यकता होती है। न्यायाधीशों को आपराधिक अभियोजन से सुरक्षा प्रदान करने वाला कोई कानून नहीं है। [ 252 ए-बी]

उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करना आपत्तिजनक नहीं है।

लोक सेवक द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को समाप्त करने से पहले एक न्यायाधीश पर आपराधिक कदाचार के लिए मुकदमा चलाया जाता है और इसके अलावा, साबित दुर्व्यवहार के लिए संसद द्वारा उसे हटाने से पहले एक न्यायाधीश पर मुकदमा चलाया जाता है। [ 252 डी-ई]

"सिद्ध दुर्व्यवहार" जो हटाने का आधार है

संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (4) के तहत न्यायाधीश कुछ मामलों में एस के तहत आपराधिक दुराचार का अपराध भी शामिल कर सकते हैं। 5 ( 1 ) अधिनियम से। लेकिन जब तक न्यायाधीश को संसद द्वारा हटाया नहीं जाता, तब तक आपराधिक अभियोजन को रोकने का कोई आधार नहीं है। एक संसद की शक्ति है और दूसरा आपराधिक न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है। दोनों एक दूसरे से अलग हैं। [ 251 ए-सी]

3.1 एस के उद्देश्य के लिए। 6 ( 1 ) ( c) अधिनियम के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति

अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है 197

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई.

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ।

3.2 धारा 6 (1) जनता की सभी श्रेणियों को अपने दायरे में लाती है।

एस में परिभाषित के रूप में सेवक। 21 आई. पी. सी. के खंड (ए) और (बी) उन लोक सेवकों के मामलों को शामिल करेंगे जो इसके संबंध में कार्यरत हैं

संघ या राज्य के मामले और उनके कार्यालय से हटाने योग्य नहीं हैं

संबंधित सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी के साथ बचत करें। खंड (ग) में कहा गया है कि किसी अन्य व्यक्ति के मामले में मंजूरी उसे उसके पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की होगी।

[ 238 ई-एफ]

एस के खंड (ए) और (बी) के प्रावधान। 6 [ ( 1 ) ] निश्चित रूप से

लोक सेवकों की श्रेणियाँ और 'अन्य' जिसका अर्थ है शेष

श्रेणियों को खंड (ग) के दायरे में लाया जाता है। खंड (ग) पूर्ववर्ती दो खंडों से अलग और अलग है। खंड की संरचना इजसडेम जेनरिस के नियम को लागू करने की अनुमति नहीं देती है।

[ 240 ए-बी }

3.3 इजसडेम जेनरिस नियम का अनुप्रयोग केवल सामान्य लोगों के लिए है।

निम्नलिखित शब्द जो कम सामान्य हैं, या सामान्य शब्द जो समान प्रकृति के विशेष और विशिष्ट शब्दों को कम करता है। ऐसे मामले में, सामान्य शब्द या अभिव्यक्ति को केवल उसी तरह की चीजों को समझने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए जो पूर्ववर्ती विशिष्ट शब्दों या अभिव्यक्तियों द्वारा निर्दिष्ट की गई हैं। सामान्य शब्द को विशेष और विशिष्ट शब्दों के समान जीनस तक सीमित माना जाता है। [ 239 एफ-जी }

3.4 निर्माण जो सामान्य विधान को बढ़ावा देगा

प्रावधान में अंतर्निहित उद्देश्य को एक ऐसे निर्माण की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो नहीं होगा। [ 247 ए]

यदि उपयोग की जाने वाली विधायी भाषा का शाब्दिक अर्थ नेतृत्व करेगा

अधिनियम के उद्देश्य को विफल करने वाले परिणामों के लिए, न्यायालय शाब्दिक अर्थ की अवहेलना करने और एक उदार निर्माण को अपनाने में उचित होगा जो विधायिका के उद्देश्य को प्रभावित करता है। [ 247 ए-बी]

एस. ए. वेंकटरमन बनाम राज्य, [1958] एससीआर 1040 और एम।

नारायणन बनाम। केरल राज्य, [1963] 2 पूरक। एस. सी. आर. 724, संदर्भित।

कानून पर क्रेज़, (6 वीं संस्करण। पी। 531) संदर्भित।

3.5 संसद की संरचना को देखते हुए, ट्रांस की प्रकृति

प्रत्येक सदन में कार्य करते हुए कार्य या कार्यवाही, अनुच्छेद 121 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के आचरण के संबंध में चर्चा पर, सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1991] 3 एस. सी. आर. को छोड़कर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में निषेध।

198

राष्ट्रपति के समक्ष उन्हें हटाने की प्रार्थना करते हुए एक अभिभाषण प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर, संसद मंजूरी देने के लिए उचित प्राधिकरण नहीं हो सकती है।

न्यायाधीश के अभियोजन के लिए मंजूरी। तथापि, इसका यह अर्थ नहीं है कि उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीश अधिनियम के दायरे से बाहर रखे जाने के हकदार हैं। [ 245 सी-एफ]

3.6 धारा 6 का उदारतापूर्वक अर्थ निकाले जाने की आवश्यकता है। यह दंडात्मक प्रावधान नहीं है, बल्कि दंडात्मक मामले में लोक सेवकों के लिए सुरक्षा का एक उपाय है।

अधिनियमन। यह उन अधिकारियों को इंगित करता है जिनकी मंजूरी के बिना एक लोक सेवक पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यह पर्याप्त है कि इसके तहत पहले से लिखे गए अधिकारी अनुभाग की भाषा के उचित अर्थ में आते हैं। ( 247 बी-सी)

"हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी" अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है

एस। 6 ( 1 ) ( ग ) इसका अर्थ एक ऐसे प्राधिकारी के रूप में भी लिया जाना चाहिए जिसके आदेश या पुष्टि के बिना लोक सेवक को हटाया नहीं जा सकता है। न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति का आदेश अनिवार्य है। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अनुच्छेद के तहत निर्धारित विशेष प्रक्रिया के साथ प्रस्ताव पारित किया गया। 124 ( 4 ) स्वयं न्यायाधीश के खिलाफ कार्य नहीं करेगा। न्यायाधीश को कार्यालय से हटाने का कोई परिणाम नहीं होगा।

जब तक कि इसका पालन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा नहीं किया जाता है। कला का खंड (4)। 124 नकारात्मक शब्दों में है। राष्ट्रपति का आदेश अनिवार्य है।

न्यायाधीश को हटाना। केवल राष्ट्रपति ही यह आदेश दे सकते थे। ( 247 सी-ई, 248 सी]

3.7 स्वामी और सेवक का संबंध जैसा कि आम कानून में आम तौर पर होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बीच मौजूद नहीं है। न्यायपालिका और सरकार। न्यायाधीश बाध्य नहीं होते हैं और न ही वे अपने कर्तव्यों के दायरे में सरकार के किसी भी आदेश का पालन करने का वचन देते हैं। वास्तव में, वे न्यायाधीश नहीं हैं यदि वे अपने कर्तव्यों के पालन में सरकार द्वारा निर्देशित होने की अनुमति देते हैं। [ 239 बी-डी]

भारत संघ बनाम। एच. एस. सेठ, [1978] 1 एस. सी. आर. 423, संदर्भित।

3.8 यह आवश्यक नहीं है कि अभियोजन के लिए बर्खास्तगी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी या जनता को हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी सेवक को उस पदानुक्रम में ऊर्ध्वाधर रूप से श्रेष्ठ होना चाहिए जिसमें लोक सेवक का पद मौजूद है। एस के तहत ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। 6 अधिनियम से। अभियोजन के लिए मंजूरी देने की शक्ति किसी भी प्राधिकारी को प्रदान की जा सकती है। ऐसा प्राधिकरण उस विभाग का हो सकता है जिसमें लोक सेवक काम कर रहा है या कोई बाहरी प्राधिकरण हो सकता है। बस इतना ही आवश्यक है कि प्राधिकरण को लोक सेवक के खिलाफ एकत्र की गई सामग्री की सराहना करने की स्थिति में होना चाहिए ताकि यह तय किया जा सके कि क्या अभियोजन पक्ष

विचार करना तुच्छ या अटकलबाजी है। [ 249 बी-सी] 199

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई.

आर. एस. नायक बनाम ए. आर. अंतुले, [1984] 2 एस. सी. सी. 183, प्रतिष्ठित।

जहाँ तक न्यायपालिका का संबंध है, राष्ट्रपति बाहरी व्यक्ति नहीं हैं। वह.

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है

अपनी कार्यकारी शक्तियों का उल्लेख करें। [ 249 ई]

शमशेर सिंह बनाम। पंजाब राज्य, 11975] 1 एससीआर 365 और एस. पी.

गुप्ता बनाम। भारत संघ, [1982] 2 एस. सी. आर. 365, संदर्भित।

नियुक्ति के मामले में संसद की कोई भूमिका नहीं है

न्यायाधीश सिवाय इसके कि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। [ 249 जी-एच]

3.9 तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि

एस के तहत अपीलार्थी के अभियोजन के लिए कोई मंजूरी नहीं। 6 अधिनियम की आवश्यकता थी क्योंकि वह प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त हो गए थे

सेवानिवृत्ति की आयु और उस तारीख को लोक सेवक नहीं था

आरोप पत्र दाखिल करना अनुपलब्ध है। सवाल अब रेस इंटीग्रा नहीं है। ( 254 जी-एच; 255 सी]

एस. ए. वेंकटरमण बनाम राज्य, [1958] एससीआर 1040; सी. आर. बंसी बनाम।

महाराष्ट्र राज्य, [1971] 3 एस. सी. आर. 236 और के. एस. धर्मादतन बनाम। केंद्र सरकार और अन्य।, [ 1979 ] 3 एस. सी. आर. 832, संदर्भित।

आर. एस. नायक और ओआरएस बनाम ए. आर. अंतुले, [1984] 2 एस. सी. आर. 183, संदर्भित

को।

4.1 न्यायाधीशों को संरक्षित करने के लिए विभिन्न सुरक्षा प्रदान की जाती हैं

न्यायपालिका की स्वतंत्रता। उन्हें अपने न्यायिक कर्तव्य के निर्वहन में उनके द्वारा किए गए या करने का आदेश दिए गए किसी भी कार्य के लिए नागरिक दायित्व से सुरक्षा प्राप्त है, चाहे ऐसा न्यायिक कर्तव्य किया गया हो या नहीं।

उनके अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर, जैसा कि एस के तहत प्रदान किया गया है। 1 न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850। इसी तरह एस। 77, आई. पी. सी. उन्हें न्यायिक रूप से किए गए कार्य के लिए आपराधिक दायित्व से सुरक्षा प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आचरण पर चर्चा संसद या राज्य विधानमंडलों में नहीं होगी, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 121 और 211 में परिकल्पित है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों का गठन अभिलेख न्यायालयों के रूप में किया गया है जो अनुच्छेद 129 और 215 द्वारा निर्धारित अवमानना करने के लिए दंडित करने की शक्ति रखते हैं। न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 दीवानी और आपराधिक अवमानना कार्यवाही करने की शक्ति प्रदान करता है। कार्यपालिका न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में सक्षम

है लेकिन उन्हें हटाने का अधिकार नहीं है। हटाने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 द्वारा परिकल्पित महाभियोग के अनुरूप प्रक्रिया द्वारा संसद में निहित है।

( 251 ई-एच; 242 ई] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1991]

3 एस. सी. आर.

200

4.2 एस द्वारा विचार किए गए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी। 6 यह केवल ईमानदार लोक सेवकों को तुच्छ और परेशान करने वाले अभियोजन से बचाने के लिए है। सक्षम प्राधिकारी अभियोजन के लिए मंजूरी देने से इनकार कर सकता है यदि कथित अपराध का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री नहीं है या यह तुच्छ है या ईमानदार अधिकारी को परेशान करने का इरादा है। लेकिन वह मंजूरी देने के लिए कर्तव्यबद्ध है यदि एकत्र की गई सामग्री शिकायत किए गए अपराध को विश्वास दिलाती है। लोक सेवक पर मुकदमा चलाने का विवेकाधिकार अभियोजन एजेंसी से छीन लिया जाता है और लोक सेवक को हटाने के लिए प्राधिकरण परिसर में निहित किया जाता है। अभियोजन एजेंसी की तुलना में अभियोजन पक्ष निष्पक्ष और उचित तरीके से एकत्र की गई सामग्री का आकलन करने और यह निर्धारित करने के लिए बेहतर स्थिति में होगा कि अभियोजन के लिए मंजूरी दी जानी चाहिए या नहीं। [ 237 एफ-जी; 238 ए-सी]

4.3 यह आशंका कि कार्यपालिका सबसे बड़ी वादी होने के नाते न्यायाधीशों पर मुकदमा चलाने की शक्ति का दुरुपयोग कर सकती है, हमारे विचार में

मुकदमेबाजी वाला समाज अनुचित या निराधार है। अधिनियम एस जैसे कुछ सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। 6 और न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाता है जो कार्यपालिका से स्वतंत्र है। लेकिन ये सुरक्षा उपाय पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। न्यायाधीश के खिलाफ किसी भी शिकायत और सी. बी. आई. द्वारा इसकी जांच को यदि प्रचारित किया जाता है, तो न्यायाधीश और वादी जनता पर इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का विवेकपूर्ण उपयोग करने की आवश्यकता है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ईमानदार और निडर न्यायाधीशों को परेशान न किया जाए। वे.

इसकी रक्षा की जानी चाहिए। ( 252 जी-एच; 253 ए-सी]

5.1 न्यायाधीशों के लिए अलग कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। यह अधिनियम न्यायपालिका में लागू करने में मूल रूप से दोषपूर्ण नहीं है। वह सब कुछ है

कुछ दिशानिर्देश निर्धारित करने की आवश्यकता है ताकि अधिनियम का दुरुपयोग न हो।

न्यायपालिका की विचाराधीनता खुद को रखने के अवसर से वंचित नहीं करेगी इस तरह के दिशानिर्देशों को कम करें। यह न्यायालय सीमित अधिकार क्षेत्र का न्यायालय नहीं है।

आज बहुत अधिक है। यह विवाद निपटान और अंतर से आगे बढ़ रहा है। स्थायी कानून बनाना। यह अस्पष्ट क्षेत्रों में एक समस्या समाधानक है। [ 253 ई-जी]

5.2 भारत के मुख्य न्यायाधीश एक सहभागी पदाधिकारी हैं।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला और

उच्च न्यायालयों के लिए भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनसे परामर्श किया जाना है।

एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण और आयु का प्रश्न

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा।

उससे परामर्श करें। भारत के मुख्य न्यायाधीश के प्रमुख होने के नाते न्यायपालिका मुख्य रूप से न्यायपालिका की अखंडता और निष्पक्षता से संबंधित है।

न्यायपालिका। इसलिए यह आवश्यक है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की आयु 201 न हो।

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई.

किसी न्यायाधीश के खिलाफ विचार किए गए किसी भी आपराधिक मामले की तस्वीर से बाहर रखा जाता है। वह मामले में अपनी राय देने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे और भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श बहुत बढ़ा होगा। सही निष्कर्ष पर पहुँचने में सरकार की सहायता। [ 253 एच; 254 ए-बी]

5.3 इसे लागू करना इस न्यायालय की जिम्मेदारी और कर्तव्य है

न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए अधिक अनुकूल रूप में विद्यमान कानून। [ 253 जी]

5.4 तत्काल मामले में तब भारत के मुख्य न्यायाधीश थे

अपनी राय देने का अनुरोध किया कि क्या अपीलार्थी पर अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश द्वारा यह विचार व्यक्त करने के बाद ही कि अपीलार्थी पर अधिनियम

के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।  
( 253 डी]

6.1 एस के तहत कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। 154 , क्र. पी.  
सी

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ जब तक कि इस मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श नहीं किया जाता है। [ 254 सी]

6.2 सरकार द्वारा राय को उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किया गया। यदि उसकी राय है कि यह अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए उपयुक्त मामला नहीं है, तो मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। [ 254 डी]

6.3 यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश स्वयं इसके खिलाफ व्यक्ति हैं

जिनके खिलाफ आपराधिक कदाचार के आरोप प्राप्त होते हैं, सरकार उच्चतम न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश या न्यायाधीश से परामर्श करेगी। अभियोजन के लिए मंजूरी देने के प्रश्न की जांच के स्तर पर इसी तरह का परामर्श होगा और यह आवश्यक और उचित होगा कि मंजूरी का प्रश्न भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के अनुसार निर्देशित किया जाए।  
( 254 डी-ई]

आशंका है कि अधिनियम का दुरुपयोग होने की संभावना है

इस प्रकार संपार्श्विक उद्देश्य के लिए कार्यपालिका को कम किया जाएगा। [ 254 ई]

7. यह कहना अनुचित है कि दोषसिद्धि और सजा नहीं है।

न्यायाधीश के न्यायालय में बैठने पर रोक। यदि कोई न्यायाधीश आपराधिक दुराचार या नैतिक अधमता से जुड़े किसी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो उसके लिए खुद को न्यायालय से दूर रखना उचित है। उसे स्वेच्छा से न्यायिक कार्य से हट जाना चाहिए और आपराधिक अभियोजन के परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि वह किसी आपराधिक मामले में केंद्रित है तो उसे तुरंत अपना इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक कि वह अपने [1991] 3 एस. सी. आर. पर रोक नहीं लगा लेता।

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दोषसिद्धि और सजा। वह तब तक पीठ में बैठने के अपने अधिकार पर जोर नहीं देगा जब तक कि वह सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा आरोप से मुक्त नहीं हो जाता। [ 250 डी-एफ]

न्यायपालिका के पास पर्स या तलवार की कोई शक्ति नहीं है। यह जीवित रहता है।

केवल जनता के विश्वास से और समाज की स्थिरता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि जनता का विश्वास न डगमगाए। जिस न्यायाधीश के चरित्र पर संदेह है और जिसके नैतिकता और ईमानदारी के मानकों पर संदेह है, उसे न्यायिक स्वतंत्रता नहीं हो सकती है और वह जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकता है। उसे स्वेच्छा से न्यायिक कार्य और प्रशासन से हट जाना चाहिए। [ 250 एफ-जी]

जे. आर. स्पेंसर द्वारा जैक्सन की न्याय की मशीनरी, 8 वीं संस्करण। पीपी।

369-70 संदर्भित किया गया।

#### 8.1 अधिनियम की धारा 5 (1) (ई) एक वैधानिक अपराध पैदा करती है जो

अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया जाना चाहिए। धारा का पहला भाग लोक सेवक के पास मौजूद संपत्ति के प्रमाण से संबंधित है। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना है कि अभियुक्त या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के पास आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक आर्थिक संसाधन या संपत्ति है। जब अभियोजन पक्ष द्वारा उस दायित्व का निर्वहन किया जाता है तो आपराधिक दुराचार के अपराध का श्रेय लोक सेवक को दिया जाता है। हालाँकि, यह उसके लिए खुला है कि वह परिसंपत्तियों की इस तरह की असमानुपातिकता के लिए संतोषजनक रूप से जवाबदेह हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जब तक लोक सेवक संपत्ति की अधिकता का हिसाब देने में सक्षम नहीं है, तब तक कोई अपराध नहीं है। यदि किसी के पास अपने वैध साधनों से परे संपत्ति है, तो यह चला जाता है।

बिना यह कहे कि अतिरिक्तता गलत तरीके से प्राप्त लाभ से होती है। [ 259 डी-ई; 260 ई-एफ]

#### 8.2 आय का स्रोत साबित करना लोक सेवक का काम है या

जिन साधनों से उसने संपत्ति अर्जित की। वह पदार्थ है

एस का खंड (ई)। 5 ( 1 ) . यह धारा वैधानिक बचाव उपलब्ध कराती है जिसे अभियुक्त द्वारा साबित किया जाना चाहिए। यह एक प्रतिबंधित रक्षा है जो है

अभियुक्त को अनुपातहीनता के लिए उत्तरदायी ठहराया गया

आय पर परिसंपत्तियाँ। लेकिन सबूत का कानूनी बोझ

अभियुक्त अभियोजन पक्ष जितना कठोर नहीं है। लेकिन यह सिर्फ

अभियोजन पक्ष के संस्करण पर कुछ संदेह नहीं डालना। [ 260 एफ-जी, 259 ई-एफ]

विधायिका ने सलाह दी है कि "संतोषजनक" अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाए।

खाता "। "संतोषजनक" शब्द पर जोर दिया जाना चाहिए। कि

इसका मतलब है कि अभियुक्त को अदालत को संतुष्ट करना होगा कि उसका स्पष्टीकरण योग्य है

स्वीकृति। अभियुक्त पर रखे गए सबूत का बोझ एक प्रमाण है।

हालांकि यह एक प्रेरक बोझ नहीं है। लेकिन आरोपी ने,

"संभावनाओं के संतुलन पर" सबूत के उस बोझ का निर्वहन कर सकता है

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई.

अभियोजन पक्ष के साक्ष्य और/या बचाव पक्ष के साक्ष्य से। 1259 एफ-जी]

8.3 संसद कुछ लोगों पर बोझ डालने के लिए सक्षम है।

अभियुक्त पर भी और विशेष रूप से मामलों में "विशेष रूप से

उसके ज्ञान के भीतर"। ( एस. साक्ष्य अधिनियम की धारा 106)। चतुराई से प्रतिभूति समर्थक से, चीजों की प्रकृति में, एक लोक सेवक के मामलों को जानने की उम्मीद नहीं की जा सकती है जो आय के अपने ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक संपत्ति के संसाधनों के कब्जे में पाया जाता है। यह उसे समझाना है। अभियुक्त पर बोझ डालने वाला ऐसा कानून नहीं हो सकता है

अनुचित, अन्यायपूर्ण या अनुचित माना जाता है। न ही इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के विपरीत माना जा सकता है। यह सिद्धांत कि सबूत का भार हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है और कभी भी आरोपी पर नहीं जाता है, हर मामले में पालन किया जाने वाला एक सार्वभौमिक नियम

नहीं है। यह सिद्धांत केवल इसके विपरीत वैधानिक प्रावधान के अभाव में लागू किया जाता है।  
[ 260 ए-सी]

वूलमिंगटन बनाम। लोक अभियोजन निदेशक, [1935] ए. सी. 462;

सी. एस. डी स्वामी बनाम राज्य, [1960] 1 एससीआर 461; सूरजपाल सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, [1961] 2 एस. सी. आर. 971; सज्जन सिंह बनाम। पंजाब राज्य, [1964] 4 एस. सी. आर. 630; रिग v. हंट, [1986] 3 डब्ल्यू. एल. आर. 1115 और महाराष्ट्र बनाम। के. के. एस. रामास्वामी, [1978] 1 एस. सी. आर. 274, संदर्भित।

महाराष्ट्र राज्य बनाम। वासुदेव रामचंद्र कैडलवार, [1981]

3 एस. सी. आर. 675, संदर्भित।

9.1 यह बताने के लिए कि सभी सामग्री के संग्रह के बाद, जांच

अधिकारी को अभियुक्त को एक अवसर देना चाहिए और उसे आय के ज्ञात स्रोतों पर संपत्ति की अधिकता का हिसाब देने के लिए कहना चाहिए और फिर यह तय करना चाहिए कि लेखा संतोषजनक है या नहीं, उसे जांच अधिकारी या न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत करना होगा। वह लोक सेवक के आचरण के खिलाफ जांच नहीं कर रहा है या संपत्ति और अभियुक्त की आय के बीच अनुपातहीनता के बारे में विवादित मुद्दों को समाप्त नहीं कर रहा है। वह केवल सभी पक्षों से सामग्री एकत्र करता है और एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसे वह आरोप पत्र के रूप में न्यायालय में दाखिल करता है। जाँच अधिकारी को केवल यह पता लगाने के लिए सामग्री एकत्र करने की आवश्यकता होती है कि क्या कथित अपराध किया गया प्रतीत होता है। जाँच के दौरान, वह अभियुक्त से पूछताछ कर सकता है। वास्तव में, निष्पक्ष जाँच के लिए आवश्यक है कि अभियुक्त को अंधेरे में नहीं रखा जाना चाहिए। यदि वह सहयोग करने को तैयार है तो उसे विश्वास में लिया जाना चाहिए। [ 261 बी-ई]

10.1 आरोप पत्र और कुछ नहीं बल्कि पुलिस की अंतिम रिपोर्ट है।

एस के तहत अधिकारी। 173 ( 2 ) सी. आर. पी. सी. धारा 173 (2) में यह प्रावधान है कि [1991] 3 एस. सी. आर.

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जाँच के पूरा होने पर संज्ञेय अपराध की जाँच करने वाला पुलिस अधिकारी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में होनी चाहिए। एस के तहत रिपोर्ट की वैधानिक आवश्यकता। 173 ( 2 ) अनुपालन किया जाएगा यदि उसमें निर्धारित विभिन्न विवरण रिपोर्ट में शामिल हैं और यह सभी दस्तावेजों और गवाहों के बयानों के साथ है जैसा कि एस द्वारा आवश्यक है। 172 ( 5 ) क्र. पी. सी. जांच अधिकारी की रिपोर्ट में और कुछ नहीं कहा जाना चाहिए। यह भी आवश्यक नहीं है कि अपराध के सभी विवरण बताए जाने चाहिए। अपराध के विवरण को साबित करने की आवश्यकता है

स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत करके मामले की सुनवाई के दौरान बाद के चरण में अभियुक्त का अपराध। [ 261 ई-एच; 262 ए-सी)

सत्य नारायण मुसादी और अन्य। वी. बिहार राज्य, [1980] 3 एससीसी

152 , संदर्भित किया गया।

10.2 तत्काल मामले में, आरोप पत्र में सभी शामिल थे

उनकी पत्नी और दो बेटों के नाम, जो असमान थे उसी अवधि में आय के ज्ञात स्रोत और वह नहीं कर सकता

इस तरह के असमान आर्थिक संसाधनों और संपत्ति के लिए संतोषजनक लेखा। की संपत्तियों और आर्थिक संसाधनों का विवरण

अपीलार्थी को भी स्पष्ट शब्दों में निर्दिष्ट किया गया था। और होने की जरूरत नहीं थी

आरोप पत्र में कहा गया है। यह पूरी तरह से शर्तों के अनुसार था

एस. 173 ( 2 ) , Cr.P.C. और s का खंड (e)। 5 ( 1 ) ( (ड) अधिनियम। { 262 सी-ई]

11. एक न्यायाधीश में ईमानदारी के लिए समाज की मांग सटीक है और

निरपेक्ष। न्यायपीठ के भीतर और बाहर न्यायिक व्यवहार के मानक,

वे आम तौर पर बहुत अधिक होते हैं। एक न्यायाधीश के लिए ऐसे मानकों से भटकना ईमानदारी और निष्पक्षता का अर्थ उस पर रखे गए विश्वास के साथ विश्वासघात करना है। नहीं।

बहाना या कोई कानूनी सापेक्षता इस तरह के विश्वासघात को माफ नहीं कर सकती है। स्टैंड से न्याय का बिंदु रिश्वत का आकार या भ्रष्टाचार का दायरा नहीं हो सकता है

न्यायाधीश के अपमान को मापने के लिए पैमाना। एक भी बेईमान न्यायाधीश नहीं केवल अपना अपमान करता है और अपने पद का अपमान करता है लेकिन खतरे में डालता है संपूर्ण न्यायिक प्रणाली की अखंडता। [ 262 एफ-एच; 263 ए]

न्यायिक घोटाले को हमेशा कहीं अधिक निंदनीय माना गया है।

कार्यपालक या सदस्य को शामिल करने वाले घोटाले से सक्षम विधायिका। में अनियमितता या अनुचितता का थोड़ा सा संकेत कोर्ट बहुत चिंता और घबराहट का कारण है। ( 263 ए-बी)

प्रति शर्मा, जे। :

1. 205 की रोकथाम में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "लोक सेवक"

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई.

भ्रष्टाचार अधिनियम, 1947 निस्संदेह इतना व्यापक है कि प्रत्येक उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों सहित न्यायाधीश। [ 263 डीजे

2.1 अधिनियम की धारा 2 "लोक सेवक" की परिभाषा को अपनाती है।

जैसा कि एस में दिया गया है। 21 , आई. पी. सी. जिसमें "प्रत्येक न्यायाधीश" शामिल है। यदि विधान मंडल का इरादा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को बाहर करने का था और

एस के क्षेत्र से सर्वोच्च न्यायालय। 5 अधिनियम के अनुसार, यह भारतीय दंड संहिता में दिए गए "लोक सेवक" के व्यापक अर्थ को अपनाने के बजाय स्पष्ट शब्दों में ऐसा कह सकता था। [ 266 ई-एफ]

2 : 2 कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। अनुच्छेद 124 के तहत एक कार्यवाही में

संविधान के अनुसार, एक न्यायाधीश को केवल अपने पद से हटाया जा सकता है। उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता और दंडित नहीं किया जा सकता। ऐसे मामले में जहां न्यायाधीश के खिलाफ ऐसी कार्यवाही में सकारात्मक निष्कर्ष दर्ज किया गया है और उस आधार पर उसे उसके पद

से हटा दिया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि वह आपराधिक दायित्व से बच जाएगा। सभ्य समाज में यह नहीं माना जा सकता कि कानून इस तरह के परेशान करने वाले परिणामों की ओर ले जा रहा है। [ 265 जी; 266 ए-बी]

### 2.3 यह मान लेना सुरक्षित नहीं है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम

इसका उद्देश्य अपने अनुप्रयोग में निचली और उच्च न्यायपालिका के बीच कोई भी भेदभाव करना है। ऐसा कोई तर्कसंगत आधार नहीं हो सकता है जिसके आधार पर उच्च न्यायपालिका के किसी सदस्य को अभियोजन से बचने की अनुमति दी जा सके, जबकि समान परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायपालिका के किसी सदस्य पर मुकदमा चलाया जाता है और उसे दोषी ठहराया जाता है। अधिनियम की इस तरह की व्याख्या इसकी संवैधानिक वैधता के खिलाफ होगी और इसलिए इसे प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। [ 265 सी-ई]

### 3.1 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके कार्यालय से हटाने की शक्ति

इसका अस्तित्व है और इसका प्रयोग संविधान के अनुच्छेद 124 के प्रावधानों के अनुसार उचित परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उसके अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी नहीं दी जा सकती है।

उपलब्ध है। [ 266 डी-ई]

### 3 : 2 अधिनियम की धारा 6 (1) (सी) "सक्षम प्राधिकारी" की बात करती है।

लोक सेवक को "अपने कार्यालय से" हटाने के लिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए सक्षम कोई प्राधिकारी है या नहीं, इस प्रश्न के नकारात्मक उत्तर में संविधान के अनुच्छेद 218 के साथ पठित अनुच्छेद 124 खंड (4) और (5) के साथ असंगत होगा। हालाँकि इस प्रक्रिया में एक से अधिक व्यक्ति शामिल हैं, लेकिन यह कहने की अनुमति नहीं है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके कार्यालय से हटाने की शक्ति का प्रयोग करने के उद्देश्य से कोई प्राधिकरण मौजूद नहीं है। [ 264 ए-सी]

इस संबंध में वास्तव में कौन अधिकारी है, यह 206 का मामला है।

[ 1991 ] 3 एस सी आर।

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जो तत्काल मामले में उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या इस तरह के प्राधिकरण का अस्तित्व है और इसका जवाब हां में दिया जाना चाहिए। [ 264 सी-डी]

4.1 यदि राष्ट्रपति को उपयुक्त प्राधिकारी माना जाता है -

संसद को संदर्भित किए बिना मंजूरी प्रदान करें, वह बाध्य होगा

न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरे में डालना जो निस्संदेह एक संविधान की मूल विशेषता। [ 267 डी-ई]

4.2 चूँकि संविधान ने स्वयं इसे पर्याप्त माना है

न्यायाधीशों के खिलाफ गंभीर आरोपों से निपटने का मामला

अनुच्छेद 124 में खंड (4) और (5) के प्रावधानों को शामिल करते हुए, वे उचित और उपयुक्त माना जाना चाहिए और इसका सहारा लिया जाना चाहिए।

अभियोजन के मामले में भी, संसद के अधिनियमन को ध्यान में रखते हुए

एस. 6 अधिनियम की उस भाषा में जो संवैधानिक रूप से आकर्षित करती है

प्रावधान। [ 268 बी-सी]

4.3 यह सच है कि मंजूरी देने में तब तक देरी होगी जब तक कि

उपखंड (5) के तहत अधिनियमित कानून के अनुसार आरोप की जांच की जाती है।

अनुच्छेद 124, लेकिन एक बार जब वह चरण समाप्त हो जाता है और उसके खिलाफ एक निष्कर्ष दर्ज किया जाता है न्यायाधीश, दोनों मामलों को जोड़ने में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए -

हटाने और मंजूरी का अनुदान जो स्पष्ट रूप से आपस में जुड़े हुए हैं,

संसद से मंजूरी प्राप्त करने के लिए। [ 268 ई-एच; 269 ए]

5.1 लोक सेवक को सामान्य रूप से सुरक्षा प्रदान की जाती है

संविधान का अनुच्छेद 311 और अधीनस्थों का हित

न्यायपालिका की देखभाल आगे उच्च न्यायालयों द्वारा की जाती है, और इसके साथ-साथ

पिछली मंजूरी से संबंधित प्रावधान उन्हें अन्याय से बचाते हैं।

मुकदमा चलाया। इसी तरह, उच्च न्यायालय को सुरक्षा उपलब्ध है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश खंड (4) और (5) के प्रावधानों के माध्यम से

संविधान का अनुच्छेद 124। जहाँ तक इस पहलू का संबंध है,

न्यायाधीशों की दो श्रेणियाँ-उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश

एक तरफ और बाकी दूसरी तरफ-द्वारा इलाज नहीं किया गया है कानून अलग तरह से। [ 265 सी-ई]

5.2 न्यायपालिका की स्वतंत्रता का संरक्षण धारा 6 में है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947, जिसके लिए प्रावधान किया गया है -

न्यायाधीश को हटाने के लिए सशक्त प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी,

यह संविधान के अनुच्छेद 124 की ओर जाता है। [ 268 ए-बी]

6.1 न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए

संविधान द्वारा परिकल्पित, यदि भारत के राष्ट्रपति को माना जाता है एक न्यायाधीश के मामले में प्राधिकरण को मंजूरी देना, और 207 के मुख्य न्यायाधीश

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई.

इस मामले में भारत से परामर्श किया जाता है और उनकी सलाह के अनुसार कदम उठाए जाते हैं, और कार्यपालिका इस नियम का सख्ती से पालन करती है, न्यायाधीशों के उत्पीड़न से और अधिक सुरक्षा अनावश्यक और अनुचित है।

आपराधिक अभियोजन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। लेकिन इस न्यायालय द्वारा संविधान और अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर ऐसा बाध्यकारी निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी को केवल संसद द्वारा अभियोजन के लिए एक शर्त के रूप में पेश किया जा सकता है न कि इस न्यायालय द्वारा। यदि न्यायालय कानून को पूरक बनाना शुरू कर देता है जैसा कि अब है, तो यह विधायी क्षेत्र का अतिक्रमण होगा। [ 266 जी-एच; 267 ए-बी; एफ-एच; 268 ए]

7. धारा 5 (1) (ई) किसी नोटिस पर विचार नहीं करती है जिसे जारी किया जाना है।

अभियुक्त। यदि अभियोजन प्राधिकारी एक उपयुक्त जांच करने के बाद, प्रासंगिक दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए और संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ करके, यह राय बनाता है कि अभियुक्त अपने कब्जे में आय से अधिक संपत्ति के संचय के लिए भारी खाते को संतुष्ट नहीं कर सकता है तो धारा आकर्षित होती है। [ 269 बी-डी]

8. तत्काल मामले में, अभिलेख स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि बाद में विधिवत

सभी उचित कदम उठाते हुए यह कहा गया कि अपीलार्थी के कब्जे में उसके अपने नाम और उसकी पत्नी और दो बेटों के नाम पर पाई गई संपत्ति संबंधित अवधि के दौरान उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से असमान थी और जिसके लिए वह "संतोषजनक रूप से लेखा नहीं दे सकता"। [ 269 डी-ई]

पर वर्मा, जे. (असहमति जताते हुए)

1.1 उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश एक संवैधानिक व्यक्ति होता है।

कार्यपालक, भले ही वह एक सार्वजनिक पद रखता हो और उस अर्थ में उसे 'लोक सेवक' की व्यापक परिभाषा में शामिल किया जा सकता है। तथापि, एक पद का धारक जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में अभिव्यक्ति की व्यापक परिभाषा के अनुसार एक लोक सेवक हो सकता है, लेकिन जिसकी अभियोजन के लिए मंजूरी देने की श्रेणी की परिकल्पना एस द्वारा नहीं की गई है। 6 अधिनियम के दायरे से बाहर है, अधिनियम के दायरे में आने का इरादा नहीं है। [ 289 एफ; 286 डी-ई]

1.2 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 6 (1) (सी),

उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू नहीं होता है

और ऐसे संवैधानिक पदाधिकारी अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं। [ 296 बी]

1.3 एस के तहत पिछली मंजूरी। 6 भ्रष्टाचार की रोकथाम

अधिनियम, 1947, एक लोक सेवक के अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है, जिस पर [1991] 3 एस. सी. आर. के दौरान मुकदमा चलाया जाता है।

208

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कार्यालय में उनकी निरंतरता। अधिनियम के दायरे में आने वाले लोक सेवक को अनिवार्य रूप से धाराओं के तीन खंडों में से एक के दायरे में आना चाहिए। 6 ( 1 ) . यदि किसी पद का धारक, भले ही अधिनियम की परिभाषा के अनुसार कोई लोक सेवक उप-धारा (1) के किसी भी खंड (ए), (बी) या (सी) के अंतर्गत नहीं आता है, तो उसे अधिनियम के दायरे से बाहर माना जाना चाहिए क्योंकि यह विशेष अधिनियम उस धारा को शामिल करने के लिए अधिनियमित नहीं किया गया था।

अधिनियम में 'लोक सेवक' की व्यापक परिभाषा के बावजूद लोक सेवकों का अपमान।  
[ 286 ए-बी]

1.4 धारा 6 (1) (सी) हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की बात करती है,

जो स्पष्ट रूप से हटाने के लिए प्राधिकरण की मूल क्षमता को इंगित करता है, न कि केवल इसके प्रक्रियात्मक या औपचारिक भाग को। प्राधिकारी को स्वयं हटाने या हटाने के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए सक्षम होना चाहिए, न कि वह जो केवल किसी अन्य प्राधिकारी के निर्णय का पालन करता है या उसे लागू करता है। यह विचार करता है कि हटाने वाले प्राधिकारी के पास यह निर्णय लेने के उद्देश्य से उसके समक्ष रखी गई सामग्री पर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए कि क्या लोक सेवक, जिसके खिलाफ मंजूरी मांगी गई है, प्रथम दृष्टया अपने पद के दुरुपयोग का दोषी रहा है ताकि पद के धारक द्वारा उसे पद से हटाकर पद और दुरुपयोग के बीच अंतर्संबंध को समाप्त करने का अवसर मिले। [ 291 ए-सी]

आर. एस. नायक बनाम ए. आर. अंतुले, [1984] 2 एस. सी. सी. 183, संदर्भित।

1.5 एस द्वारा परिकल्पित सक्षम मंजूरी प्राधिकरण। 6 ( 1 ) ( ग) है

पदानुक्रम में एक ऊर्ध्वाधर श्रेष्ठ जिसमें सुपरिटेन की कुछ शक्ति होती है

लोक सेवक के कामकाज पर ध्यान देना। जहां किसी ऊर्ध्वाधर पदानुक्रम के अभाव में ऐसा कोई संबंध मौजूद नहीं है और सार्वजनिक पद का धारक एक संवैधानिक पदाधिकारी है जो किसी भी वरिष्ठ के अधीक्षण की शक्ति के अधीन नहीं है। 6 उसमें संलग्न योजना के आधार पर कोई आवेदन नहीं हो सकता है। [ 291 सी-डी]

1.6 एस का निर्माण। 6 ( 1 ) ( ग) राष्ट्रपति के रूप में व्यवहार करने वाले अधिनियम का





यह योजना कि एक न्यायाधीश के दुर्व्यवहार की जांच और सबूत से निपटने के लिए एक अलग संसदीय कानून पर स्पष्ट रूप से संवैधानिक कार्य की इस श्रेणी के लिए एक विशेष तंत्र प्रदान करके विचार किया गया था

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1991] 3 एस. सी. आर.

राज्य सामान्य रूप से लोक सेवकों के लिए उपलब्ध और लागू सामान्य कानून के बावजूद, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 शामिल था। [ 294 जी-एच; 295 ए]

2.6 संविधान के अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 218 के खंड (4) और (5) के रूप में विशेष प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, और

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए संवैधानिक योजना में प्रदान किए गए अनुच्छेद 124 (5) के तहत संसद द्वारा अधिनियमित, यह नहीं कहा जा सकता है कि वे केवल उनके लिए अधिनियमित इन विशेष प्रावधानों के अलावा सामान्य दृष्टिकोण द्वारा शासित होते हैं। इन विशेष प्रावधानों की आवश्यकता लागू होने वाले सामान्य प्रावधानों के उनके लिए अप्रयोज्य होने की दिशा में एक स्पष्ट संकेत है।

अन्य सार्वजनिक पदों पर आसीन लोक सेवकों के लिए, न कि संवैधानिक कार्यकर्ताओं के रूप में। [ 295 ए-बी]

2.7 . यह विचार कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के दायरे से बाहर हैं, उपयुक्त है।

संवैधानिक योजना के साथ और इसके अनुरूप भी है

वरिष्ठ न्यायाधीशों से संबंधित संपूर्ण मौजूदा कानून की कई बारीकियां

जबकि इसके विपरीत कई मौकों पर इसके साथ फाउल होता है कई कमियां हैं जिन्हें न्यायिक अभ्यास से भरा नहीं जा सकता है। [ 303 एफ-जी]

2.8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947, द्वारा संशोधित

1964 संशोधन, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर लागू नहीं होता है और

सुप्रीम कोर्ट। [ 304 ए]

46 एम. जुर। 2 डी। \$ 84 , संदर्भित किया गया।

3.1 आपराधिक दुराचार को लागू करने में व्यावहारिक कठिनाई है,

एस की उप-धारा (1) के खंड (ई) में परिभाषित। 5 किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को अधिनियम का। [ 296 सी]

3.2 एस के खंड (ई) में शब्द। 5 ( 1 ) अधिनियम का दिया जाना चाहिए

कुछ अर्थ जो अभियोजन पक्ष पर बोझ डालेंगे,

चाहे कितना भी हल्का क्यों न हो, मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए एस के तहत सक्षम प्राधिकारी। 6 अधिनियम और यह किया जा सकता है

केवल तभी जब इसे उस योजना के हिस्से के रूप में पढ़ा जाए जिसके तहत लोक सेवक

असंतुलन और संतोषजनक रूप से लेखा करने में उनकी असमर्थता हो सकती है अनुमान लगाया। [ 297 ए-बी]

3.3 जबकि एस के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी के अनुसार। 6 अधिनियम का,

सक्षम प्राधिकारी को लोक सेवक के बारे में खुद को संतुष्ट करना होगा

असंगत के कब्जे के लिए संतोषजनक रूप से लेखा देने में असमर्थता संपत्ति।  
मंजूरी देने से पहले सक्षम प्राधिकारी को 211 आवेदन करने होते हैं।

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई.

उसका मन और उसके सामने रखी गई सामग्री के आधार पर लोक सेवक के अभियोजन के लिए प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व के बारे में संतुष्ट हो। एक वस्तुनिष्ठ राय बनाने के लिए, सक्षम लेखक के पास लोक सेवक का संस्करण होना चाहिए जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह संतोषजनक लेखा है या नहीं। [ 296 ई-एफ]

3.4 आम तौर पर लोक सेवकों पर लागू होने वाले नियम

उनके आचरण के लिए उन्हें अपनी परिसंपत्तियों की आवधिक जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है जो उनके सेवा रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। ऐसे लोक सेवकों के मामले में जब भी एस के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी जाती है। 6 , सक्षम प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर

पहुंचने के लिए लोक सेवक के सेवा रिकॉर्ड सहित उपलब्ध सामग्री के आधार पर अपेक्षित राय बना सकता है कि क्या धाराओं के खंड (ई) के तहत अपराध है। 5 ( 1 ) आय से अधिक संपत्ति का कब्जा जो लोक सेवक नहीं कर सकता है

प्रथम दृष्टया संतोषजनक रूप से लेखा तैयार किया जाता है। [ 296 एफ-जी, 297 सी-डी]

3.5 उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में, प्रस्तुत करने के किसी भी प्रावधान के तहत कोई आवश्यकता नहीं है।

उनकी परिसंपत्तियों का विवरण ताकि रेफ्रे रेंस के साथ एक रिकॉर्ड प्रदान किया जा सके जिसके लिए ऐसी राय बनाई जा सकती है और संबंधित न्यायाधीश से जानकारी प्राप्त करने में सक्षम कानूनी प्राधिकरण के साथ कोई ऊर्ध्वाधर उच्चतर नहीं है। यह भी इस दिशा में एक संकेत है कि अधिनियम के 1964 के संशोधन के बाद भी विधानमंडल का इरादा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अधिनियम के दायरे में शामिल करने का नहीं था।

( 297 डी-एफ]

4.1 यदि यह अधिनियम उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होता है, तो यह स्पष्ट है कि यह भारत के मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और मुख्य न्यायाधीश पर भी लागू होना चाहिए।

चुनाव आयुक्त। इस तरह की घटना में असंगत परिणाम सामने आएंगे। [ 297 एफ-जी]

4.2 यदि अपराध की जाँच शुरू करने के लिए भी भारत के मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी आवश्यक है, और राष्ट्रपति ने एस के तहत मंजूरी देते समय हस्तक्षेप किया है। 6 ( 1 ) ( ग) यह भी माना जाता है कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर कार्य करता है और यदि अधिनियम में ऐसे किसी प्रावधान के अभाव में ऐसा करने की अनुमति है, तो समस्या उत्पन्न होगी जहां भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ ऐसी कार्रवाई पर विचार किया जाता है।

स्वयं। [ 297 जी-एच; 298 ए]

4.3 कोई भी प्रावधान जो [1991] 3 एस. सी. आर. के मुख्य न्यायाधीश पर लागू नहीं हो सकता है।

भारत, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों या उस मामले के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी आवेदन नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत का मुख्य न्यायाधीश उनमें से किसी से ऊर्ध्वाधर नहीं है, ऐसा कोई ऊर्ध्वाधर पदानुक्रम नहीं है और भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी अधीक्षण की कोई शक्ति नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी बहुत कम। [ 298 ए-बी]

#### 4.4 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के मामले में और

मुख्य चुनाव आयुक्त, स्थिति और अधिक तीखी होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश उनसे संबंधित प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं और उस स्थिति में उस भूमिका को भरने के लिए कोई और नहीं है। संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि उनकी स्थिति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगी, लेकिन उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से उच्च पद पर रखने का इरादा नहीं हो सकता था। यदि इस अधिनियम को इन संवैधानिक अधिकारियों पर लागू करने का इरादा था, तो इसे ऐसे अंतराल को छोड़कर अधिनियमित नहीं किया जा सकता था जो होने में असमर्थ हैं। इस उद्देश्य के लिए एक व्यापक योजना प्रस्तुत करने के लिए जोड़ा गया। [ 298 सी-ई]

#### 5.1 एस के तहत मंजूरी की आवश्यकता। 6 अभियोजन के लिए अधिनियम

सार्वजनिक पद का धारक यह तय करने के लिए अधिनियम की परिधि और दायरे को इंगित करता है कि क्या सार्वजनिक पद का धारक अधिनियम के दायरे में आता है। एस के तहत अभियोजन के लिए कोई मंजूरी नहीं। 6 लोक सेवक के पद धारण करना बंद करने के बाद इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस पद को धारण करना बंद करने के बाद सार्वजनिक पद का प्रत्येक धारक अधिनियम के दायरे में है, भले ही कार्यालय में कार्यकाल के दौरान, केवल वे लोक सेवक इसके दायरे में हों जिनके मामले में एस के तहत मंजूरी दी गई हो। 6 प्राप्त किया जाना चाहिए। [ 298 एफ-एच; 299 ए]

#### 5.2 अधिनियमन का दायरा इन आधार पर निर्धारित किया जाना है -

लोक सेवक द्वारा धारित लोक पद, जिसके बारे में आरोप लगाया गया है कि अधिनियम के तहत अपराधिक दुराचार का अपराध करने के लिए कार्यकाल के दौरान किस पद का दुरुपयोग किया गया है और यह उस पद पर बने रहने या इसे धारण करना बंद करने का तथ्य नहीं है जो अधिनियम की सीमा तय करता है। यदि कार्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान किसी सार्वजनिक पद के धारक को एस के तहत मंजूरी के बिना अलग नहीं किया जा सकता है। 6, तब, पद धारण करना बंद करने के बाद उसके अभियोजन के लिए कोई मंजूरी आवश्यक नहीं हो सकती है, लेकिन उसका अभियोजन किया जाता है क्योंकि पद पर रहते हुए उस पर एस के तहत पिछली मंजूरी के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है। 6. इसके विपरीत, यदि किसी सार्वजनिक पद के धारक पर उस पद

पर बने रहने के दौरान एस की अप्रयोज्यता के कारण इस अधिनियम के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। 6 और, इसलिए, एस के तहत अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी की गैर-व्यवहार्यता। 6, फिर पद धारण करना बंद करने पर, उसे अधिनियम के दायरे में नहीं लाया जाता है। [ 299 ए-सी] 212

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई.

5.3 यह अधिनियम के प्रावधानों को समझने के उद्देश्य से है।

और उसके दायरे और दायरे का निर्धारण और यह तय करने के लिए कि क्या किसी सार्वजनिक पद का धारक इस अधिनियम के दायरे में आता है कि अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी की व्यवहार्यता और एस की प्रयोज्यता। 6 अधिनियम महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें वह कुंजी है जो अधिनियम के वास्तविक परिदृश्य को खोलती है। [ 299 डी-ई]

5.4 एक वरिष्ठ द्वारा अभियोजन के लिए मंजूरी की अवधारणा इस प्रकार है

अधिनियम के कपड़े में अटूट रूप से बुना गया है कि पैटर्न इसके बिना अधूरा है। स्पष्ट विधायी आशय यह है कि अधिनियम केवल उन लोगों पर लागू होता है जिनके मामले में इस तरह की मंजूरी पर विचार किया जाता है और जिनके लिए मंजूरी का प्रावधान पूरी तरह से लागू नहीं हो सकता है, वे इसके दायरे से बाहर हैं। मंजूरी के लिए प्रावधान अधिनियम के मेहराब में प्रमुख पत्थर की तरह है। मंजूरी की कुंजी को हटा दें और मेहराब टूट जाए। [ 299 ई-जी]

आर. एस. नायक बनाम ए. आर. अंतुले, [1984] 2 एस. सी. सी. 183, प्रतिष्ठित।

6.1 संविधान में उच्च न्यायपालिका के साथ अलग व्यवहार किया गया था

नियुक्ति करने के लिए तंत्र को निर्धारित करने में दी गई बड़ी देखभाल और ध्यान का संकेत। यह उम्मीद की गई थी कि उस स्तर पर सच्चाई के मार्ग से कोई भी विचलन एक दुर्लभ घटना होगी और असाधारण स्थिति के लिए अनुच्छेद 124 के खंड (4) के अनुसार हटाने का प्रावधान किया गया था, उस पाठ्यक्रम को अपनाने में कठिनाई स्वयं उस दुर्लभता का संकेत है जिसके साथ इसे लागू करने की उम्मीद की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उस स्तर पर एक दुर्लभ विसंगति के लिए, जब तक कि न्यायाधीश ने ऐसी स्थिति का सामना करने पर इस्तीफा नहीं दिया, अनुच्छेद 124 (4) के अनुसार पद से हटाने की परिकल्पना एकमात्र कानूनी मंजूरी के रूप में की गई थी।

यदि संविधान निर्माताओं की यह अपेक्षा थी और स्वतंत्र भारत में न्यायपालिका के उच्च क्षेत्रों में नैतिक ताने-बाने की उनकी दृष्टि थी, तो उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के दायरे में लाने में चूक या अकेले उनके लिए इसी तरह के कानून के अभाव में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह स्थिति संधम समिति के विचार-विमर्श के दौरान भी जारी रही, जिसने 1964 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि उसने न्यायपालिका को अपने विचार-विमर्श के दायरे से बाहर माना है। स्पष्ट रूप से, यह उम्मीद की गई थी कि उच्च न्यायपालिका, जिसका शब्द संविधान सहित सभी कानूनों की व्याख्या में अंतिम होगा, में ऐसे लोग शामिल होंगे जो इस मामले में अग्रणी होंगे।

आत्म-त्याग की भावना अधिकारों की तुलना में उनके दायित्वों से अधिक संबंधित थी, ताकि किसी और के लिए उन पर निर्णय लेने का कोई अवसर न हो। [ 305 एच;306 ए-डी]

- 6.2 तथ्य यह है कि संसद ने 214 के लिए कोई अन्य कानून नहीं बनाया

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1991] 3 एस. सी. आर.

एक वरिष्ठ न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच और उसके मुकदमे और उस अपराध के लिए सजा और बाकी सामग्री अनुच्छेद 124 (4) के तहत किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान करने के लिए केवल न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 को अधिनियमित करना इस दिशा में एक स्पष्ट संकेत है कि संसद ने अभी तक किसी वरिष्ठ न्यायाधीश के भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमे और सजा के लिए ऐसा कोई कानून बनाने के लिए बाध्य नहीं माना है, सिवाय इसके कि उसे निर्धारित तरीके से पद से हटा दिया जाए। न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के प्रावधान एक वरिष्ठ न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच और सबूत के लिए प्रक्रिया प्रदान करते हैं और यदि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 उन पर लागू होता है, तो इन दोनों अधिनियमों के तहत दो अलग-अलग प्रक्रियाएं होंगी जो एक ही आरोप में निवेश का प्रावधान करती हैं। इस विसंगति और विसंगति को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 1964 के संशोधन के बाद न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 को लागू करते समय संसद के एक सचेत कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। [ 301 डी-एफ }

7.1 संवैधानिक पदाधिकारी अर्थात् उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

न्यायालयों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और मुख्य चुनाव आयुक्त का इरादा कभी भी इस अधिनियम के दायरे में आने का नहीं था जैसा कि शुरू में 1947 में अधिनियमित किया गया था, जब भारत सरकार अधिनियम, 1935 में संविधान के अनुच्छेद 124 (4) और (5) के समान प्रावधान मौजूद थे, और न ही 1964 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन द्वारा ऐसा कोई प्रयास किया गया था और यही स्थिति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में भी बनी हुई है। [ 300 ए-बी]

7.2 यदि अब ऐसी स्थिति के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता महसूस की जाती है, तो उपचार पूर्व उद्देश्य के लिए उपयुक्त संसदीय कानून में निहित है

ऐसी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एक उचित और पर्याप्त तंत्र प्रदान करते हुए संभावित कार्यकारी प्रभाव से मुक्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता की सेवा करना। जांच के बाद उनके मुकदमे और सजा के लिए। उपाय यह नहीं है कि मौजूदा कानून का विस्तार किया जाए और इसे व्यवहार्य बनाया जाए

इसमें कुछ दिशानिर्देशों को पढ़ना जिनके लिए इसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि अधिनियम उन पर लागू होने का इरादा नहीं था। [ 300 बी-सी]

7.3 मौजूदा कानून की प्रयोज्यता की कसौटी प्रस्तावित दिशानिर्देशों की कानूनी मंजूरी और न्यायसंगतता होगी, जिनके बिना यह लागू होता है। ऐसे व्यक्तियों के मामले में काम नहीं हो सकता। वास्तव में, मौजूदा कानून में प्रस्तावित दिशानिर्देशों को निहितार्थ से पढ़ने की आवश्यकता एक स्पष्ट संकेत है कि जो कानून मौजूद है वह उन पर लागू नहीं होता है। सुझाए गए दिशा-निर्देशों की सहायता से कानून को लागू करना न्यायिक शिल्प कौशल के क्षेत्र में नहीं है, बल्कि एक वर्जित क्षेत्र में विधायी शक्ति का नग्न दुरुपयोग है। [ 300 सी-डी] 215

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई.

8.1 अंतर्निहित रूप से पालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों को निर्धारित करना, यदि वे नहीं पाते हैं

मौजूदा अधिनियम में स्थान देना और उस आधार पर वरिष्ठ न्यायाधीशों को मौजूदा कानून के दायरे में लाना, मौजूदा कानून के दायरे से बाहर एक नया कानून बनाने के बराबर होगा और न कि केवल कमियों को पूरा करके इसे अपने अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यवहार्य बनाने के लिए इसका अर्थ लगाया जाएगा। [ 273 ई-एफ]

एस. पी. संपत कुमार बनाम भारत संघ, [1987] 1 एस. सी. सी. 124,

प्रतिष्ठित।

8.2 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे किसी कानून के मामले में

इस समय वरिष्ठ न्यायाधीशों को भी आवश्यक माना जाता है, संसद उपयुक्त कानून बनाकर अपना कार्य कर सकती है, क्योंकि यह कानून का एक वर्जिन क्षेत्र है। [ 274 बी]

8.3 न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का संकेत देने के लिए कोई सामग्री नहीं है

जब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लागू किया गया तो यह एक ऐसी शरारत थी जिसे ठीक किया जाना था। इस कारण से, इस तरह का कानून होने की अब व्यक्त की गई वांछनीयता मौजूदा कानून के निर्माण में सहायता नहीं हो सकती है ताकि इसका दायरा बढ़ाया जा सके और इन संवैधानिक अधिकारियों को इसके भीतर लाया जा सके। [ 273 बी-सी]

8.4 न्यायिक सक्रियता कमियों को पूरा कर सकती है और कमियों को पूरा कर सकती है।

एक पहले से मौजूद संरचना में कुछ मायनों में कमी पाई गई, लेकिन इसे एक नई इमारत का निर्माण करना बंद करना चाहिए जहां कोई नहीं है। [ 273 डी]

8.5 यदि यह माना जाता है कि स्थिति बदल गई है तो आवश्यकता है

उच्चतम स्तर पर न्यायाधीशों के आचरण की भी जांच, और यह कि यह संसद को तय करना है, तो इसका उपाय न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों का प्रावधान करने वाले उस उद्देश्य के लिए उपयुक्त कानून बनाने में निहित है क्योंकि मौजूदा कानून उस स्थिति के लिए प्रावधान नहीं करता है। [ 306 डी-ई]

8.6 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को लाने का कोई भी प्रयास और

उच्चतम न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के दायरे में, अधिनियम के एक प्रतीत होने वाले निर्माणात्मक अभ्यास द्वारा, एक गोल छेद में एक वर्गाकार खूटी को फिट करने के लिए एक अभ्यास प्रतीत होता है, जबकि दोनों का कभी भी मिलान करने का इरादा नहीं था। [ 306 ई-एफ]

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील

1979 का सं. 400।

मद्रास उच्च न्यायालय के 27.4.79 दिनांकित निर्णय और आदेश से

आपराधिक विविध में न्यायालय। 1978 का पी. सं. 265।

[ 1991 ] 3 एस सी आर।

216

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कपिल सिब्बल, बी. आर. एल. अयंगर, के. वी. मोहन, एस. आर. सेतिया, के. आर.

अपीलार्थी के लिए नांबियार और ए. के. निगम।

ए. डी. गिरि, सॉलिसिटर जनरल, के. टी. एस. तुलसी, अतिरिक्त सॉलिसिटर

प्रतिवादी के लिए जनरल, ए. एम. खानविलकर और पी. परमेस्वरन।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

रे, जे. मुझे दोनों मसौदों को समझने का लाभ मिला है।

मेरे विद्वान भाइयों शेड्टी और वर्मा, जे. जे. द्वारा तैयार किए गए निर्णय। मैं अपने विद्वान भाई जे. शेड्टी द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से सहमत हूँ, फिर भी इस मामले में शामिल प्रश्नों के बड़े महत्व को देखते हुए, मैं इस पर विचार करना और अपने विचार व्यक्त करना उचित और उचित समझता हूँ।

इस मामले में निर्णय के लिए तीन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहले

चाहे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 2 के अर्थ के भीतर एक लोक सेवक है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 2 एक लोक सेवक की व्याख्या भारतीय दंड संहिता की धारा 21 अर्थात् 1860 के अधिनियम 45 में परिभाषित लोक सेवक के रूप में करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में कहा गया है कि एक लोक सेवक इसमें उल्लिखित किसी भी विवरण के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति को दर्शाता है:

" तीसरा-द्वारा सशक्त किसी भी व्यक्ति सहित प्रत्येक न्यायाधीश

निर्वहन के लिए कानून, चाहे वह स्वयं या किसी के सदस्य के रूप में हो

व्यक्तियों का निकाय कोई भी न्यायिक कार्य "।

इस प्रकार, लोक सेवक की परिभाषा इतनी व्यापक है कि

इनमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ-साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 77 न्यायाधीशों को किसी भी शक्ति का प्रयोग करते समय न्यायिक रूप से कार्य करते समय न्यायाधीशों द्वारा किए गए किसी भी कार्य के संबंध में प्रतिरक्षा प्रदान करती है, जो उसे कानून द्वारा दी गई है या जिसे वह सद्भावना से मानता है।

अगला सवाल यह है कि क्या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर आपराधिक गलत नलिका का अपराध करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जैसा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 की उप-धारा 1 के खंड (ई) में संदर्भित है। धारा 5 (1) के खंड (ई) के प्रावधान इस प्रकार हैं:

217

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [आरएवाई, जे।]

" यदि वह या उसकी ओर से कोई व्यक्ति कब्जे में है या है,  
अपने पद की अवधि के दौरान किसी भी समय, कब्जे में था,  
जिसके लिए लोक सेवक संतोषजनक रूप से जवाबदेह नहीं हो सकता है,  
उसके लिए आनुपातिक आर्थिक संसाधनों या संपत्ति का  
आय के ज्ञात स्रोत "।

इसलिए, यह स्पष्ट है कि एक न्यायाधीश आपराधिक अपराध करने के लिए उत्तरदायी होगा। उप-धारा (1) के खंड (ई) के अर्थ के भीतर दुराचार

या आय के ज्ञात स्रोतों से असमान संपत्ति जिसके लिए लोक सेवक (या लोक सेवक के रूप में एक न्यायाधीश) संतुष्ट नहीं कर सकता है

रिली खाता। धारा 6 (1) (सी) विशेष रूप से आदेश देती है कि कोई भी अदालत

इस अधिनियम की धारा 5 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेना, जो कथित रूप से एक लोक सेवक यानी न्यायाधीश द्वारा किया गया है।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित उच्च न्यायालय वर्तमान मामला, किसी अन्य व्यक्ति के मामले में खंड (ग) के तहत पूर्व मंजूरी के अलावा, उसे हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी का है।

अपने कार्यालय से। अतः धारा 5 (1) (ई) के तहत आने वाले आपराधिक कदाचार के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित किसी न्यायाधीश को अपने कार्यालय से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी है -

अनिवार्य है।

उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश

न्यायालय एक संवैधानिक पदाधिकारी है जिसे क्रमशः अनुच्छेद 124 और संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 124 के उप-अनुच्छेद 2 में आगे यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के साथ परामर्श करने के बाद अपने हाथ और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाएगी जिन्हें राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे और जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक पद पर रहेगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में, भारत के मुख्य न्यायाधीश को हमेशा दोषी ठहराया जाएगा। अनुच्छेद 217 में प्रावधान है कि उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में परामर्श के बाद अपने हाथ और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाएगी। उक्त अनुच्छेद 124 के उप-अनुच्छेद 4 में आगे यह आदेश दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश

संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा समर्थित और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई के बहुमत से पारित राष्ट्रपति के आदेश के अलावा उन्हें अपने पद से हटा दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1991] 3 एस. सी. आर.

साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर इस तरह के निष्कासन के लिए उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उप-अनुच्छेद (5) में यह भी प्रावधान है कि संसद कानून द्वारा खंड (4) के तहत किसी न्यायाधीश के संबोधन को प्रस्तुत करने और दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच और प्रमाण के लिए प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है। अनुच्छेद 218 में कहा गया है कि अनुच्छेद 124 के खंड (4) और (5) के प्रावधान उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होंगे।

अनुच्छेद 124 के उप-अनुच्छेद 4 के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा समर्थित और उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा एक संबोधन के बाद पारित किया गया है, जिसे साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर इस तरह के निष्कासन के लिए उसी सत्र में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया है। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रपति स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को तब तक नहीं हटा सकता जब तक कि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा और उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा एक संबोधन पारित नहीं किया जाता है और साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर न्यायाधीश को हटाने के लिए उसे प्रस्तुत नहीं किया जाता है। इसलिए, इस शक्ति का भंडार केवल राष्ट्रपति में नहीं है, बल्कि यह है

संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा समर्थित और के बहुमत द्वारा समर्थित एक संबोधन के बाद प्रयोग किया गया

उस सदन के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों को प्रस्तुत किया जाता है

राष्ट्रपति। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा इस तरह के संबोधन के बिना, राष्ट्रपति को संविधान के तहत अधिकार नहीं है -

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उनके कार्यालय से हटाने का आदेश। लेख

218 यह निर्धारित करता है कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है

खंड (4) के तहत प्रदान की गई तरीके से राष्ट्रपति द्वारा पद और

( 5 ) अनुच्छेद 124। अतः उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानों को देखते हुए साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के लिए एक न्यायाधीश को हटाने के लिए, यह है यह अनिवार्य है कि संसद का प्रत्येक सदन एक संबोधन देगा - इसके बाद राष्ट्रपति को कुल बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। उस सदन की सदस्यता और कम से कम दो के बहुमत से उस सदन के एक तिहाई सदस्य उपस्थित होते हैं और मतदान करते हैं। सिवाय इसके कि इसके लिए उसी सत्र में राष्ट्रपति को संबोधन प्रस्तुत किया जाता है हटाने के लिए, राष्ट्रपति को संविधान के तहत अधिकार नहीं है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का आदेश दें साबित के आधार पर भारत या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का दुर्व्यवहार या अक्षमता। बेशक, राष्ट्रपति की शक्ति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना 219 होना चाहिए।

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [राय। जे.]

राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 124 के खंड 4 में स्पष्ट रूप से निर्धारित तरीके से प्रयोग किया गया। भारत संघ के मामले में v. संकलचंद, आकाशवाणी

1977 ( एससी ) 2328 यह संविधान के बहुमत द्वारा मनाया गया है

पीठ ने कहा कि अनुच्छेद का अर्थ लगाने के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने या उसकी रक्षा करने के लिए कोई आवश्यकता या औचित्य नहीं है 222 ( 1 ) इसका अर्थ यह है कि एक न्यायाधीश को उसकी सहमति के बिना एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

" उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की शक्ति द्वारा प्रदान की जाती है

संविधान जनहित में है न कि इस उद्देश्य के लिए

जो इसकी रेखा का पालन नहीं करता है या कौन, किसी कारण से या अन्य, अपनी कृपा से गिर गया है। कार्यपालिका के पास नहीं है

हालांकि हम इस तरह से दिखाने में कठिनाइयों को देखते हैं कि एक ट्रांस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए एक दिए गए मामले में बनाया जाता है

बाहरी कारण, शक्ति का प्रयोग अनुमोदन कर सकता है कानूनी दुर्भावना से दूषित होने के रूप में खारिज किया जाए

विश्वास करते हैं। असाधारण शक्ति जो संविधान के पास है

जिस तरीके से हारने या नष्ट करने के लिए गणना की जाती है एक स्ट्रोक विभिन्न प्रावधानों का उद्देश्य और उद्देश्य

न्यायपालिका को इससे अलग रखने के लिए इस तरह की देखभाल के साथ कल्पना की गई

कार्यपालिका का प्रभाव और दबाव। की शक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दंडित करना, यदि कोई इसका वर्णन कर सकता है, तो

केवल कला में पाया जा सकता है। 218 कला के साथ पढ़ें। 124 ( 4 ) और (5)

संविधान, जिसके तहत उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कर सकता है

संसद के प्रत्येक सदन द्वारा एक संबोधन के बाद पारित किया गया, उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा चित्त्रित

और कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से

उस सदन के वर्तमान और मतदान को प्रस्तुत किया गया है

राष्ट्रपति ने उसी सत्र में इस तरह के निष्कासन के लिए

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण करने के लिए मंत्रिपरिषद सार्वजनिक हित पर असर नहीं करने वाले लेकिन उत्पन्न होने वाले कारण

कार्यपालिका की सनक, सनक या कल्पना या झुकने की उसकी इच्छा

अपने सोचने के तरीके के लिए एक न्यायाधीश, की कोई संभावना नहीं है

न्यायपालिका की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप यदि

न्यायाधीश का स्थानांतरण उनकी सहमति के बिना किया जाता है।

कॉन [1991] 3 एस. सी. आर. से न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में भी यही दृष्टिकोण।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ई कार्यकारी की टिप्पणियों द्वारा लिखा गया है

एस. पी. गुप्ता और अन्य के मामले में सात न्यायाधीशों की पीठ पर। भारत और ओआरएस का एन. टी. , ए. आई. आर. 1982 (एस. सी.) 149.

" न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा एक महान है

अवधारणा जो संवैधानिक योजना को प्रेरित करती है और

उस नींव को स्थापित करें जिस पर हमारी इमारत टिकी हुई है

लोकतांत्रिक राजनीति। अगर एक सिद्धांत है जो चलता है संविधान के पूरे ताने-बाने के माध्यम से, यह है

कानून के शासन के सिद्धांत और संविधान के तहत, यह है

न्यायपालिका जिसे रखने का कार्य सौंपा गया है

कानून की सीमाओं के भीतर राज्य का प्रत्येक अंग और

जिससे कानून के शासन को सार्थक और प्रभावी बनाया जा सके। यह. इस कार्य में न्यायपालिका की सहायता करना है कि न्यायपालिका की शक्ति

न्यायपालिका को समीक्षा प्रदान की गई है और इसके द्वारा

इस शक्ति का प्रयोग करना जो सबसे अधिक है

कानून के शस्त्रागार में शक्तिशाली हथियार, कि न्यायपालिका

अपने संविधान के उल्लंघन से नागरिक की रक्षा करना चाहता है राष्ट्रीय या कानूनी अधिकार या सत्ता का दुरुपयोग

कार्यकारी ज्यादातियों के खिलाफ एक गढ़ के रूप में जेन और राज्य और कार्यपालिका द्वारा दुरुपयोग या दुरुपयोग या शक्ति और वहाँ यह

यह बिल्कुल आवश्यक है कि न्यायपालिका इससे मुक्त हो और यह सुरक्षित किया गया है कार्यकारी दबाव या प्रभाव

संविधान निर्माताओं द्वारा विस्तृत प्रावधान करके संविधान में जिसका विस्तृत संदर्भ दिया गया है

संकलचंद सेठ के मामले (ए. आई. आर.) में दिए गए निर्णय

1977 एससी 2326) (ऊपर)। लेकिन यह याद रखना आवश्यक है

स्वयं न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा

केवल कार्यकारी अध्यक्ष से स्वतंत्रता तक ही सीमित नहीं है

निश्चित या प्रभाव लेकिन यह एक बहुत व्यापक अवधारणा है जो लेता है कई अन्य दबावों से अपनी व्यापक स्वतंत्रता के भीतर

और पूर्वाग्रह। इसके कई आयाम हैं, जिनके नाम निम्न हैं।

न्यायाधीश जिन वर्ग से संबंधित हैं। अगर हम फिर से उद्धृत कर सकते हैं न्यायमूर्ति कृष्ण लायर के वाक्पटु शब्द:

" न्यायपालिका की स्वतंत्रता छल नहीं है;

न ही यह सरकार के हर प्रस्ताव का विरोध करता है। यह. विपक्ष के उपाय के लिए बनाई गई है और न ही

न तो न्यायपालिका

सरकार की खुशी।

221

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. 1. [रे, जे।]

टाइक्रॉन, सांप्रदायिक, संकीर्णतावादी,

उन्मादी, चरमपंथी और कट्टरपंथी प्रतिक्रियावादी झूठ बोल रहा है

और अवचेतन रूप से न्यायिक सलाह को आकार दे रहे हैं  
न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरा जब वे

पैरामाउंट चर्मपत्र के भाग III और IV के साथ भिन्नता "।

न्यायाधीशों को कठोर और कठोर होना चाहिए।

सत्ता, चाहे वह आर्थिक हो या राजनीतिक, और वे

कानून के शासन के मूल सिद्धांत को बनाए रखना चाहिए जो कहता है

" चाहे आप कभी भी इतने ऊँचे हों, कानून आपके ऊपर है। यह वह है

न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत जो इसके लिए महत्वपूर्ण है

● वास्तविक सहभागी लोकतंत्र की स्थापना, मुख्य रूप से -

एक गतिशील अवधारणा और विशिष्टता के रूप में कानून के शासन का  
अधिकार

समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक न्याय  
बहुत से लोग। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का यही सिद्धांत है।

जिनका हमें प्रासंगिक व्याख्या करते समय ध्यान रखना चाहिए।

संविधान के प्रावधान।

तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस में विचार के लिए आता है।

मामला वह है जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को अपने पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी है ताकि उस प्राधिकारी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 6 द्वारा निर्धारित प्रावधानों के तहत न्यायाधीश के अभियोजन के लिए मंजूरी देने में सक्षम बनाया जा सके। धारा 6 को निम्नलिखित प्रभाव के लिए नकारात्मक शब्दों में जोड़ा गया है:

" कोई भी न्यायालय दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

धारा 161 या धारा 164 या धारा 165 के तहत  
भारतीय दंड संहिता (1860 का 45), या उप-धारा (2) के तहत या

इस अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3 ए), कथित रूप से

ओउस मंजूरी,  
( ग ) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, प्राधिकरण का

उसे उसके कार्यालय से हटाने के लिए तम्बू ।

किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ अभियोजन शुरू करने के लिए

उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी अनिवार्य रूप से आवश्यक है । इसलिए सवाल यह उठता है कि मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है । उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के प्रावधानों के तहत या अनुच्छेद 217 के प्रावधानों के तहत की जाती है ।

222

सक्रिय रूप से । उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्य में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों के साथ परामर्श करने के बाद अपने हाथ और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाएगी जो राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझें और 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर रहेंगे । इसी प्रकार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की स्थिति में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करने के बाद अपने हाथ और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाएगी और वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अतिरिक्त न्यायाधीश के मामले को छोड़कर पद धारण करेगा । अतः यह स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश एक संवैधानिक पदाधिकारी है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पहले उद्धृत निर्णयों में देखा गया है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने और न्यायाधीश को न्यायाधीश के रूप में अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने और कानून के शासन को बनाए रखने में सक्षम बनाने के लिए, यहां तक कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के खिलाफ आई. एस. के संबंध में भी । न्यायाधीश को अनुच्छेद 124 या अनुच्छेद 217 में अनिवार्य रूप से शामिल करके कार्यपालिका के नियंत्रण और प्रभाव से पूरी तरह से वंचित कर दिया जाता है कि एक न्यायाधीश को केवल अनुच्छेद 124 के खंड (4) और (5) में प्रदान की गई तरीके से उसके पद से हटाया जा सकता है । इस प्रकार, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश केंद्र सरकार और राज्य सरकार सहित पक्षों के बीच किसी भी तरह से राज्य द्वारा अप्रभावित मामलों

का निर्णय लेते समय कार्यपालिका के नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। यह किसी भी संदेह से परे है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति के बीच कोई स्वामी और सेवक संबंध या नियोक्ता और कर्मचारी संबंध नहीं है, जिसमें संघ की कार्यकारी शक्ति संविधान के अनुच्छेद 53 के प्रावधानों के तहत निहित है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को अपने पद से हटाने की एकमात्र शक्ति या अनन्य शक्ति नहीं दी गई है, हालांकि राष्ट्रपति युद्ध द्वारा न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं।

राज्यों में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का, जैसा कि वह कर सकता है उस उद्देश्य के लिए और नियुक्ति के मामले में आवश्यक समझते हैं

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद अपने हाथ और मुहर के नीचे वारंट द्वारा एक न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं।

भारत, राज्य का राज्यपाल और एक की नियुक्ति के मामले में

मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश। न्यायाधीश को उसके कार्यालय से हटाने का एकमात्र तरीका

साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता का आधार खंडों में निर्धारित किया गया है।

( 4 ) और अनुच्छेद 124 का (5)। यह वाक्पटुता और जोरदार तरीके से किया गया है।

अपीलार्थी की ओर से आग्रह किया गया कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय एक संवैधानिक पदाधिकारी है और 223

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [आरएवाई, जे।]

कोई नियोक्ता और कर्मचारी संबंध या स्वामी और सेवक नहीं है

न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति के बीच संबंध और उसके लिए

केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है

कार्यपालिका द्वारा न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार सिवाय इसके कि -

अनुच्छेद में परिकल्पित महाभियोग की प्रक्रिया का सहारा लेना

124 ( 4 ) और (5) भारत के संविधान का। यह आगे आग्रह किया गया है इस संबंध में कि यदि यह माना जाता है कि राष्ट्रपति के पास शक्ति है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा दें। कार्यालय यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को समाप्त कर देगा और करेगा अप्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका के नियंत्रण में न्यायपालिका होने के नाते भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत, राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते समय सहायता और सलाह पर कार्य करना पड़ता है प्रधान मंत्री के साथ मंत्रिपरिषद, जैसा कि है इस न्यायालय द्वारा शमशेर सिंह और अनुर में अभिनिर्धारित किया गया था। वी. पंजाब राज्य, [ 1975 ] 1 एस. सी. आर. 814 और एस. पी. गुप्ता और अन्य आदि। वी. इनिडा का संघ और ओआरएस। आदि।, ( ऊपर)। इसलिए यह आग्रह किया गया है कि धारा 6 ( 1 ) ( ग) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 इन पर लागू नहीं होता है - उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का मामला। नहीं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ अभियोजन शुरू किया जा सकता है या उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत उच्च न्यायालय के संविधान के अनुच्छेद 124, खंड 4 और 5 में परिकल्पित विधि न्यायाधीश को हटाना। विचाराधीन एफ. आई. आर., जो दर्ज की गई है अपीलार्थी के विरुद्ध याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए और उसे अलग कर दिया जाना चाहिए। धारा 2 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में परिभाषित लोक सेवक को संदर्भित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 21 (1860 का 45)। यह देखा गया है इससे पहले कि तीसरा खंड विशेष रूप से धारा 21 का भारतीय दंड संहिता में किसी भी व्यक्ति सहित प्रत्येक न्यायाधीश शामिल है। स्वयं या सदस्य के रूप में कार्य निर्वहन करने के लिए कानून द्वारा सशक्त

व्यक्तियों का कोई निकाय कोई निर्णयात्मक कार्य करता है। अतः एक न्यायाधीश उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की परिभाषा के भीतर आता है लोक सेवक और वह के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी है " भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। यह हमारे दिमाग से बहुत दूर है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश इससे मुक्त होगा। के कार्यकाल के दौरान किए गए अपराधिक अपराधों के लिए अभियोजन से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनका कार्यालय।

इन परिस्थितियों में विचार करने के लिए एकमात्र सवाल यह है कि कौन प्राधिकरण होगा या जिसके लिए मंजूरी देने का अधिकार होगा धारा 6 (1) (सी) के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अभियोजन अधिनियम ने कहा। न्यायाधीश को एक संवैधानिक पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा रहा है राष्ट्रपति को केवल अनिवार्य प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत और किसी अन्य तरीके से नहीं। द. न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 संसद द्वारा 3 एस. सी. आर. को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

224

#### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान के अनुच्छेद 124 की उप धारा 1 के खंड (5) के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच और प्रमाण के लिए प्रक्रिया। न्यायाधीश (जांच) नियम, 1969 न्यायाधीशों की धारा 7 (4) के तहत बनाए गए हैं।

( जांच) अधिनियम, 1968। केवल उक्त अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम साबित दुर्व्यवहार के आधार पर न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान

या असमर्थता। इसमें अपराधों के लिए न्यायाधीश पर मुकदमा चलाने का प्रावधान नहीं है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 (1) (ई) के तहत। यह है।

मंत्रि पद की जिम्मेदारी का विकास, महाभियोग एक हथियार था द्वारा नियुक्त लेखा मंत्रियों को बुलाने के लिए कॉमन्स को सक्षम करना, और

क्राउन के लिए जिम्मेदार। जैसे-जैसे आम लोगों ने प्रत्यक्ष नियंत्रण हासिल किया

मंत्रियों पर, बोझिल मशीन को काम पर रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी

महाभियोग की संख्या बहुत कम है और 1805 के बाद से कोई महाभियोग नहीं हुआ है। चूँकि राजनीतिक अपराधियों के महाभियोग में न केवल वंचित करना शामिल हो सकता है

पद का त्याग लेकिन अन्य दंड, क्षमा का शाही विशेषाधिकार

महाभियोग को रोकने के लिए नहीं बल्कि क्षमा करने के लिए विस्तारित है

महाभियोग पर दंड। इंग्लैंड में, कार्यालय आयोजित किए गए

अच्छे व्यवहार के दौरान दुराचार की स्थिति में निर्धारित किया जा सकता है

महाभियोग द्वारा। व्यवहार में, हालांकि, क्राउन के लिए एक पता

एक न्यायाधीश को हटाने की उत्पत्ति हाउस ऑफ कॉमन्स में होनी चाहिए;

के अधिनियम के बाद से इस विधि से न्यायाधीश को हटाने का उदाहरण समझौता। महाभियोग या संबोधन द्वारा हटाने की यह शक्ति, ए

अच्छे व्यवहार के दौरान पद धारण करने वाला व्यक्ति, एक आवश्यक काउंटर है द्वारा उच्च पद धारकों को प्राप्त स्वतंत्रता का हिस्सा

उनके कार्यकाल को आनंद के बजाय अच्छे व्यवहार में से एक बनाना।

कला के तहत। II, एस। 4 , अमेरिकी संविधान, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति

राष्ट्रपति और संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी नागरिक अधिकारियों को हटाया जा सकता है

"देशद्रोह, रिश्वतखोरी" के लिए महाभियोग और दोषसिद्धि पर पद से या अन्य उच्च अपराध और दुराचार "। राष्ट्रपति के बाद से

संयुक्त राज्य अमेरिका जो राज्य का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण है,

महाभियोग का प्रावधान किया गया है और वास्तव में, राष्ट्रपति जॉनसन थे 1867 में उच्च अपराधों और दुराचारों के लिए महाभियोग चलाया गया। 1913 में,

वाणिज्य न्यायालय के न्यायमूर्ति आर्चीबाल्ड को पद से हटा दिया गया था

सड़क कंपनियाँ, जिनमें से कुछ उस समय उनके न्यायालय में वादी थीं; 1936 में फ्लोरिडा न्यायालय के न्यायाधीश राइट को आचरण के लिए हटा दिया गया।

एक प्राप्त के संबंध में जिसने इस बारे में गंभीर संदेह पैदा किए सत्यनिष्ठा, हालाँकि उन्हें विशिष्ट आरोपों से बरी कर दिया गया था, ऐसा लगता है कि

व्यापक दृश्य को पुनर्स्थापित किया। क्योंकि, किसी भी मामले में, दोनों न्यायाधीश नहीं थे

एक अभियोग अपराध का दोषी पाया गया। यह कहा गया है कि:

225

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [आर. ए. वाई, जे.)

" संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायाधीशों के लिए कम से कम 'अच्छे' की कमी

व्यवहार 'और' उच्च अपराध और दुराचार 'समाप्त हो गए हैं।  
लैपिंग यदि सटीक रूप से संयोगात्मक अवधारणाएं नहीं हैं।

( सीरवई का भारत का संवैधानिक कानून, तीसरा संस्करण, Vol.II, पृष्ठ

1698 पैरा 18.8 और 18.9)।

सॉलिसिटर जनरल के साथ-साथ अड्डी ने भी इसका आग्रह किया है

राष्ट्रीय सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में दिए गए अपराधों के संबंध में अभियोजन से छूट नहीं दी जा सकती है। यह भी आग्रह किया गया है कि अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए या उन शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन में उनके द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह होने से सुरक्षा दी गई है। उक्त अनुच्छेद के खंड 2 में आगे यह प्रावधान किया

गया है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू या शुरू नहीं की जाएगी। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में आपराधिक अभियोजन से ऐसी कोई प्रतिरक्षा प्रदान नहीं की गई है। इसलिए, यह आग्रह किया गया है कि उच्च न्यायालय को उक्त अधिनियम के तहत एक न्यायाधीश के खिलाफ अभियोजन शुरू करने के लिए तौर-तरीके सुनिश्चित करने चाहिए। निस्संदेह, न्यायपालिका और इसकी सार्वजनिक विश्वसनीयता और गरिमा के प्रति सम्मान बनाए रखना होगा ताकि सार्वजनिक रूप से न्यायाधीशों के लिए और न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों के लिए भी सम्मान सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए, गंभीर आरोपों के मामलों में मंजूरी देने के अनुरूप कुछ विधि विकसित करना आवश्यक है। भ्रष्टाचार और अधिग्रहण या आय से अधिक परिसंपत्तियों का कब्जा जिसका न्यायाधीश संतोषजनक रूप से लेखा नहीं दे सकता है या न्यायाधीश की आय के स्रोतों के अनुपात से अधिक संपत्ति का कब्जा। यदि इन बातों पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, तो यह उच्च पद की गरिमा, सम्मान और विश्वसनीयता और अखंडता पर एक गंभीर अवरोध पैदा करेगा, जिसे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश धारण करता है, जिसके परिणामस्वरूप जनता के आकलन में न्यायाधीशों के उच्च पद की गरिमा और सम्मान पर क्षरण होता है। जैसा कि मेरे विद्वान भाई शेड्टी, जे. ने सुझाव दिया है कि राष्ट्रपति को अपने हाथ और मुहर के नीचे वारंट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति दी गई है और इसी तरह संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुच्छेद 124, खंड (4) और (5) में प्रदान किए गए तरीके से एक संबोधन पारित करने और राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाने के बाद भी, एक न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति द्वारा उस आशय का आदेश पारित नहीं किया जाता है। अतः राष्ट्रपति के पास 226 के आधार पर न्यायाधीश को नियुक्त करने के साथ-साथ अपने पद से हटाने की शक्ति है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1991] 3 एस. सी. आर.

संविधान के अनुच्छेद 124 में प्रावधान के अनुसार दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हुई। राष्ट्रपति, इसलिए, एक न्यायाधीश को नियुक्त करने और हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी होने के नाते, संविधान के अनुच्छेद 124, खंड (4) और (5) में परिकल्पित प्रक्रिया के अनुसार, अभियोजन के लिए मंजूरी देने का प्राधिकारी माना जा सकता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 (1) (ई) में उपबंधित अपराधों के संबंध में धारा 6 (1) (सी) के प्रावधानों के तहत न्यायाधीश की नियुक्ति। एक न्यायाधीश को तुच्छ सुरक्षा और अनावश्यक उत्पीड़न से पर्याप्त रूप से बचाने के लिए राष्ट्रपति न्यायाधीश से परामर्श करेंगे

भारत के मुख्य न्यायाधीश जो अपने समक्ष रखी गई सभी सामग्रियों पर विचार करेंगे और मामले में संतुष्ट होने के बाद संबंधित न्यायाधीश के खिलाफ अभियोजन शुरू करने या प्राथमिकी दर्ज करने की मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति को अपनी सलाह देंगे। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यदि मुख्य न्यायाधीश की राय है कि यह संबंधित न्यायाधीश के अभियोजन के लिए मंजूरी देने के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं है, तो राष्ट्रपति न्यायाधीश को गद्य के लिए मंजूरी नहीं देंगे। यह संबंधित न्यायाधीश को अनावश्यक उत्पीड़न के साथ-साथ उसके खिलाफ तुच्छ अभियोजन से बचाएगा जैसा कि मेरे विद्वान भाई जे. शेर्टी ने अपने फैसले में कहा था। इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मामले में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करेगा जो उसे उचित और उचित लगे और राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या न्यायाधीशों द्वारा उसे दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। लोक सेवक अर्थात् उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर मुकदमा चलाने से पहले पूर्व मंजूरी देने का उद्देश्य न्यायाधीश को अनावश्यक उत्पीड़न और तुच्छ अभियोजन से बचाना है, विशेष रूप से न्यायाधीश को उस मामले में निर्णय देने के लिए पक्षपातपूर्ण अभियोजन से बचाना है जो सरकार या उसके अधिकारियों के खिलाफ जाता है, हालांकि अच्छे कारणों और कानून के शासन के आधार पर। इस संबंध में सी. के. डाफ्टरी बनाम में निर्णय का उल्लेख किया जा सकता है। ओ. पी. गुप्ता, ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 1132, जिसमें यह कहा गया है:

" हमें ऐसा लगता है कि जिसने भी महाभियोग प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया है, उसने अनुच्छेद 124 (4) में व्यक्त "दुर्व्यवहार" के अर्थ के भीतर तथ्यों को लाने की दृष्टि से इसका मसौदा तैयार किया है, क्योंकि उसने यह महसूस किया होगा कि यह कहना कि एक न्यायाधीश ने त्रुटियों को कम किया है, यहां तक कि गंभीर त्रुटियां भी नहीं हो सकती हैं।

" दुर्व्यवहार "।

यह तर्क कि केंद्र सरकार या उसके किसी भी अधिकारी के खिलाफ निर्णय देने के लिए किसी न्यायाधीश के खिलाफ तुच्छ अभियोजन शुरू किया जा सकता है, इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि इस तरह का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 124 के अर्थ के भीतर दुर्व्यवहार नहीं है।

संविधान।

इस संबंध में यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि अपील

जब सी. बी. आई. द्वारा एफ़. आई. आर. दर्ज की गई तो उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे दिया, इसलिए सी. बी. आई. द्वारा उनके खिलाफ एफ़. आई. आर. दर्ज करने की तारीख को वे लोक सेवक नहीं रहे। भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 6 के दायरे और प्रयोज्यता पर विचार किया गया

नायक बनाम. ए. आर. अंतुले, [1984] 2 एस. सी. आर. 495 संविधान के समक्ष

इस न्यायालय का च जहां यह अवलोकन किया गया है:

" धारा 6 न्यायालय को इसका संज्ञान लेने से रोकती है

इसमें कथित रूप से किए गए अपराधों की गणना की गई है

की पूर्व मंजूरी के अलावा एक लोक सेवक द्वारा

आवश्यक अनुदान देने के लिए सशक्त सक्षम प्राधिकारी

मंजूरी।

सेक्शन 6 कोर्ट के लिए एक बार बनाता है

उसमें उल्लिखित अपराधों का संज्ञान लेने से

में निर्धारित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के अलावा

उप-धारा का खंड (ए) (बी) और (सी)। ( आई)। अंतर्निहित वस्तु

इस तरह का प्रावधान लोक सेवक को बचाने के लिए था

तुच्छ या अप्रमाणित आरोपों का उत्पीड़न। द.

एस. सी. में अंतर्निहित नीति। 6 और इसी तरह के अनुभाग हैं कि

लोक सेवकों का अनावश्यक उत्पीड़न नहीं होना चाहिए

( सी. आर. बंसी बनाम महाराष्ट्र राज्य), [1971] 3 एस. सी. आर. 236।

इस प्रकार एक वैध मंजूरी का अस्तित्व एक पूर्व-आवश्यकता है

कथित रूप से गणना किए गए अपराधों का संज्ञान लेना

एक लोक सेवक द्वारा किया गया है। बार के लिए है

न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेना। इसलिए, जब लोक सेवक पर कथित अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए लोक सेवक के रूप में उनके द्वारा प्रतिबद्ध किया गया है। संदेह नहीं धीरे-धीरे अभियुक्त को लोक सेवक होना चाहिए जब वह आरोप है कि उसने वह अपराध किया है जिसका वह दोषी है अभियुक्त क्योंकि आई. पी. सी. की धारा 161, 164, 165 और धारा 15 ( 2 ) में से 1947 के अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसमें अपराध परिभाषित एक लोक सेवक द्वारा किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए टेम्प्लेट किया गया है जिसने अपराध किया है ऐसे अपराध, जब न्यायालय को संज्ञान लेने के लिए कहा जाता है अपराध की संभावना, एक सजा उपलब्ध होनी चाहिए अन्यथा न्यायालय के पास लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। अपराध का संज्ञान। वैध मंजूरी के बिना मुकदमा जहाँ धारा 6 के तहत एक आवश्यक माना गया है न्यायालय द्वारा अधिकारिता के बिना एक मुकदमा। ( आर. आर. चारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एस. एन. बोस बनाम बिहार राज्य), मोहम्मद। इकबाल अहमद बनाम। ए. पी. राज्य में, यह माना गया था कि टर्मिनस सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [1991] 3 एस. सी. आर.

228

वैध मंजूरी के लिए ए क्वो वह समय होता है जब अदालत को अपराध का संज्ञान लेने के लिए कहा जाता है। इसलिए, जब अपराध किए जाने का आरोप लगाया जाता है तो अभियुक्त एक लोक सेवक था, लेकिन जब तक अदालत को लोक सेवक के रूप में उसके द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान लेने के लिए कहा जाता है, तब तक वह लोक सेवक नहीं रह जाता है,

उसके खिलाफ अपराध का संज्ञान लेने के लिए किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। यह दृष्टिकोण धारा में अंतर्निहित नीति के अनुरूप है। 6 कि एक लोक सेवक को एक तुच्छ या सट्टा पेशेवर के उत्पीड़न के लिए उजागर नहीं किया जाना है

सेक्यूशन। यदि वह इस बीच एक लोक सेवक बनना बंद कर देता है, तो यह महत्वपूर्ण विचार अस्तित्व में नहीं रहता है।

वर्तमान अपील में अपीलार्थी लोक सेवक नहीं रह जाता है क्योंकि उसने पद से त्यागपत्र दे दिया था। इसलिए एफ. आई. आर. दर्ज करने के समय अपीलार्थी लोक सेवक नहीं रह जाता है और इसलिए धारा के तहत कोई मंजूरी नहीं है।

6 ( 1 ) ( ग ) उक्त अधिनियम आवश्यक है। अतः मंजूरी के संबंध में तर्क का मुख्य आधार अस्तित्व में नहीं है। इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय का निर्णय और आदेश धारा के तहत आवेदन को खारिज करता है। 482 आपराधिक संहिता

प्रक्रिया पूरी तरह से कानून के अनुसार है और इस तरह उच्च न्यायालय के आदेश को किसी भी परिस्थिति में बरकरार रखा जाना चाहिए। मैं अपने विद्वान भाई जे. शेड्टी के निष्कर्ष से सहमत हूँ, इसलिए अपील खारिज कर दी जाती है। प्रत्यर्थी द्वारा दायर आपराधिक मामला सं. 46/77 का मुकदमा आगे बढ़ाया जाए।

के. जगन्नाथ शेड्टी, जे. प्रमाण पत्र द्वारा यह अपील

संविधान के अनुच्छेद 132 (1) और 134 (1) (ई) के तहत मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा दायर किया गया है। उसी उच्च न्यायालय की पीठ ने उनके खिलाफ की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया। यह अपील उच्च न्यायालयों और इस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए एकमात्र महत्व और परिणाम के प्रश्न उठाती है। केंद्रीय मुद्दा यह है कि क्या न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 ('अधिनियम') के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।

सबसे छोटी रूपरेखा में मामले की पृष्ठभूमि इस प्रकार है: अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता के रूप में अपना जीवन शुरू किया

मद्रास। वे 1941 में मद्रास बार में शामिल हुए। 1953 में उन्हें सहायक सरकारी वकील के रूप में नियुक्त किया गया। 1959 में वे सरकार बने।

प्लीडर। उन्होंने 20 फरवरी 1960 तक उस पद पर कार्य किया जब उन्हें मद्रास उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में बेंच में पदोन्नत किया गया।

229 पर

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [शेड्टी, जे।]

1 मई 1969 में वे मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने।

कहा जाता है कि न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने आय के ज्ञात स्रोत से असमान रूप से अर्जित परिसंपत्तियाँ। द.

इस संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस में शिकायत की गई थी।

स्थापना ("सीबीआई")। 24 फरवरी 1976 को, सी. बी. आई. ने उनके खिलाफ एक प्रथम सूचना रिपोर्ट जारी करने के साथ एक मामला दर्ज किया जो नई दिल्ली की एक अदालत में दायर किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपीलार्थी की आय के स्रोतों और उसके न्यायाधीश/मुख्य न्यायाधीश की अवधि के दौरान आवश्यक संभावित खर्चों के साथ उसके जीवन के तरीके और शैली को ध्यान में रखते हुए, यह उचित रूप से माना जाता है कि अपीलार्थी उन संपत्तियों के कब्जे के लिए संतोषजनक रूप से हिसाब नहीं दे सकता है जो उसकी आय के ज्ञात स्रोत से बहुत अधिक हैं। यह भी आरोप लगाया गया कि उसने ऐसा किया है

अधिनियम की धारा 5 (1) के खंड (बी) (डी) और (ई) के साथ पठित धारा 5 (2) के तहत अपराध। 28 फरवरी 1976 को प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति जांच अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से मद्रास ले जाया गया था।

और इसे विशेष न्यायाधीश, मद्रास के न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था। द एपेल-। इन घटनाओं के बारे में पता चलने पर वे छुट्टी पर चले गए 9 मार्च 1976 से और बाद में 8 अप्रैल 1976 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुए।

हालाँकि, सी. बी. आई. द्वारा मामले की जाँच जारी रही।

अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने की परिणति के साथ। 15 दिसंबर 1977 को दंड प्रक्रिया संहिता (सी. आर.) की धारा 173 (2) के तहत एक अंतिम रिपोर्ट। पी. सी.) अपीलार्थी के खिलाफ विशेष न्यायाधीश, मद्रास के समक्ष दायर किया गया था। धारा 173 (2) के तहत रिपोर्ट को आम तौर पर आरोप पत्र कहा जाता है, और हम इसे आरोप पत्र भी कहना पसंद करेंगे। आरोप-पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि अपीलार्थी ने मद्रास के मुख्य न्यायाधीश के

रूप में पदभार संभालने के बाद धीरे-धीरे आय से अधिक संपत्ति आदि जमा करना शुरू कर दिया। कि 1 मई 1969 से 24 फरवरी 1976 के बीच की अवधि के लिए, उनके पास रुपये की आय से अधिक आर्थिक संसाधन और संपत्ति थी। 6. 41, इसी अवधि में आय के ज्ञात स्रोतों के लिए। यह उनके अपने नाम और उनकी पत्नी श्रीमती के नाम पर था। एलुथाई अम्मल और उनके दो बेटे श्री वी. सुरेश और श्री वी. भास्कर। अपीलार्थी संतोषजनक रूप से नहीं कर सकता है

ऐसी असमान परिसंपत्तियों के लिए लेखा। अपीलार्थी ने इस प्रकार धारा 5 (1) के खंड (ई) के तहत आपराधिक दुराचार का अपराध किया है जो अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत दंडनीय है। उपरोक्त अवधि के दौरान आय से अधिक परिसंपत्तियों और अपील की आय का विवरण आरोप पत्र में पूरी तरह से दिया गया है। आरोप-पत्र को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अपीलार्थी की उपस्थिति के लिए प्रक्रिया जारी की थी, लेकिन अपील

230

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1991] 3 एस. सी. आर.

लैट वहाँ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया। पी. सी. ने उच्च न्यायालय के समक्ष उस आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए तर्क दिया कि उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही असंवैधानिक, पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना, अवैध और शून्य थी। उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने बहुमत के दृष्टिकोण से उनके मामले को खारिज कर दिया है। कभी भी, मामले में शामिल संवैधानिक प्रश्नों के महत्व को देखते हुए उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष हर संभावित बिंदु पर तर्क दिया गया था। वे विविध और विविध हैं। हम संक्षेप में उन दलीलों का उल्लेख उनकी जांच करने के उद्देश्य से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनमें से अधिकांश को हमारे सामने नहीं दबाया गया है, बल्कि केवल यह इंगित करने के लिए है कि अपीलार्थी ने अपने मामले को कैसे पेश किया। यह तर्क दिया गया था कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सामान्य आपराधिक न्यायालयों के समक्ष जवाबदेह नहीं होंगे, बल्कि केवल संसद के प्रति जवाबदेह होंगे।

उनके दुर्व्यवहार से अकेले संसद ही निपट सकती थी संविधान के अनुच्छेद 217 और 218 के साथ पठित अनुच्छेद 124 (4) और (5) के प्रावधान। न्यायाधीश सुपरन की उम्र तक पद धारण करते हैं।

साबित दुर्व्यवहार या असमर्थता के लिए पहले हटाए जाने के अधीन इट्टी। न्यायाधीशों को यह संरक्षण विफल हो जाएगा यदि उन्हें मजबूर किया जाता है उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते समय किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाता है सेवानिवृत्ति से पहले भी कार्यालय। यहां तक कि संसद या राज्य विधानमंडल भी मामलों में अपराध पैदा करने वाले कानून बनाने के लिए पात्र सक्षम नहीं हैं।

न्यायाधीश के कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित। ऐसा कोई भी कानून दूषित कर देगा योजना और संविधान की संघीय संरचना, विशेष रूप से

अनुच्छेद 124 (4) की योजना को अनुच्छेद 217 और 218 के साथ पढ़ा जाता है। यदि विधायी निकायों को अपराध पैदा करने की शक्तियां दी जाती हैं जिसके लिए न्यायाधीश कर सकते हैं

तब साधारण आपराधिक न्यायालयों में मुकदमा चलाया जाए, यह बहुत ही भारतीय को प्रभावित कर सकता है

न्यायपालिका का विचाराधीनता और संविधान की मूल संरचना।

हालांकि धारा 21 के तहत "लोक सेवक" की परिभाषा

भारतीय दंड संहिता में उच्च न्यायपालिका का एक न्यायाधीश शामिल हो सकता है, क्योंकि न्यायाधीश संघ के मामलों के संबंध में नियोजित नहीं है।

या 'राज्य', परिभाषा को केवल अन्य न्यायाधीशों के लिए संकुचित किया जाना चाहिए

उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की तुलना में।

अपीलकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज करने और अपराध की जांच करने के लिए सी. बी. आई. के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाए गए। जारी करना

प्रथम सूचना रिपोर्ट और बाद में आरोप दाखिल करना शीट पर महाभियोग चलाया गया। यह आरोप लगाया गया था कि उन्हें कोल द्वारा प्रेरित किया गया था

पार्श्वक विचार। वैकल्पिक रूप से, यह दावा किया गया था कि यहाँ तक कि मान भी लें

यह मानते हुए कि अपीलार्थी के खिलाफ सभी आरोप सही हैं, यह नहीं होगा अधिनियम की धारा 5 (1) के खंड (ई) के तहत अपराध का गठन करता है क्योंकि अपराध के तत्व मामले में मौजूद नहीं हैं। अंतिम और 232

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [शेट्टी, जे।]

शायद उच्च न्यायालय के समक्ष आग्रह किया गया सबसे महत्वपूर्ण विवाद अपीलार्थी के अभियोजन के लिए कॉम्पे टेंट प्राधिकरण से पूर्व मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता के बारे में था, जैसा कि नीचे आवश्यक है।

अधिनियम की धारा 6। और चूंकि ऐसी कोई मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी, इसलिए न्यायालय के पास मामले का संज्ञान लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

न्यायमूर्ति मोहन, जिनके साथ न्यायमूर्ति नटराजन, (उनके रूप में)

तब था) एक सुविचारित निर्णय में सभी दलीलों को खारिज कर दिया। जे. मोहन द्वारा अंतिम मुद्दे को छोड़कर सभी मुद्दों पर व्यक्त किए गए विचारों को यहां प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन सभी मुद्दों को हमारे सामने नहीं उठाया गया है। अपीलार्थी के अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता से संबंधित अंतिम पहलू पर, विद्वान न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि अपीलार्थी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है और आरोप पत्र दाखिल करने की तारीख को 'लोक सेवक' नहीं रहा है, इसलिए अधिनियम की धारा 6 के तहत उसके अभियोजन के लिए आवश्यक मंजूरी आवश्यक नहीं है। तीसरे न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति बालासुब्रमण्यन ने एक अलग फैसले में अधिकांश प्रश्नों पर बहुमत के विचारों से सहमति व्यक्त की है। हालांकि, उनका तीन बिंदुओं पर मतभेद है, जिनमें से केवल एक का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अन्य दो का हमारे समक्ष अपीलार्थी के वकील द्वारा समर्थन नहीं किया गया है। विद्वत न्यायाधीश ने धारा 5 (1) के खंड (ई) के तहत अपराध के अंतर्निहित मामलों पर विचार किया है, जिसके साथ अपीलार्थी पर आरोप लगाया गया था। अपराध के तत्वों का विश्लेषण करते हुए, उन्होंने कहा कि अपराध का सार केवल संपत्ति का कब्जा नहीं है। न ही आय पर परिसंपत्तियों की सरासर अधिकता, बल्कि लोक सेवक की अतिरिक्त राशि के लिए संतोषजनक रूप से जवाबदेह नहीं होने में असमर्थता। उन्होंने कहा कि अधिनियम की धारा 5 (1) का खंड (ई) असंतोषजनक लेखांकन स्थापित करने का बोझ पूरी तरह से इस पर डालता है -

अभियोजन पक्ष। धारा द्वारा डाले गए इस बोझ का ठीक से निर्वहन करने के लिए, जांच अधिकारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह सबसे पहले लोक सेवक को आय से अधिक संपत्ति के लिए जिम्मेदार ठहराए। फिर उसे लोक सेवक के स्पष्टीकरण पर अपने स्वयं के निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उसे बताना चाहिए कि यह संतोषजनक है या नहीं। और धारा 5 (1) के खंड (ई) के तहत शिकायत किए गए अपराध को जांच अधिकारी द्वारा इस तरह के अभ्यास और

निष्कर्ष के बिना नहीं बनाया जाता है। हालाँकि, विद्वान न्यायाधीश अपने तर्क को संशोधित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतते थे ताकि यह संवैधानिक संरक्षण के अनुरूप हो सके।

संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के तहत अभियुक्त को गारंटी। अनुच्छेद 20 (3) में प्रावधान है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि अनुच्छेद 20 (3) को ध्यान में रखते हुए जांच अधिकारी के पास आरोपी को अपनी आय से अधिक राशि के लिए अपना स्पष्टीकरण देने के लिए मजबूर करने की कोई शक्ति नहीं है

परिसंपत्तियाँ, लेकिन उसे अनिवार्य रूप से लोक सेवक से खाते के लिए पूछना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1991] 3 एस. सी. आर.

232

इस मामले में, अभियुक्त-अपीलार्थी ने स्वेच्छा से अपनी संपत्ति और आय का विवरण जांच अधिकारी को प्रस्तुत किया है। जाँच प्रक्रिया। हालाँकि, ऐसा लगता है कि जे. बालासुब्रमण्यन ने उस बयान को नजरअंदाज कर दिया और अपीलार्थी को आय से अधिक संपत्ति के लिए जवाबदेह नहीं ठहराने में जांच अधिकारी के चूक पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उस दृष्टिकोण से, उन्होंने कहा कि आरोप पत्र को कायम नहीं रखा जा सकता है और तदनुसार अभियोजन को रद्द कर दिया।

हमसे पहले, अपीलार्थी के वकील ने केवल दो प्रस्ताव पेश किए

टियोन। पहला आरोप अपराध के घटकों और अपीलार्थी के खिलाफ दायर आरोप पत्र की आवश्यकताओं से संबंधित है। इसमें जाँच अधिकारी के कर्तव्य भी शामिल हैं। इस संबंध में वकील ने बालासुब्रमण्यन, जे. द्वारा अपने असहमत निर्णय में व्यक्त किए गए विचारों का समर्थन करने की मांग की। दूसरा प्रस्ताव इनप्लिका से संबंधित है।

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अधिनियम की योग्यता। द. इस पहलू पर की गई प्रस्तुतियों का सार विशेष पर आधारित है

उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की स्थिति और भूमिका और आवश्यकता में

संवैधानिक के अनुरूप न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करना प्रावधान।

हम पहले दूसरे प्रश्न पर विचार करेंगे।

क्योंकि, यदि यह अपीलार्थी के पक्ष में निर्धारित किया जाता है, तो पहला यह अकादमिक हो जाता है और हम आसानी से इसे छोड़ सकते हैं। एक उचित के लिए दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा की गई दलीलों पर विचार अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

धारा 2 में कहा गया है:

" 2. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "लोक सेवक" का अर्थ है भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में परिभाषित एक लोक सेवक।

धारा 4 में कहा गया है:

4. [ ( 1 ) ] जहां भारतीय दंड संहिता की धारा 161 या धारा 165 (या इस अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (ए) या खंड (बी) में निर्दिष्ट अपराध की उप-धारा (2) के तहत दंडनीय) के तहत दंडनीय अपराध के किसी भी मुकदमे में, यह साबित हो जाता है कि एक अभियुक्त व्यक्ति ने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी भी अनुग्रह (कानूनी पारिश्रमिक के अलावा) या किसी भी मूल्यवान चीज को किसी भी व्यक्ति से स्वीकार किया है या प्राप्त किया है या प्राप्त करने का प्रयास किया है, तो यह तब तक माना जाएगा जब तक कि इसके विपरीत 233 नहीं है।

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [शेट्टी, जे।]

साबित किया कि उसने स्वीकार किया या प्राप्त किया, या स्वीकार करने के लिए सहमत हुआ या

उस संतुष्टि या उस मूल्यवान को प्राप्त करने का प्रयास किया वस्तु, जैसा भी मामला हो, एक उद्देश्य या पुरस्कार के रूप में जैसे कि है

उक्त धारा 161 में उल्लिखित, या, जैसा भी मामला हो, बिना विचार किए या उस विचार के लिए जो उसने

अपर्याप्त होना जानते हैं। ( 2 ) जहाँ के तहत दंडनीय अपराध के किसी भी मुकदमे में

इस अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) से यह साबित होता है कि कोई संतुष्टि (कानूनी पारिश्रमिक के अलावा) या कोई

मूल्यवान वस्तु दी गई है या देने की पेशकश की गई है या

उस संतुष्टि को देने का प्रस्ताव दिया या देने का प्रयास किया या वह मूल्यवान वस्तु, जैसा भी मामला हो, एक उद्देश्य के रूप में या

भारतीय दंड संहिता की धारा 161 में उल्लिखित पुरस्कार दंड संहिता या, जैसा भी मामला हो, बिना किसी विचार के

या एक ऐसे विचार के लिए जिसे वह अपर्याप्त जानता है। ( 3 ) उप-धाराओं (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद

और (2) न्यायालय अनुमान लगाने से इनकार कर सकता है। उक्त उप-धाराओं में से किसी में संदर्भित, यदि निःशुल्क

उसकी राय में, उपरोक्त बात या बात इतनी तुच्छ है कि नहीं भ्रष्टाचार का निष्कर्ष निष्पक्ष रूप से निकाला जा सकता है।'

अन्य प्रावधान अधिक सामग्री हैं, अर्थात् धारा 5 और और पूरी तरह से निर्धारित किया जाना चाहिए।

आयन 5 प्रदान करता है:

" 5 ( 1 ) एक लोक सेवक को अपराध करने के लिए कहा जाता है

आपराधिक दुराचार

1

( क ) यदि वह आदतन स्वीकार करता है या प्राप्त करता है या स्वीकार करने के लिए सहमत होता है या

अपने लिए या किसी के लिए किसी व्यक्ति से प्राप्त करने का प्रयास

अन्य व्यक्ति, कोई भी संतुष्टि (कानूनी पारिश्रमिक के अलावा) (टियोन) एक उद्देश्य या पुरस्कार के रूप में जैसा कि खंड में उल्लिखित है।

161 भारतीय दंड संहिता, या

(ख) यदि वह आदतन स्वीकार करता है या प्राप्त करता है या स्वीकार करने के लिए सहमत होता है।

या अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्राप्त करने का प्रयास,

विचार किए बिना या [1991] 3 एस. सी. आर. के लिए कोई भी मूल्यवान वस्तु।

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिस पक्ष को वह अपर्याप्त जानता है, किसी भी व्यक्ति से, जिसे वह जानता है कि वह किसी कार्यवाही या व्यवसाय में शामिल था, या होने की संभावना है, जो उसके द्वारा की गई या होने वाली है, या जिसका अपने या किसी अन्य के आधिकारिक कार्यों से कोई संबंध है।

लोक सेवक जिसके वह अधीनस्थ है, या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे वह जानता है कि वह इस तरह से संबंधित व्यक्ति में रुचि रखता है या उससे संबंधित है, या

(ग) यदि वह बेईमानी से या धोखाधड़ी से दुरुपयोग करता है या अन्यथा लोक सेवक के रूप में उसे सौंपी गई या अपने नियंत्रण में किसी संपत्ति को अपने उपयोग के लिए परिवर्तित करता है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति देता है, या

(घ) यदि वह भ्रष्ट या अवैध तरीकों से या अन्यथा लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक सलाह प्राप्त करता है।

टेग (या)

(ङ) यदि वह या उसकी ओर से कोई व्यक्ति अधिकार में है या अपने पद की अवधि के दौरान किसी भी समय अधिकार में रहा है।

सायन, जिसके लिए लोक सेवक संतोषजनक रूप से नहीं कर सकता है

आर्थिक संसाधनों या संपत्ति के अनुपात का लेखा-जोखा  
पर ध्यान दें।

आय के अपने ज्ञात स्रोतों

( 2 ) कोई भी लोक सेवक जो आपराधिक कदाचार करता है, वह एक वर्ष से कम की अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, लेकिन जो सात वर्ष तक बढ़ सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा:

बशर्ते कि न्यायालय किसी विशेष कारण से

लिखित रूप में अभिलिखित, एक वर्ष से कम के कारावास की सजा अधिरोपित करें।

( 3 ) जो भी आदतन करता है

( (i) धारा 162 के अधीन दंडनीय अपराध या

भारतीय दंड संहिता की धारा 163, या

( (ii) संविधान की धारा 165 ए के तहत दंडनीय अपराध।

भारतीय दंड संहिता, एक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय होगा जो 235

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [शेड्टी, जे।]

एक वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन जिसका विस्तार हो सकता है सात वर्ष, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा:

बशर्ते कि न्यायालय किसी विशेष कारण से लिखित रूप में अभिलिखित, कारावास की सजा अधिरोपित करें

( 3 ए) जो कोई भी निर्दिष्ट अपराध करने का प्रयास करता है उप-धारा (1) के खंड (ग) या खंड (घ) में दंड दिया जाएगा।

एक अवधि के लिए कारावास के साथ सक्षम जो विस्तारित हो सकता है

तीन साल, या जुर्माना, या दोनों के साथ।

( 3 बी) जहां उप के तहत जुर्माने की सजा दी जाती है

धारा (2) या उप-धारा (3) निर्धारित करने में न्यायालय

जुर्माने की राशि को ध्यान में रखा जाएगा या

संपत्ति का मूल्य, यदि कोई हो, जो अभियुक्त व्यक्ति

अपराध करके या जहां अपराध किया गया है

धारा (1), निर्दिष्ट आर्थिक संसाधन या संपत्ति                      उस खंड में जिसके लिए अभियुक्त  
व्यक्ति असमर्थ है

संतोषजनक लेखा।

और कुछ समय के लिए किसी अन्य कानून के अपमान में नहीं                      लागू है, और इसमें  
निहित कुछ भी किसी भी छूट से मुक्त नहीं होगा

लोक सेवक को किसी भी कार्यवाही से, जो इसके अलावा हो सकती है

इस धारा से उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए।

आयन 6 निम्नलिखित शब्दों में है:

" 6. कोई भी अदालत किसी दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगी।

धारा 161 (या धारा 164) या धारा 165 के तहत सक्षम

भारतीय दंड संहिता, या उप-धारा (2) (या उप-धारा) के तहत

3 ए) इस अधिनियम की धारा 5 की धारा, जो कथित रूप से की गई है

एक लोक सेवक द्वारा, पिछली मंजूरी के अलावा,                      (क) एक व्यक्ति के मामले में जो  
संबंध में कार्यरत है

(संघ) के मामलों के साथ और से हटाने योग्य नहीं है

केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा या उसकी मंजूरी के बिना उसका कार्यालय

राज्य सरकार की सरकार;

(ख) उस व्यक्ति के मामले में जो संबंध में कार्यरत है।

(एक राज्य) के मामलों के साथ और उसके [1991] 3 एस. सी. आर. से हटाने योग्य नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

( ग ) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, प्राधिकरण का उसे उसके कार्यालय से हटाने के लिए तम्बू।

( 2 ) जहाँ किसी भी कारण से कोई संदेह उत्पन्न होता है।

क्या उप-धारा के तहत आवश्यक पूर्व मंजूरी

( 1 ) केंद्र या राज्य सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए या कोई अन्य प्राधिकरण, ऐसी मंजूरी उसके द्वारा दी जाएगी सरकार या प्राधिकरण जो संयुक्त होता

उस समय लोक सेवक को उसके कार्यालय से हटाने के लिए तम्बू जब अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया था।

अगर इस स्तर पर, हम धारा 5 ए भी पढ़ते हैं, तो यह सुविधाजनक नहीं होगा। अप्रासंगिक खंड, धारा 5 ए इन शब्दों में है:

" 5 ए. संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद

रैंक ( क ) दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के मामले में,

एक पुलिस निरीक्षक का;

( ख ) प्रेसीडेंसी में-कलकत्ता और मद्रास के शहरों में, एक

सहायक पुलिस आयुक्त; ( ग ) प्रेसीडेंसी में-बॉम्बे के कस्बों, एक सुपरिटेन के

पुलिस का डेंट; और

( घ ) अन्यत्र, एक पुलिस उपाधीक्षक का,

धारा 161 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध की जांच करेगा,

भारतीय दंड संहिता की धारा 165 या धारा 165 ए या

अध्यक्ष के आदेश के बिना इस अधिनियम की धारा 5 के तहत

डेन्सी मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, के रूप में

मामला हो सकता है, या इसके लिए कोई गिरफ्तारी कर सकते हैं

इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, वह प्रेसी 237 के आदेश के बिना ऐसे किसी भी अपराध की जांच करें।

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [शेट्टी, जे. जे.]

डेन्सी मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, के रूप में बिना वारंट के मामला हो सकता है या गिरफ्तारी की जा सकती है:

बशर्ते कि के खंड (ई) में निर्दिष्ट अपराध

एक पुलिस अधिकारी का आदेश जो एक के पद से नीचे नहीं है पुलिस अधीक्षक।

इस अधिनियम का उद्देश्य रिश्वत और भ्रष्टाचार को दबाना था।

लोक प्रशासन और इसमें कड़े प्रावधान हैं। धारा 4 तब तक अनुमान लगाती है जब तक कि भारतीय दंड संहिता की धारा 161 या धारा 165 के तहत दंडनीय अपराध या अधिनियम की धारा 5 (1) के खंड (ए) या खंड (बी) में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में आरोपी द्वारा इसके विपरीत साबित नहीं किया जाता है। अधिनियम की धारा 5 एक लोक सेवक की ओर से आपराधिक दुराचार का अपराध पैदा करती है। धारा 2 के तहत परिभाषित लोक सेवक का अर्थ है आई. पी. सी. की धारा 21 में परिभाषित लोक सेवक। आई. पी. सी. की धारा 21 वास्तव में "लोक सेवक" को परिभाषित नहीं कर रही है, बल्कि लोक सेवकों की श्रेणियों की गणना कर रही है। यह गणना की गई है

लोक सेवकों की बारह श्रेणियाँ। धारा 5 (2) आपराधिक दुराचार के ऐसे अपराध के लिए 7 साल की अवधि तक या जुर्माने या दोनों के साथ सजा का प्रावधान करती है। धारा 6 न्यायालयों को किसी अपराध का संज्ञान लेने से रोकती है जब तक कि कुछ शर्तों का पालन नहीं किया जाता है। हमारे पास धारा 6 के प्रावधानों पर विस्तार से विचार करने का अवसर होगा और वर्तमान में हम केवल किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए अदालत के लिए धारा द्वारा निर्धारित शर्त पर ही विचार कर सकते हैं। इसमें निर्धारित शर्त एक कॉम्पे टेंट प्राधिकरण की पूर्व मंजूरी है। लोक सेवक पर धारा में निर्दिष्ट अपराधों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी न हो। यह याद रखना महत्वपूर्ण हो सकता है कि

किसी अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय में निहित है। धारा 6 मुख्य रूप से यह देखने के लिए संबंधित है कि निर्दिष्ट अपराधों के लिए अभियोजन एक सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना शुरू नहीं होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि इस अधिनियम का उद्देश्य रिश्वत और भ्रष्टाचार के अपराध को माफ करना था।

लोक सेवक। न ही इसका उद्देश्य लोक सेवक को ऐसे अपराधों के लिए आपराधिक अभियोजन से सुरक्षा प्रदान करना था। यह केवल ईमानदार लोक सेवकों को तुच्छ और परेशान करने वाले अभियोजन से बचाने के लिए है। सक्षम प्राधिकारी को अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से रिकॉर्ड पर सामग्री की जांच करनी होगी कि क्या कथित अपराध तुच्छ है या परेशान करने वाला है। सक्षम प्राधिकारी अभियोजन के लिए मंजूरी देने से इनकार कर सकता है यदि कथित अपराध के लिए कोई सामग्री नहीं है या यह तुच्छ है या ईमानदार अधिकारी को परेशान करने का इरादा है। लेकिन वह मंजूरी देने से इनकार नहीं कर सकता है यदि एकत्र की गई सामग्री में सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1991] 3 एस. सी. आर. है।

238

लोक सेवक के खिलाफ अपराध का आरोप।

वास्तव में वह मंजूरी देने के लिए बाध्य है यदि एकत्र की गई सामग्री उधार देती है। शिकायत किए गए अपराध की विश्वसनीयता। लगता है एक और

जाँच एजेंसी के विवेक को छीनने का कारण लोक सेवक पर मुकदमा चलाना या न चलाना। जब एक लोक सेवक

उस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाता है जो उसकी ईमानदारी और अखंडता को चुनौती देता है, ऐसे मामले में मुद्दा केवल अभियोजक और अभियोजक के बीच नहीं है।

अपराधी, लेकिन राज्य भी इससे बहुत चिंतित है क्योंकि यह प्रभावित करता है

लोक सेवकों का मनोबल और प्रशासनिक हित भी

राज्य। लोक सेवक पर मुकदमा चलाने का विवेकाधिकार छीन लिया जाता है

अभियोजन अभिकरण और उस प्राधिकरण में निहित है जो संयुक्त है

लोक सेवक को हटाने के लिए तम्बू। हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी

लोक सेवक अभियोजन पक्ष की तुलना में बेहतर स्थिति में होगा

निष्पक्ष और विवेकपूर्ण तरीके से एकत्र की गई सामग्री का आकलन करने वाली एजेंसी

सक्षम तरीके से और यह निर्धारित करने के लिए कि क्या अभियोजन के लिए मंजूरी लोक सेवक को मंजूरी दी जानी चाहिए या नहीं।

अब धारा 6 का विश्लेषण किया जा सकता है। धारा 6 (1) के खंड (ए) में शामिल हैं

संघ के मामलों के संबंध में कार्यरत लोक सेवक।

ऐसे व्यक्तियों के लिए पूर्व मंजूरी देने के लिए निर्धारित प्राधिकारी

केंद्र सरकार होगी। धारा 6 (1) के खंड (बी) में शामिल हैं

राज्य के मामलों के संबंध में कार्यरत लोक सेवक।

ऐसे अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी सरकार होंगे। खंड (ए) और (बी)

व्यक्ति राज्य

संघ या राज्य के मामलों के साथ और उनके से हटाने योग्य नहीं हैं या उसकी मंजूरी के साथ कार्यालय को छोड़कर

केंद्र सरकार द्वारा

राज्य सरकार। यही अंत नहीं है। खंड आगे जाता है खंड (ग) लोक सेवकों की श्रेणियों को शामिल करेगा। खंड (ग) में कहा गया है कि किसी अन्य व्यक्ति के मामले में मंजूरी उसे उसके पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की होगी। धारा 6 है

इस प्रकार जनता की सभी श्रेणियों को अपने दायरे में लाना धारा 21 के तहत परिभाषित सेवक।

आई. पी. सी. की

यह सामान्य आधार है कि धारा 6 (1) के खंड (ए) और (बी)

अधिनियम उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शामिल नहीं कर सकता है।

न्यायालय चूंकि वे मामलों के संबंध में कार्यरत नहीं हैं

संघ या राज्य। सवाल यह है कि क्या उन्हें अंदर लाया जा सकता है।

धारा 6 (1) के खंड (ग) की परिधि। श्री कपिल सिब्बल ने सीखा वकील ने खंड (ग) को पढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया।

अपीलार्थी के

“ खंड (ए) और (बी) को सामान्य माना जाता है। उनके अनुसार सभी धारा 6 केवल ऐसे लोक सेवकों पर लागू होती प्रतीत होती है जहाँ उनके और उनके नियोक्ता के बीच स्वामी और सेवक का संबंध।

239

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [शेट्टी, जे।]

यदि स्वामी और सेवक का कोई संबंध नहीं है, जैसा कि लोक सेवक और उसे नियुक्त करने के प्राधिकारी के बीच है, तो खंड (सी) लोक सेवक पर लागू नहीं होता है। जहाँ तक उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का संबंध है, यह तर्क दिया गया था कि उनके और सरकार के बीच स्वामी और सेवक का कोई संबंध नहीं है और धारा 6 (1) का खंड (सी) उनके लिए लागू नहीं है।

यह सच है कि स्वामी और सेवक का संबंध सामान्य है।

उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों और सरकार के बीच सामान्य कानून में स्पष्ट रूप से समझा जाने वाला संबंध मौजूद नहीं है। जहाँ स्वामी और सेवक का संबंध होता है, वहाँ स्वामी कमान संभालने की स्थिति में होता है। उसके पास कर्मचारी पर न केवल यह निर्देश देने की शक्ति है कि सेवक को क्या काम करना है, बल्कि यह भी कि काम कैसे किया जाना है। सेवक स्वामी की सेवा करने और अपने कर्तव्य के दायरे में उचित आदेशों का पालन करने का वचन देता है। इस तरह के रिश्ते में यह निहित है कि नौकर केवल अपने जोखिम पर ही स्वामी के आदेश की अवज्ञा कर सकता है। लेकिन न्यायाधीशों और उनकी नियुक्ति करने वाले अधिकारी यानी सरकार के बीच ऐसा कोई संबंध नहीं है। न्यायाधीश बाध्य नहीं होते हैं और न ही वे अपने कर्तव्यों के दायरे में सरकार के किसी भी आदेश का पालन करने का वचन देते हैं। वास्तव में, वे न्यायाधीश नहीं हैं यदि वे अपने कर्तव्यों के पालन में सरकार द्वारा निर्देशित होने की अनुमति देते हैं। में।

एक ही प्रकृति के शब्द। ऐसे मामले में, सामान्य शब्द या अभिव्यक्ति को केवल उसी तरह की चीजों को समझने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए जो पूर्ववर्ती विशिष्ट शब्दों या अभिव्यक्तियों द्वारा निर्दिष्ट की गई हैं। सामान्य शब्द को विशेष और विशिष्ट शब्दों के समान जीनस तक सीमित माना जाता है। ( मैक्सवेल को व्याख्या पर देखें कानूनों का, 12 वां संस्करण। पी। 297 ) . हमारे यहाँ क्या है? आई. पी. सी. की धारा 21 ने "लोक सेवक" को परिभाषित करते हुए बारह को दर्शाया है।

व्यक्तियों की श्रेणियाँ। इसमें न केवल राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी शामिल हैं, बल्कि न्यायाधीश, जूरी सदस्य, मूल्यांकनकर्ता [1991] 3 एस. सी. आर. जैसे अन्य भी शामिल हैं।

240

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और मध्यस्थ। इसमें सेवा या वेतन में प्रत्येक व्यक्ति भी शामिल है।

सरकार या सरकार द्वारा शुल्क या कमीशन द्वारा पारिश्रमिक। प्रत्येक श्रेणी दूसरे से अलग है और कुछ श्रेणियों में स्वामी और सेवक का शायद ही कोई संबंध है। द. अधिनियम की धारा 6 (1) के खंड (ए) और (बी) के प्रावधानों में लोक सेवकों की कुछ श्रेणियां शामिल हैं और 'अन्य' जिसका अर्थ है

शेष श्रेणियों को खंड (ग)/खंड (ग) के दायरे में लाया जाता है जो पूर्ववर्ती दो खंडों से स्वतंत्र और अलग है। खंड की संरचना इजसडेम जेनरिस के नियम को लागू करने की अनुमति नहीं देती है।

हालाँकि, इसकी प्रयोज्यता के लिए दो आवश्यकताएँ हैं -

उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश के लिए धारा 6 (1) का खंड (सी)। सबसे पहले, न्यायाधीश को एक लोक सेवक होना चाहिए। दूसरा, न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए एक सक्षम प्राधिकारी होना चाहिए। यदि इन दोनों आवश्यकताओं का पालन किया जाता है, तो एक न्यायाधीश अधिनियम के संचालन से बच नहीं सकता है। पहली आवश्यकता पर बहुत कम संदेह है और अपीलार्थी के वकील द्वारा भी गंभीरता से विवादित नहीं है। उनका दृष्टिकोण खंड (ग) के संचालन को केवल अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायाधीशों तक सीमित करना है। लेकिन हम उस दृष्टिकोण में कोई स्थिरता नहीं पाते हैं। आई. पी. सी. की शुरुआत से ही "प्रत्येक न्यायाधीश"

आई. पी. सी. की धारा 21 के तहत परिभाषित "लोक सेवक" की श्रेणियों में स्थान मिलता है। इसे विशेष रूप से तीसरी श्रेणी में दर्शाया गया था

आई. पी. सी. की धारा 21 के तहत लोक सेवक।

1962 में, भारत सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों में सुधार का सुझाव देने के लिए सी. के. संधानम, सांसद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति को नौ विशिष्ट संदर्भ दिए गए थे। समिति को दिया गया चौथा कार्यकाल

इसमें लिखा है: " कानून में बदलाव का सुझाव देना जो रिश्वत, भ्रष्टाचार और आपराधिक कदाचार के मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करेगा और अन्यथा कानून को और अधिक प्रभावी बनाएगा। समिति ने प्रशासनिक राशन में भ्रष्टाचार की प्रकृति से संबंधित जनता से बहुत सारे साथी रियाल एकत्र किए। जनता द्वारा समिति के समक्ष यह प्रतिनिधित्व किया गया कि भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ गया है कि लोगों ने लोक प्रशासन की अखंडता में विश्वास खोना शुरू कर दिया है। हम सभी ने सुना है।

", समिति ने बताया कि " हाल के वर्षों में भ्रष्टाचार प्रशासन के उन स्तरों तक फैल गया है जहाँ से यह अतीत में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित था। " ( संधानम समिति की रिपोर्ट देखें, पैरा 2.12, 2.15 और 2.16)। समिति ने 31 मार्च 1964 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ऊपर निकाले गए संदर्भ के चौथे कार्यकाल की जांच करते हुए, समिति ने अपनी रिपोर्ट की धारा 7 में आई. पी. सी. में संशोधन के प्रश्न पर विचार किया। समिति ने विशेष रूप से 241 अंक जुटाए

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [शेट्टी, जे।]

आई. पी. सी. की धारा 21 में 'लोक सेवक' की परिभाषा पर ध्यान देना।

रिपोर्ट के अनुच्छेद 7 के तहत समिति ने सुझाव दिया है कि

सहायक के रूप में कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों को शामिल करने के लिए श्रेणी जोड़ी जानी चाहिए। तत्काल किसी भी संघ या राज्य कानून के तहत सहायक कार्य

बल '। पैरा 7.7 के तहत समिति ने सिफारिश की कि आई. पी. सी. की धारा 21 के तहत तीसरी श्रेणी में संशोधन किया जा सकता है जैसा कि नीचे कहा गया है:

" तीसरा-प्रत्येक न्यायाधीश, जिसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है, किसी भी प्रवर्तन के दौरान न्यायिक कार्य

उस समय लागू कानून "।

इस सिफारिश के कारण भ्रष्टाचार विरोधी कानून बनाया गया

विधि (संशोधन) अधिनियम 1964 (1964 का अधिनियम सं. 40)। संसद ने इस अधिनियम को पारित करके धारा 21 को तीसरी धारा के साथ पुनः अधिनियमित किया है:

" 21. ' लोक सेवक '-' लोक सेवक 'शब्द का अर्थ है

इसके बाद के किसी भी विवरण के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति

कम करना, अर्थात्;

तीसरा-द्वारा सशक्त किसी भी व्यक्ति सहित प्रत्येक न्यायाधीश

निर्वहन के लिए कानून, चाहे वह स्वयं या किसी के सदस्य के रूप में हो

व्यक्तियों का निकाय, कोई भी न्यायिक कार्य।

यह देखा जाएगा कि संसद ने न केवल आई. पी. सी. की धारा 21 के तहत लोक सेवक की मूल गणना में "प्रत्येक न्यायाधीश" अभिव्यक्ति को बरकरार रखा है, बल्कि किसी भी न्यायिक कार्यों का निर्वहन करने के लिए कानून द्वारा सशक्त किसी भी व्यक्ति को शामिल करने के लिए अभिव्यक्ति का विस्तार किया है। आई. पी. सी. की धारा 19 का भी संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें "न्यायाधीश" को परिभाषित किया गया है। धारा 19 में कहा गया है:

" 19. " जज "-" जज "शब्द का अर्थ न केवल हर व्यक्ति को संदर्भित करता है।

वह व्यक्ति जिसे आधिकारिक तौर पर न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है, लेकिन

प्रत्येक व्यक्ति

जिसे कानून द्वारा किसी भी कानूनी कार्यवाही में देने का अधिकार है,

दीवानी या आपराधिक, एक निश्चित निर्णय, या एक निर्णय

जेकर इसके विरुद्ध अपील नहीं की जाती है तो यह निश्चित होगा, या

निर्णय जिसकी, यदि किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की जाती है,

निश्चित होगा, या 242

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1991] 3 एस. सी. आर.

जो व्यक्तियों के निकाय में से एक है, व्यक्तियों का कौन सा निकाय है  
इस तरह का निर्णय देने के लिए कानून द्वारा सशक्त "।

अभिव्यक्ति "प्रत्येक न्यायाधीश" की तीसरी श्रेणी में उपयोग किया जाता है

धारा 21 सभी न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों और सभी न्यायाधीशों को इंगित करती है। यह एक सामान्य शब्द है और अधिनियम में सामान्य शब्द को संकीर्ण रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। इसे व्यापक अर्थ प्राप्त करना चाहिए जब तक कि इसके विपरीत सकारात्मक संकेत न हो। अधिनियम में इसके विपरीत ऐसा कोई संकेत नहीं है। इसलिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लोक सेवक की परिभाषा से अलग नहीं किया जा सकता है। वह पूरी तरह से अधिनियम के दायरे में आता है बशर्ते धारा 6 (1) के खंड (सी) के तहत दूसरी आवश्यकता पूरी हो।

खंड के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए दूसरी आवश्यकता

(ग) उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश के लिए धारा 6 (1) की धारा यह है कि उसके अभियोजन के लिए मंजूरी देने के उद्देश्य से, एक

प्राधिकारी और प्राधिकारी को न्यायाधीश को हटाने के लिए सक्षम होना चाहिए। यह.

अब उच्च न्यायपालिका के संबंध में ऐसे प्राधिकरण की पहचान करना आवश्यक है। हमारे देश में उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश सुरक्षित और सुरक्षित हैं। वे उच्च गणमान्य व्यक्ति और संवैधानिक पदाधिकारी हैं।

उन्हें राष्ट्रपति द्वारा अपनी कार्यपालिका के अभ्यास में नियुक्त किया जाता है।

वे सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं 62, जबकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। वे होने योग्य हैं

साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के लिए हटा दिया गया। कार्यपालक है

न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए सक्षम लेकिन उन्हें हटाने के लिए सशक्त नहीं।

प्रक्रिया द्वारा उन्हें हटाने की शक्ति संसद में निहित है।

महाभियोग के समान। शक्ति के अनुच्छेद 124 के तहत स्थित है

संविधान। जहाँ तक सामग्री की बात है, अनुच्छेद 124 इस प्रकार प्रदान करता है:

" 124. उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन

XXXXX

XXXXX

XXXXX

( 4 ) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा समर्थित और उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई के बहुमत से राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पारित किया गया हो।

243

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [शेट्टी, जे।]

( 5 ) संसद विधि द्वारा प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है -

न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या अक्षमता का प्रमाण

खंड (4)।

अनुच्छेद 218 में कहा गया है कि संविधान के खंड (4) और (5) के प्रावधान

अनुच्छेद 124 उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होगा जैसा कि वे सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में लागू होते हैं।

अनुच्छेद 124 के खंड (5) के तहत निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए,

संसद ने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 पारित किया है, जिसमें एक पते को प्रस्तुत करने और एक न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच और सबूत के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है। न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करना उपयोगी होगा। धारा 3 (1) में किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना करते हुए राष्ट्रपति को एक अभिभाषण प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्ताव की सूचना देने का प्रावधान है, (ए) लोक सभा में दिए गए प्रस्ताव की सूचना के मामले में, उस सदन के कम से कम एक सौ

सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए; (बी) राज्य परिषद में दी गई सूचना के मामले में, उस परिषद के कम से कम पचास सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। प्रस्ताव की सूचना अध्यक्ष को या, जैसा भी मामला हो, अध्यक्ष को दी जानी चाहिए, जो ऐसे व्यक्तियों से परामर्श करने के बाद, जैसा वह उचित समझे, और उसके बाद ऐसी सामग्री, यदि कोई हो, जो उसके पास उपलब्ध हो, पर विचार करते हुए या तो प्रस्ताव स्वीकार करें या उसे स्वीकार करने से इनकार कर दें। धारा 3 (2) में कहा गया है कि यदि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो अध्यक्ष या, जैसा भी मामला हो, अध्यक्ष एक समिति का गठन करेगा।

उन आधारों की जाँच करना जिनके आधार पर न्यायाधीश को हटाने का अनुरोध किया जाता है। समिति के तीन सदस्य होंगे; जिनमें से एक का चयन मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किया जाएगा; एक का चयन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों में से किया जाएगा और एक व्यक्ति वह होगा जो उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों में से एक है। अध्यक्ष या, यथास्थिति, अध्यक्ष, एक प्रतिष्ठित न्यायविद की राय। इस धारा में आगे यह प्रावधान किया गया है कि समिति न्यायाधीश के खिलाफ निश्चित आरोप बनाएगी जिसके आधार पर जाँच करने का प्रस्ताव है और न्यायाधीश को बचाव का लिखित बयान प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिया जाएगा। न्यायाधीश (पूछताछ) अधिनियम के तहत गठित न्यायाधीश (जाँच) नियम, 1969 नामक नियम हैं जो न्यायाधीश के खिलाफ जाँच करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 की धारा 4 (1) में कहा गया है कि जाँच के समापन पर समिति प्रस्तुत करेगी।

अध्यक्ष को या, यथास्थिति, अध्यक्ष को उसका प्रतिवेदन, जिसमें प्रत्येक आरोप पर अपने निष्कर्षों को अलग-अलग बताते हुए, पूरे मामले पर ऐसी टिप्पणियों के साथ जो वह उचित समझता है। स्पीकर या 244

[ 1991 ] 3 एस सी आर।

#### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, उस रिपोर्ट को लोक सभा और राज्य परिषद के समक्ष रखने का कारण बनेंगे। धारा 6 में प्रावधान है कि यदि समिति की रिपोर्ट में यह निष्कर्ष है कि न्यायाधीश किसी दुर्व्यवहार का दोषी नहीं है या किसी असमर्थता से पीड़ित नहीं है, तो संसद के किसी भी सदन में आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।

धारा 6 (2) में कहा गया है कि यदि समिति की रिपोर्ट में एक

यह पाते हुए कि न्यायाधीश किसी भी दुर्व्यवहार का दोषी है या किसी असमर्थता से पीड़ित है, संसद का प्रत्येक सदन आगे के कदम उठाएगा। समिति की रिपोर्ट के साथ राष्ट्रपति को संबोधित करने का प्रस्ताव उस सदन द्वारा विचार के लिए लिया जाएगा जिसमें यह लंबित है। वह पता हटाने के लिए प्रार्थना कर रहा है

न्यायाधीश को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अनुच्छेद 124 के खंड (4) के प्रावधानों के अनुसार अपनाया जाना चाहिए। अनुच्छेद 124 के खंड (4) में प्रावधान है कि अभिभाषण को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा पारित किया जाना चाहिए।

उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई के बहुमत द्वारा समर्थित। इसके बाद इसे प्रस्तुत किया जाएगा

न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति। संयोग से, यह उल्लेख किया जा सकता है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए भी यही प्रक्रिया लागू की गई है। ( अनुच्छेद 148 का खंड (1) और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए देखें। ( खंड देखें

( 5 ) संविधान का अनुच्छेद 324।

उपरोक्त का उल्लेख करते हुए अपीलार्थी के लिए वकील

संविधान के प्रावधानों में कहा गया है कि किसी न्यायाधीश को हटाने की शक्ति किसी एक व्यक्ति या प्राधिकरण में निहित नहीं है। कोई भी व्यक्ति या प्राधिकारी किसी न्यायाधीश के कदाचार के किसी भी आरोप का संज्ञान लेने या उसके लिए कानूनी कार्रवाई करने के लिए सक्षम नहीं है।

निकालना। न्यायाधीश को हटाने की शक्ति संसद के दोनों सदनों और राष्ट्रपति के पास निहित है। प्रक्रिया और शक्ति दोनों हैं संसद और संसद में एकीकृत अकेले एक न्यायाधीश को हटाने के लिए सक्षम है। लेकिन वकील ने तर्क दिया कि संसद किसी न्यायाधीश के अभियोजन के लिए मंजूरी देने वाला प्राधिकरण नहीं हो सकती है। मंजूरी देने के लिए जांच एजेंसी द्वारा एक्टर की गई सामग्री पर विचार करने की आवश्यकता होती है और संसद सामग्री पर ठीक से विचार नहीं कर सकती है। पार्लियामेंट उस काम के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त है। यह उचित होगा कि

यह मानते हुए कि विधानमंडल अधिनियम की धारा 6 (1) के खंड (सी) को अधिनियमित करते समय संसद को मंजूरी देने वाला प्राधिकरण नहीं बना सकता था। अन्य प्राधिकारी को न्यायाधीश के अभियोजन के लिए मंजूरी देने में शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह

अधिनियम के प्रावधानों और संवैधानिक आवश्यकताओं के साथ असंगत होगा। वकील ने जोर देकर कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और 245 के न्यायाधीशों को बाहर करना आवश्यक है।

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई. (शेट्टी, जे।)

अधिनियम के संचालन से उच्च न्यायालय।

श्री तुलसी, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, दूसरी ओर

हाथ, हटाने के संबंध में राष्ट्रपति की भूमिका पर जोर दिया

एक न्यायाधीश। उन्होंने बताया कि हटाने के लिए राष्ट्रपति का आदेश संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (4) के तहत एक न्यायाधीश अनिवार्य है।

खंड (ग) के तहत राष्ट्रपति और राष्ट्रपति उचित प्राधिकारी हो सकते हैं। अधिनियम की धारा 6 (1)।

तो फिर, बहुत जल्दी में, इस तरह के विवादों को संबोधित किया गया था

अभियोजन के लिए मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी पर उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीश।

हम अपीलार्थी के वकील से सहमत हैं कि संसद कर सकती है

खंड के तहत मंजूरी देने वाला प्राधिकारी होने का इरादा नहीं है (ग) धारा 6 (1)। संसद की संरचना जिसमें

राष्ट्रपति और दो सदन (अनुच्छेद 79) इसे कार्य के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं।

प्रत्येक सदन में लेन-देन या कार्यवाही की प्रकृति

उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के आचरण के लिए प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को छोड़कर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में

न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रार्थना करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित करना

इसके बाद प्रदान किया गया है "। संविधान में एकमात्र अपवाद बनाया गया है न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा के लिए प्रस्ताव तब लिया जाता है जब

उसे हटाने के लिए। किसी अन्य अवसर पर किसी न्यायाधीश का आचरण  
कर्तव्यों का निर्वहन दोनों में चर्चा का विषय हो सकता है।

संसद के सदन। बिना चर्चा के, यह मुश्किल होगा

अनुदान के संबंध में वस्तुनिष्ठ निर्णय लेने का दावा

अभियोजन के लिए मंजूरी। इसलिए संसद उचित नहीं हो सकती है। न्यायाधीश के  
अभियोजन के लिए मंजूरी देने के लिए प्राधिकरण।

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश  
अधिनियम के दायरे से बाहर किए जाने के हकदार हैं जैसा कि तर्क दिया गया है  
अपीलार्थी। यह अधिनियम के उद्देश्य को विफल करना होगा। अधिनियम  
इसका उद्देश्य लोक सेवकों की सभी श्रेणियों को शामिल करना था। जाहिर है कि  
कानून की नीति एक स्वच्छ लोक प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए है  
भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर निकालना। अधिनियम की प्रस्तावना इंगित करती है कि  
अधिनियम का उद्देश्य रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को अधिक प्रभावी ढंग से रोकना था  
लोक सेवकों द्वारा विघटन। इस न्यायालय के पास जाँच करने का अवसर है  
अधिनियम की व्यापक रूपरेखा। इमाम। जे., एस. ए. वेंकटरमन बनाम।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1991] 3 एस. सी. आर.

246

राज्य, [1958] एस. सी. आर. 1040 ने अधिनियम के प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए  
(1048 पर) कहा: कि अधिनियम के प्रावधानों से संकेत मिलता है कि विधायिका का इरादा एक  
लोक सेवक की ओर से अब तक के भ्रष्टाचार से अधिक गंभीर व्यवहार करना था और इसे किसी  
भी तरह से माफ नहीं करना था। सुब्बा राव की टिप्पणियों का भी संदर्भ दिया जा सकता है। जे.,  
जैसा कि वे तब थे, एम. नारायणन बनाम में। केरल राज्य, [1963] 2 पूरक। एससीआर 724।  
विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि यह अधिनियम जनहित में परिकल्पित एक सामाजिक रूप से

उपयोगी उपाय है और इसे उदारता से परिभाषित किया जाना चाहिए। उनके अपने शब्दों को उद्धृत करने के लिए (729 पर):

" प्रस्तावना इंगित करती है कि अधिनियम को पारित किया गया था क्योंकि रिश्वत और भ्रष्टाचार के पूर्व उल्लेख के लिए अधिक प्रभावी प्रावधान करना समीचीन था। लंबे शीर्षक के साथ-साथ प्रस्तावना से संकेत मिलता है कि उक्त सामाजिक बुराई यानी लोक सेवक द्वारा रिश्वत और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए अधिनियम पारित किया गया था। रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार का एक रूप है। तथ्य यह है कि 'रिश्वतखोरी' शब्द के अलावा 'भ्रष्टाचार' शब्द का उपयोग किया जाता है, यह दर्शाता है कि इस कानून का उद्देश्य इससे भी लड़ना था रिश्वतखोरी के अतिरिक्त अन्य बुराइयाँ। मौजूदा कानून। अर्थात् दंड संहिता को हमारे देश की सार्वजनिक सेवा को बाधित करने वाली रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की बढ़ती बुराई को मिटाने या नियंत्रित करने के लिए अपर्याप्त पाया गया। प्रावधानों में मोटे तौर पर एस. एस. के तहत मौजूदा अपराध शामिल हैं। 161 और लोक सेवकों द्वारा की गई भारतीय दंड संहिता की धारा 165 और अभियुक्त के खिलाफ अनुमानित साक्ष्य का एक नया नियम अधिनियमित किया। यह अधिनियम लोक सेवकों द्वारा आपराधिक दुराचार का एक नया अपराध भी पैदा करता है, हालांकि कुछ हद तक यह पूर्व-मौजूदा अपराधों पर ओवरलैप करता है और आपराधिक न्यायशास्त्र के प्रसिद्ध सिद्धांतों के विपरीत एक खंडन योग्य धारणा को लागू करता है। इसका उद्देश्य यह निर्धारित करके ईमानदार लोक सेवकों को उत्पीड़न से बचाना भी है कि उनके खिलाफ जांच केवल विशेष दर्जे के पुलिस अधिकारियों द्वारा की जा सकती है और उनके अभियोजन के लिए सरकार या अन्य उपयुक्त अधिकारी की मंजूरी को पूर्व शर्त बनाना है। चूंकि यह जनहित में परिकल्पित एक सामाजिक रूप से उपयोगी उपाय है, इसलिए इसका उदारतापूर्वक अर्थ लगाया जाना चाहिए ताकि वांछित उद्देश्य यानी लोक सेवकों के बीच टकराव को रोका जा सके और उत्पीड़न को रोका जा सके।

उनमें से ईमानदार। '

इन क्रेज़ ऑन स्टैच्यू लॉ, (छूटा संस्करण। पी। 531) यह कहा गया है कि "एक सख्त और एक उदार निर्माण के बीच का अंतर लगभग समाप्त हो गया है। विधियों के सभी वर्गों के संबंध में, ताकि सभी विधियां, 247

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [शेड्टी, जे।]

दंडात्मक है या नहीं, अब काफी हद तक समान रूप से समझा जाता है

नियम। इनका अब सही अर्थ के संदर्भ में अर्थ लगाया जाता है।

और विधानमंडल का वास्तविक इरादा "। निर्माण जो होगा

प्रावधान में अंतर्निहित सामान्य विधायी उद्देश्य को बढ़ावा देना

प्रश्न, एक ऐसे निर्माण की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो नहीं होगा। अगर

निर्माण जो विधायिका के उद्देश्य को प्रभावित करता है। धारा 6, के साथ जिसे लेकर हम वास्तव में चिंतित हैं, उसे उदारता से समझने की आवश्यकता है। यह है।

दंडात्मक प्रावधान नहीं बल्कि लोक सेवकों के लिए सुरक्षा का एक उपाय

दंडात्मक अधिनियम। यह उन अधिकारियों को इंगित करता है जिनके बिना सैनिक

एक लोक सेवक पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यह पर्याप्त है कि इसके तहत निर्धारित अधिकारी उचित अर्थ में आते हैं

खंड की भाषा। अभिव्यक्ति "सक्षम प्राधिकारी धारा 6 (1) के खंड (सी) में उपयोग किए गए "हटाने" का अर्थ लगाया जाना है

एक प्राधिकरण भी जिसके आदेश या पुष्टि के बिना लोक सेवक इसे हटाया नहीं जा सकता। इस दृष्टिकोण से, राष्ट्रपति के रूप में माना जा सकता है

न्यायाधीश के अभियोजन के लिए मंजूरी देने का अधिकार

न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति का आदेश अनिवार्य है। द.

संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष प्रक्रिया के साथ पारित प्रस्ताव

अनुच्छेद 124 के खंड (4) के तहत निर्धारित उचित नहीं होगा।

न्यायाधीश के खिलाफ कार्य करें। इसे हटाने का कोई परिणाम नहीं होगा।

न्यायाधीश को कार्यालय से निकालना जब तक कि उसके आदेश का पालन न किया जाए राष्ट्रपति।

एक को हटाने के लिए राष्ट्रपति के आदेश का महत्व

न्यायाधीश को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अध्यक्ष को हटाने के प्रावधानों के साथ अनुच्छेद 124 के खंड (4) के प्रावधानों की तुलना करके देखा जा सकता है। अनुच्छेद 61 भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया प्रदान करता है। अनुच्छेद 61 का खंड (4) इस प्रकार है:

" 61 ( 4 ) यदि जाँच के परिणामस्वरूप एक संकल्प है

कुल के कम से कम दो-तिहाई के बहुमत से पारित  
सदन की सदस्यता जिसके द्वारा प्रभार था

राष्ट्रपति के खिलाफ लगाए गए आरोप को कायम रखा गया है,  
इस तरह के प्रस्ताव का राष्ट्रपति को हटाने का प्रभाव होगा।

जिस तारीख को निर्णय लिया गया है, उस तारीख से अपने कार्यालय से बाहर  
निकल जाना

यह इस तरह से पारित हो गया है "।

हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करने का परिणाम भी ऐसा ही है

अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति और अनुच्छेद [1991] 3 एस. सी. आर. के तहत अध्यक्ष।

248

#### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

94 संविधान से। संविधान के अनुच्छेद 67 (बी) में प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति को परिषद के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित और लोक सभा द्वारा सहमत राज्य परिषद के प्रस्ताव द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 94 (सी) में कहा गया है कि सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित लोक सभा के प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष को उनके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अध्यक्ष को हटाने के लिए संबंधित प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पारित प्रस्ताव वास्तव में काम करेगा।

उन अधिकारियों के खिलाफ। उन्हें हटाने के लिए किसी अन्य प्राधिकरण से आगे किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है।

लेकिन न्यायाधीश को हटाने के मामले में यह स्थिति नहीं है।

अनुच्छेद 124 के खंड (4) में कहा गया है कि "एक न्यायाधीश को उसके पद से संसद के प्रत्येक सदन द्वारा एक संबोधन के बाद पारित राष्ट्रपति के आदेश के अलावा नहीं हटाया

जाएगा।" खंड (4) नकारात्मक शब्दों में है। न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति का आदेश अनिवार्य है। यह आदेश केवल राष्ट्रपति ही दे सकते थे।

यह कहा जाता है कि धारा 6 में परिकल्पना की गई है कि सक्षम प्राधिकारी

एक लोक सेवक को कार्यालय से हटा देना उस पदानुक्रम में ऊर्ध्वाधर रूप से श्रेष्ठ होना चाहिए जिसमें कार्यालय मौजूद है। धारा 6 केवल उन मामलों में लागू होती है जहां सार्वजनिक कार्यालयों और लोक सेवकों का एक ऊर्ध्वाधर पदानुक्रम है जिनके खिलाफ मंजूरी देने वाले अधिकारी से मंजूरी मांगी जाती है। जहां लोक सेवक द्वारा आयोजित पद ऊर्ध्वाधर पदानुक्रम का हिस्सा नहीं है जिसमें लोक सेवक से ऊपर कोई अधिकार है, तो धारा 6 का कोई अनुप्रयोग नहीं हो सकता है। आर. एस. नायक बनाम में हमें जे. देसाई के आक्षेपों का उल्लेख किया गया है। ए. आर. अंतुले, [1984] 2 एस. सी. सी. 183 206:

" केवल वही सक्षम प्राधिकारी प्रकृति को जानेगा।

और लोक सेवक द्वारा निर्वहन किया गया कार्य

सक्षम प्राधिकारी के बीच ऊर्ध्वाधर पदानुक्रम है

लोक सेवक को उस कार्यालय से हटाने और

लोक सेवक द्वारा धारण किए गए पद की प्रकृति जिसके विरुद्ध

मंजूरी मांगी जाती है जो एक पदानुक्रम को इंगित करेगी और

इसलिए जो ज्ञान के निष्कर्ष की अनुमति देगा

मंजूरी देने के लिए तम्बू जो जनता को हटाने का हकदार है

वह सेवक जिसके खिलाफ कार्यालय से मंजूरी मांगी जाती है। "249

के. वीरस्वामी बनाम। यू. ओ. आई. [शेट्टी, जे।]

अत्यंत सम्मान के साथ; हम उपरोक्त से सहमत होने में असमर्थ हैं।

अवलोकन। हमें ऐसा लगता है कि इन टिप्पणियों का उद्देश्य इस कानून को निर्धारित करना नहीं था कि लोक सेवक के अभियोजन के लिए मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी को पदानुक्रम में ऊर्ध्वाधर रूप से श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि लोक सेवक का पद मौजूद है। उस मामले में यह मुद्दा नहीं था। अतः टिप्पणियों को कानून निर्धारित करने के लिए नहीं माना जाना चाहिए और न

ही माना जाना चाहिए। यह लगभग बहुत बार कहा गया है कि इस बात को दोहराने की आवश्यकता है कि निर्णयों को कानून के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। हमारी राय में, यह आवश्यक नहीं है कि अभियोजन के लिए मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी या लोक सेवक को हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी उस पदानुक्रम में ऊर्ध्वाधर रूप से श्रेष्ठ होना चाहिए जिसमें लोक सेवक का पद मौजूद है। धारा 6 के तहत ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। अभियोजन के लिए मंजूरी देने की शक्ति किसी भी प्राधिकारी को प्रदान की जा सकती है। ऐसा प्राधिकरण उस विभाग का हो सकता है जिसमें लोक सेवक काम कर रहा है या कोई बाहरी प्राधिकरण हो सकता है। बस इतना ही आवश्यक है कि प्राधिकरण को लोक सेवक के खिलाफ एकत्र की गई सामग्री की सराहना करने की स्थिति में होना चाहिए ताकि यह तय किया जा सके कि विचाराधीन अभियोजन तुच्छ है या अटकलबाजी है। हमारे अधिनियम के तहत लोक सेवक को हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी को शक्ति प्रदान की गई है। ब्रिटिश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1906 के तहत उस अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए अभियोजन के लिए सहमति देने की शक्ति महान्यायवादी या महान्यायवादी को प्रदान की गई है।

जहाँ तक न्यायपालिका का संबंध है, राष्ट्रपति बाहरी व्यक्ति नहीं हैं।

राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 217 के खंड (1) में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, न ही राज्य सरकार और मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की जाएगी। इसी तरह राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 124 के खंड (2) में प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श से की जाएगी जो राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझें और मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की स्थिति में, भारत के मुख्य न्यायाधीश को हमेशा नियुक्त किया जाएगा। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से इस शक्ति का प्रयोग करते हैं।

शमशेर सिंह बनाम। पंजाब राज्य, [1975] 1 एस. सी. आर. 814 और एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ, [1982] 2 एस. सी. आर. 365। न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में संसद की कोई भूमिका नहीं है सिवाय इसके कि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1991] 3 एस. सी. आर.

राष्ट्रपति के न्यायाधीश के अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में माने जाने की स्थिति में,

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। कार्यपालिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप करके शक्ति का दुरुपयोग कर सकती है। न्यायालय ऐसी व्याख्या से बचेगा जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित होने की संभावना है। वकील ने आग्रह किया कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आपराधिक कदाचार से निपटने के लिए एक अलग संसदीय कानून बनाया जा सकता है जो उन्हें हटाने के लिए संवैधानिक योजना के अनुरूप है और केवल ऐसा कानून न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा न कि वर्तमान अधिनियम। एक सुझाव यह भी दिया गया कि चूंकि संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (4) के तहत 'दुर्व्यवहार' और अधिनियम की धारा 5 (1) के तहत 'आपराधिक कदाचार' समानार्थी है, इसलिए इसे हटाने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया

न्यायाधीश को पहले देखा जाना चाहिए और उसके हटाने के बाद ही प्रो

यदि आवश्यकता हो तो उसी प्रक्रिया में सेक्यूशन की सिफारिश की जाती है। अन्यथा, यह कहा जाता है कि इससे विसंगति पैदा होगी क्योंकि संविधान या किसी अन्य अधिनियम के तहत न्यायाधीश को निलंबित करने या न्यायाधीश को आपराधिक न्यायालय में उसके मुकदमे या दोषसिद्धि तक काम सौंपने से इनकार करने की कोई शक्ति नहीं है और न्यायाधीश अपनी दोषसिद्धि और सजा के बाद भी उसे हटाए जाने तक बने रहने के अपने अधिकार पर जोर दे सकता है।

यह कहना अनुचित है कि दोषसिद्धि और सजा नहीं है।

न्यायाधीश के न्यायालय में बैठने पर रोक। हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि यदि कोई न्यायाधीश आपराधिक दुराचार या नैतिक अधमता से जुड़े किसी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो उसके लिए खुद को न्यायालय से दूर रखना उचित है। उसे स्वेच्छा से न्यायिक कार्य से हट जाना चाहिए और आपराधिक अभियोजन के परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि उसे किसी आपराधिक मामले में सजा सुनाई जाती है तो उसे तुरंत अपना इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक कि वह अपनी दोषसिद्धि और सजा पर रोक नहीं लगा लेता। वह तब तक पीठ में बैठने के अपने अधिकार पर जोर नहीं देगा जब तक कि वह सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा आरोप से मुक्त नहीं हो जाता। न्यायपालिका के पास पर्स या तलवार की कोई शक्ति नहीं है। यह केवल जनता के विश्वास से जीवित रहता है और समाज की स्थिरता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि समाज का विश्वास

जनता हिलती नहीं है। वह न्यायाधीश जिसका चरित्र अस्पष्ट है और जिसके नैतिकता और ईमानदारी के मानकों पर संदेह है, उसे न्यायिक स्वतंत्रता नहीं हो सकती है और वह जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकता है। उसे स्वेच्छा से न्यायिक कार्य और प्रशासन से हट जाना चाहिए।

इस बिंदु पर जोर देना अनावश्यक नहीं लगना चाहिए। प्रो. जैक्सन का कहना है कि "एक न्यायाधीश द्वारा दुर्व्यवहार, चाहे वह बेंच पर हो या बेंच के बाहर, न्याय के प्रशासनिक अनुपात में जनता के विश्वास को कम करता है, और 251 के कानून के लिए सार्वजनिक सम्मान को भी नुकसान पहुंचाता है।

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई. {शेट्टी, जे.]

भूमि; यदि इसके बारे में कुछ भी नहीं किया जाता है, तो नुकसान बिना जोड़े चला जाता है। ऐसा तब होना चाहिए जब न्यायाधीश एक गंभीर आपराधिक अपराध करता है और पद पर रहता है। (जे. आर. स्पेंसर द्वारा जैक्सन की मशीनरी ऑफ जस्टिस 8 वां संस्करण। पी. पी 369-370)।

सिद्ध "दुर्व्यवहार" जो एक को हटाने का आधार है

संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (4) के तहत न्यायाधीश कुछ मामलों में अधिनियम की धारा 5 (1) के तहत आपराधिक दुराचार का अपराध भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन जब तक अपीलार्थी के वकील द्वारा सुझाए गए न्यायाधीश को संसद द्वारा हटा नहीं दिया जाता है, तब तक आपराधिक प्रतिभूति को रोकने का कोई आधार नहीं है। एक संसद की शक्ति है और दूसरा आपराधिक न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है। दोनों एक-दूसरे से अलग हैं। यहां तक कि एक सरकारी कर्मचारी जो अपने कदाचार के लिए जवाबदेह है जो आई. पी. सी. के तहत या अधिनियम की धारा 5 के तहत एक अपराध भी हो सकता है, उस पर विभागीय जांच के अलावा मुकदमा चलाया जा सकता है। यदि आपराधिक अदालत में मुकदमा चलाया जाता है तो उसे कारावास या जुर्माने या दोनों के रूप में दंडित किया जा सकता है, लेकिन विभागीय जांच में, उस पर लगाया जा सकने वाला सबसे बड़ा दंड बर्खास्तगी है। कोपे टेंट प्राधिकरण या तो अभियोजन पक्ष को न्यायालय में चलने की अनुमति दे सकता है या उसे विभागीय जांच के अधीन कर सकता है या उसे समवर्ती या लगातार दोनों के अधीन कर सकता है। अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को समाप्त करने से पहले लोक सेवक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करना आपत्तिजनक नहीं

है, और इसलिए, एक न्यायाधीश पर आपराधिक कदाचार के लिए मुकदमा चलाना, संसद द्वारा उसे हटाने से पहले, गलत साबित होने के लिए, आपत्तिजनक नहीं है।

न्यायाधीशों को संरक्षित करने के लिए विभिन्न सुरक्षा प्रदान की जाती हैं

न्यायपालिका की स्वतंत्रता। उन्हें अपने न्यायिक कर्तव्य के निर्वहन में उनके द्वारा किए गए या करने का आदेश दिए गए किसी भी कार्य के लिए नागरिक दायित्व से सुरक्षा प्राप्त है, चाहे ऐसा न्यायिक कर्तव्य उनके अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किया गया हो या नहीं। यह न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850 की धारा 1 के तहत प्रदान किया गया है। इसी तरह, आई. पी. सी. की धारा 77 उन्हें न्यायिक कार्य के लिए आपराधिक दायित्व से सुरक्षा प्रदान करती है।

सीली। धारा 77 में कहा गया है कि "कुछ भी अपराध नहीं है जो एक न्यायाधीश द्वारा किसी भी शक्ति के प्रयोग में न्यायिक रूप से कार्य करते समय किया जाता है, जो उसे कानून द्वारा दी गई है, या जिसे वह सद्भावना से मानता है"। अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा राज्य विधानमंडलों या संसद में नहीं होगी (अनुच्छेद 121 और 211)। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय का गठन अभिलेख न्यायालयों के रूप में किया गया है जिनके पास अवमानना करने के लिए किसी को भी दंडित करने की शक्ति है। (अनुच्छेद 129 और 215)। न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (अधिनियम 70-71) न्यायालय को दीवानी और आपराधिक अवमानना कार्यवाही करने की शक्ति प्रदान करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1991] 3 एस. सी. आर.

252

लेकिन हम न्यायाधीशों को आपराधिक मामलों से सुरक्षा प्रदान करने के बारे में नहीं जानते हैं।

अभियोजन। अनुच्छेद 361 (2) आपराधिक अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। केवल राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के लिए और किसी अन्य के लिए नहीं।

यहां तक कि उनके कार्यकाल के दौरान प्रतिरक्षा भी सीमित रही है। द.

न्यायाधीशों के साथ उसी तरह व्यवहार किया जाना चाहिए जैसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ किया जाता है।

आपराधिक अपराध के संबंध में। यह केवल रिश्वत लेने में या उसके साथ है।

भ्रष्टाचार के अपराध के संबंध में आपराधिक अभियोजन के लिए मंजूरी यह आवश्यक है।

अन्य देशों में स्थिति अलग नहीं लगती है। में

एस. की पुस्तक "न्यायिक स्वतंत्रता-समकालीन बहस"।

शेड्रीट और जे. डेसचेनेस (1985 संस्करण) माउरो कैपेलेट्टी द्वारा "हू वॉचेस द वॉचमैन" शीर्षक से एक लेख है। लेखक ने कहा है

कुछ की कानूनी प्रणालियों में न्यायाधीशों के दंडात्मक दायित्व का सर्वेक्षण किया देशों को। लेखक का कहना है कि "कई राष्ट्रीय प्रणालियों में एक

कुछ कृत्यों के लिए आपराधिक प्रतिबंधों का प्रावधान भी पा सकते हैं या चूक जो केवल न्याय प्रशासन के लिए विशिष्ट हैं, जैसे कि

न्याय से इनकार, या न्यायिक कार्यालय का जानबूझकर दुरुपयोग। यहाँ तक कि अपराध जो अधिक सामान्य अनुपयोग के हैं, जैसे कि रिश्वत लेना, हो सकता है

अलग तरह से स्वीकृत किया जाए-लेकिन संभवतः अधिक गंभीर रूप से-जब

वे न्यायिक अधिकारियों को संदर्भित करते हैं। अन्य देशों में, जैसे कि

पोलैंड, ग्रीस और इटली, एक अलग दृष्टिकोण प्रचलित है। वहाँ कोई नहीं है

आपराधिक मंजूरी जो विशेष रूप से केवल न्यायिक मामलों पर लागू होती है

व्यवहार; बल्कि, न्यायाधीश उन आपराधिक प्रावधानों में शामिल हैं।

कार्यालय, वेक्सा की गतिविधियों को करने के लिए भ्रष्टाचार, चूक या इनकार इत्यादि। "

अगर हम प्रारंभिक अंग्रेजी कानून को लेते हैं तो यह देखा जाएगा कि भ्रष्टाचार

एक न्यायाधीश की ओर से सबसे निंदनीय अपराध और सजा थी उच्च राजद्रोह के रूप में सक्षम। यहाँ तक कि लॉर्ड बेकन, सबसे प्रतिभाशाली दिमाग

अंग्रेजी पुनर्जागरण, प्रशंसित दार्शनिक और सर्वश्रेष्ठ कानूनी मस्तिष्क

रिश्वत लेने की सजा से नहीं बरखा गया। उन पर जुर्माना लगाया गया। चालीस हजार पाउंड, एक विशाल राशि, और "कैद में

राजा की खुशी के दौरान मीनार "। उन्हें भी हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था "राज्य या राष्ट्रमंडल" में कोई पद धारण करना या उसमें बैठना संसद, या "न्यायालय के कगार के भीतर" आने से। राजा। हालाँकि, जेम्स ने उसे जेल से मुक्त कर दिया, उसका जुर्माना माफ कर दिया, और उसे पूरी तरह से क्षमा करें (जोसेफ बोरकिन द्वारा द करप्ट जज 1962 संस्करण। पी। 3 , 4. & 17 ) .

हालांकि इस बात की आशंका है कि कार्यपालिका

सबसे बड़े वादी द्वारा न्यायाधीशों पर मुकदमा चलाने की शक्ति का दुरुपयोग किए जाने की संभावना है।

253

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [शेट्टी, जे।]

हमारे अति-मुकदमेबाजी वाले समाज में यह आशंका प्रतीत नहीं होती है

अनुचित या निराधार। इस अधिनियम में कोई संदेह नहीं है कि कुछ सुरक्षा प्रदान करता है।

पहरेदार। धारा 6 सक्षम व्यक्ति से पूर्व मंजूरी प्रदान करती है।

प्राधिकरण और निर्देश देते हुए कि कोई भी अदालत इसका संज्ञान नहीं लेगी

स्थापित कानून कि मंजूरी देने के लिए हकदार प्राधिकरण को इसे लागू करना चाहिए मामले के तथ्यों और उससे पहले एकत्र किए गए सभी सबूतों पर ध्यान दें।

एक राय बनाना कि मंजूरी देनी है या नहीं। दूसरा,

यदि सी. बी. आई. द्वारा इसकी जाँच का प्रचार किया जाता है, तो इसका न्यायाधीश और वादी जनता पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। अतः आवश्यकता यह है कि अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का विवेकपूर्ण उपयोग। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ईमानदार और निडर न्यायाधीशों को परेशान न किया जाए। उनकी रक्षा की जानी चाहिए।

तत्काल मामले में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया गया था कि

अपनी राय दें कि क्या अपीलार्थी को इसके तहत आगे बढ़ाया जा सकता है एक्ट करें। मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने विचार व्यक्त करने के बाद ही अपीलार्थी पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है, मामला हर मामले में। लेकिन अपीलार्थी के वकील को आपत्ति है। वह. उन्होंने कहा कि यह राज्य के लिए होगा कि वह एक के साथ आगे आए

न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप न्यायाधीशों के लिए अलग अधिनियम और दोषपूर्ण कानून में सुधार के लिए इस न्यायालय के लिए नहीं। हमारी राय में, न्यायाधीशों के लिए एक अलग कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। यह अधिनियम न्यायपालिका में लागू करने में मूल रूप से दोषपूर्ण नहीं है। बस कुछ दिशानिर्देश निर्धारित करने की आवश्यकता है ताकि अधिनियम का दुरुपयोग न हो। यह न्यायालय लोगों के अधिकारों और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अंतिम संरक्षक होने के नाते इस तरह के दिशानिर्देशों को निर्धारित करने के अवसर से खुद को वंचित नहीं करेगा। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह न्यायालय केवल विवाद निपटान का सीमित क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय नहीं है। लगभग शुरुआत से ही, यह न्यायालय एक कानून निर्माता रहा है, हालांकि, होम्स की अभिव्यक्ति में। अंतरालीय कानून निर्माता'। वास्तव में, आज अदालत की भूमिका बहुत अधिक है। यह विवाद निपटान और अंतरालीय कानून बनाने से परे विस्तार कर रहा है। यह अस्पष्ट क्षेत्रों में एक समस्या समाधानक है। इस मामले में, हम इसे केवल अवसर नहीं मानते हैं: यह एक कर्तव्य है। यह हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि हम मौजूदा कानून को न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए अधिक अनुकूल रूप में लागू करें।

भारत के मुख्य न्यायाधीश 254 में एक सहभागी पदाधिकारी हैं।

[ 1991 ] 3 एस सी आर।

#### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला। ( अनुच्छेद 124 (2) और 217 (1)। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए भी मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाना चाहिए।

भारत के राष्ट्रपति (अनुच्छेद 222)। यदि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठाया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (अनुच्छेद 217 (3)) के परामर्श के बाद प्रश्न का निर्णय लिया जाएगा। दूसरा, मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका का प्रमुख होने के नाते मुख्य रूप से न्यायपालिका की अखंडता और निष्पक्षता से संबंधित है। इसलिए यह आवश्यक है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को किसी न्यायाधीश के खिलाफ विचार किए गए किसी भी अपराधिक मामले की तस्वीर से बाहर नहीं रखा जाए। वह मामले में अपनी राय देने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे और भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श से सरकार को सही निष्कर्ष पर पहुंचने में बहुत मदद मिलेगी। इसलिए हम निर्देश देते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत कोई अपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। पी. सी. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ जब तक कि इस मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श नहीं किया जाता है। सरकार द्वारा मुख्य न्यायाधीश द्वारा व्यक्त राय को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। यदि मुख्य न्यायाधीश की राय है कि यह अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए उपयुक्त मामला नहीं है, तो मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश स्वयं वह व्यक्ति है जिसके खिलाफ अपराधिक दुराचार के आरोप प्राप्त होते हैं तो सरकार सर्वोच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों से परामर्श करेगी। प्रश्नों की जांच के चरण में इसी तरह का परामर्श होगा।

अभियोजन के लिए मंजूरी देना और यह आवश्यक और उचित होगा कि मंजूरी का प्रश्न भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से निर्देशित हो। तदनुसार निर्देश सरकार के पास जाएंगे। हमारी राय में, ये निर्देश सभी संबंधित लोगों की इस आशंका को दूर करेंगे कि कार्यपालिका द्वारा संपार्श्विक उद्देश्य के लिए अधिनियम का दुरुपयोग किए जाने की संभावना है।

जिन कारणों से हमने रूपरेखा तैयार करने का प्रयास किया है और

जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, हम मानते हैं कि अधिनियम की धारा 6 (1) के खंड (सी) के उद्देश्य के लिए भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी देने का अधिकार है।

इस भाग में केवल एक छोटे से बिंदु से निपटना बाकी है

चर्चा करें। उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया है कि धारा 6 के तहत अपीलार्थी पर मुकदमा चलाने के लिए कोई मंजूरी आवश्यक नहीं है क्योंकि वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है और आरोप पत्र दाखिल करने की तारीख को लोक सेवक नहीं था। उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अनुपलब्ध प्रतीत होता है। धारा 6 के दायरे पर सबसे पहले इस न्यायालय द्वारा एस. ए. वेंकटरमण के 255 में विचार किया गया था।

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [शेट्टी, जे।]

मामला, जहां यह देखा गया था (1048 में) कि अधिनियम की धारा 6 पर किसी भी निर्माण की धारा में उपयोग किए गए शब्दों के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 में उपयोग किए गए शब्दों पर निर्णयों द्वारा रखे गए हो सकते हैं। पी. सी. न्यायालय ने धारा की शर्तों का विश्लेषण करने के बाद (1049 में) आगे कहा कि "धारा 6 (1) में उपयोग किए गए शब्दों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दूर से भी सुझाव दे कि अदालत द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में उसमें उल्लिखित अपराधों का संज्ञान लेने से पहले पूर्व मंजूरी आवश्यक थी, जो उस समय लोक सेवक नहीं रह गया था जब अदालत को संज्ञान लेने के लिए कहा गया था, हालांकि वह अपराध के समय ऐसा व्यक्ति था।" इस दृष्टिकोण का पालन सी. आर. बंसी बनाम में किया गया है। महाराष्ट्र राज्य, [1971] 3 एस. सी. आर. 236 और के. एस. धर्मादत्तन बनाम। केंद्रीय सरकार और अन्य।, [ 1979 ] 3 एस. सी. आर. 832 और अंत में आर. एस. नायक और अन्य में एक संविधान पीठ के फैसले में दोहराया गया। वी. ए. आर. अंतुले, [1984] 2 एस. सी. सी. 183। इसलिए सवाल यह है कि अब रेज़ इंटीग्रा नहीं है।

यह हमें दूसरे प्रश्न के अंत में लाता है और हमें आगे ले जाता है।

पहले सवाल के लिए। के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं में से

अपीलार्थी, पहला प्रश्न धारा 5 (1) के खंड (ई) के तहत बनाए गए अपराध की प्रकृति से संबंधित है। दूसरा, संबद्ध प्रश्न, तत्काल मामले में दायर आरोप पत्र की अयोग्यता के बारे में है क्योंकि यह अपराध के आवश्यक घटक को शामिल करने में विफल रहा है। यह था। आग्रह किया कि लोक सेवक परिसंपत्तियों और आय के ज्ञात स्रोतों के बीच असमानता को समझाने का अवसर पाने का हकदार है। यह अवसर लोक सेवक को जांच अधिकारी द्वारा दिया जाना चाहिए और आरोप पत्र में इस आशय का एक बयान होना चाहिए, यानी लोक सेवक द्वारा लेखांकन के असंतोषजनक तरीके के लिए। जब तक आरोप पत्र में ऐसा कोई कथन नहीं है, वकील ने तर्क दिया कि कानून के तहत अधिनियम की धारा 5 (1) के खंड (ई) के तहत अपराध नहीं बनाया जाता है।

दलीलों पर उचित विचार के लिए, हमारे पास हो सकता है

धारा 5 (1) के खंड (ई) का प्रसवपूर्व इतिहास। अधिनियम की धारा 5 (1), जैसा कि मूल रूप से था, चार खंडों (ए), (बी), (सी) और (डी) में उन कार्यों या चूक का प्रावधान करता है जिनके बारे में कहा जाता है कि लोक सेवक ने किए थे।

अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आपराधिक दुराचार का अपराध। 'अपने कर्तव्यों के निर्वहन में' शब्द को छोड़कर ये सभी प्रावधान अभी भी मौजूद हैं। इसके बाद धारा 5 (3) आई जो इन शब्दों में थी:

" उप-धारा (2) के तहत दंडनीय अपराध के किसी भी मुकदमे में तथ्य यह है कि अभियुक्त व्यक्ति या उसका कोई अन्य व्यक्ति पक्ष कब्जे में है, जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति नहीं कर सकता है आर्थिक संसाधनों या संपत्ति का संतोषजनक लेखा [1991] 3 एस. सी. आर.

256

#### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आय के ज्ञात स्रोतों से असमान हो सकता है साबित हुआ, और इस तरह के सबूत पर अदालत मान लेगी, जब तक कि इसके विपरीत साबित होता है कि अभियुक्त व्यक्ति दोषी है अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में आपराधिक कदाचार और उसके लिए उसकी दोषसिद्धि केवल कारण से अमान्य नहीं होगी। कि यह पूरी तरह से ऐसी धारणा पर आधारित है। .

यह धारा 5 (3) एक नया अपराध नहीं बनाती है, बल्कि केवल प्रावधान करती है।

धारा के तहत दंडनीय अपराध साबित करने का एक अतिरिक्त तरीका 5 ( 2 ) जिसके लिए किसी भी आरोपी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा रहा था। यह न्यायालय को कुछ परिस्थितियों में अभियुक्त के अपराध का अनुमान लगाने में सक्षम बनाता है। यह अतिरिक्त तरीका धन की सीमा को साबित करके है।

अभियुक्त या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में संसाधन या संपत्ति और उसके बाद यह दर्शाना कि यह उसकी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुरूप नहीं है। यदि ये तथ्य साबित हो जाते हैं तो धारा न्यायालय के लिए यह मान लेना अनिवार्य बनाती है कि अभियुक्त व्यक्ति अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में आपराधिक दुराचार का दोषी है, जब तक कि इसके विपरीत अभियुक्त द्वारा साबित नहीं किया जाता है कि वह इतना दोषी नहीं है। धारा 5 (3) में आगे यह प्रावधान किया गया है कि आपराधिक दुराचार के अपराध के लिए दोषसिद्धि इस कारण से अमान्य नहीं होगी कि यह पूरी तरह से ऐसी धारणा पर आधारित है। ( देखिए: ( i) सी. एस. डी. स्वामी बनाम द.

राज्य, [1960] 1 एससीआर 461; (ii) सूरजपाल सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, [961] 2 एस. सी. आर. 971, और (iii) सज्जन सिंह बनाम। पंजाब राज्य, [1964] 4 एससीआर 630।

1962 में, जैसा कि पहले बताया गया था, 'पूर्ववत' पर संधानम समिति

भ्रष्टाचार से संबंधित कानून की समीक्षा करने, रिश्वत और आपराधिक कदाचार के मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने और अन्यथा कानून को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए भ्रष्टाचार का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ इसकी सिफारिश की है - अधिनियम में धारा 5 (1) के खंड (ई) को मूल अपराध के रूप में शामिल करना। सरकार ने उस सिफारिश को स्वीकार कर लिया और

उस सिफारिश के प्रभाव से, अधिनियम की धारा 5 (3) के स्थान पर धारा 5 (1) का खंड (ई) अधिनियमित किया गया। भ्रष्टाचार विरोधी कानून (संशोधन) अधिनियम, 1964 (1964 का अधिनियम संख्या 40) के अधिनियमन की ओर ले जाने वाले विधेयक के साथ उद्देश्यों और कारणों का विवरण जिसके द्वारा अधिनियम में धारा 5 (1) का खंड (ई) पेश किया गया था, इस प्रकार है:

" ( घ) समिति ने कई सिफारिशों की हैं -

अधिनियम, 1947। इसने सुझाव दिया है कि अनुमान एनून अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) और (2) में उल्लिखित

257 के तहत अपराधों के संबंध में भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई. (शेट्टी, जे. जे.

धारा 5 और आय से अधिक संपत्ति का कब्जा होना चाहिए।  
एक मूल अपराध बनाया जाए "।

( जोर दिया गया)

तत्काल संदर्भ के लिए, धारा 5 (1) के खंड (ई) का खंडन किया जाता है।

यहाँ नीचे लिखा है:

" 5 ( 1 ) ( ई) यदि वह या उसकी ओर से कोई व्यक्ति कब्जे में है  
या अपने पद की अवधि के दौरान किसी भी समय  
कब्जा, जिसके लिए लोक सेवक संतुष्ट नहीं हो सकता है  
आर्थिक संसाधनों या संपत्ति का ऋण खाता

आय के अपने ज्ञात स्रोतों का उल्लेख करें।

खंड (ई) की शर्तें इंगित करती हैं कि अंतर्निहित सिद्धांत

ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 5 (3) को कुछ अलग शब्दों में मूल अपराध में बढ़ा दिया गया है।  
हम वर्तमान में खंड (ई) के तहत अपराध के घटकों का विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले, खंड  
(ई) के दायरे पर इस न्यायालय के दो निर्णयों को संदर्भित किया जा सकता है। महाराष्ट्र में वी.

के. के. एस. रामास्वामी, [1978] 1 एस. सी. आर. 274, जे. शिंगल, ने कहा (276 पर) कि  
खंड (ई) के अधिनियमन का परिणाम यह है कि केवल

ज्ञात से असमान आर्थिक संसाधन या संपत्ति एक लोक सेवक की आय के स्रोत, जिसके  
लिए वह कारक के रूप में लेखा नहीं दे सकता था, अपने आप में एक अपराध बन गया, हालांकि  
धारा 5 (3) जो धारा 5 (1) (ई) से पहले मौजूद थी, एक अपराध नहीं थी।

महाराष्ट्र राज्य में v. वासुदेव रामचंद्र कैडलवार,

[ 1981 ] 3 एस. सी. आर. 675, जे. सेन, ने धारा 5 (1) के खंड (सी) की अंतर्दृष्टि को  
संक्षिप्त रूप से स्पष्ट किया। 682 से 684):

अधिनियम वही हैं जो पुरानी धारा 5 (3) में उपयोग किए गए हैं।  
हालांकि दोनों प्रावधान दो अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं,

"आय के ज्ञात स्रोत" का अर्थ है "स्रोत" अभियोजन पक्ष को पता है "। तो भी वही अर्थ होना चाहिए उन शब्दों को दिया जाए जिनके लिए लोक सेवक है एस में होने वाले "को संतोषजनक रूप से ध्यान में रखने में असमर्थ। 5 ( 1 ) ( ई)। नहीं। संदेह एस। 4 ( 1 ) मामलों में अपराध के अनुमान का प्रावधान एसएस के तहत गिरना। 5 ( 1 ) ( a) और (b), लेकिन वहाँ था, हमारे कारण स्पष्ट है। एस में निहित प्रावधान। 5 ( 1 ) ( ई) का अधिनियम एक स्व-निहित प्रावधान है। का पहला भाग धारा अभियोजन पक्ष पर बोझ डालती है और दूसरा

### 1 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1991] 3 एस. सी. आर.

अभियुक्त के बारे में। जब एस। 5 ( 1 ) ( ई) उन शब्दों का उपयोग करता है जिनके लिए लोक सेवक संतोषजनक रूप से जवाबदेह नहीं है।

इसका तात्पर्य यह है कि बोझ ऐसे लोक सेवक पर है

असमान के अधिग्रहण के लिए स्रोतों के लिए

संपत्ति। इसलिए, उच्च न्यायालय ने निर्णय लेने में गलती की थी

कि एक लोक सेवक पर अनुपातहीन होने का आरोप लगाया गया है

ऐसी परिसंपत्तियाँ जिनके लिए वह संतोषजनक रूप से कब्जा नहीं कर सकता है

खाते में, एस के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। 5 ( 2 ) एस के साथ पढ़ें। 5 ( 1 ) ( ई) अधिनियम के जब तक अभियोजन पक्ष

आय के सभी संभावित स्रोतों को साबित करता है।

अधिनियम की धारा 5 (1) (ई) के तहत सबूत का बोझ, सीखा 1:

"सबूत का बोझ" अभिव्यक्ति के दो अलग-अलग अर्थ हैं।

इंस; (1) कानूनी बोझ अर्थात् अपराध को स्थापित करने का बोझ, और (2) साक्षय का बोझ अर्थात् साक्षय देने का बोझ। अपराधिक मुकदमे में, साबित करने का बोझ

के खिलाफ आरोप स्थापित करने के लिए आवश्यक सब कुछ

अभियुक्त अभियोजन पक्ष पर झूठ बोलता है, और वह बोझ कभी नहीं

स्थानांतरण। सामान्य नियम के बावजूद कि

सबूत विशेष रूप से अभियोजन पक्ष पर निहित है, के मामले में

कुछ अपराधों में किसी विशेष तथ्य को साबित करने का बोझ इस मुद्दे को कानून द्वारा अभियुक्त पर रखा जा सकता है। बोझ।

हालाँकि, ऐसे मामलों में अभियुक्त को आराम नहीं दिया जाता है।

उतना ही भारी जो अभियोजन पक्ष पर निर्भर करता है और

संभाव्यताओं के संतुलन के प्रमाण द्वारा आरोपित।

अपराध के अंश, विद्वान न्यायाधीश ने जारी रखा:

" अपराधिक दुराचार के अपराध के तत्व एस के तहत। 5 ( 2 ) एस के साथ पढ़ें। 5 ( 1 ) ( ई) आर्थिक संसाधनों या संपत्ति के कब्जे के लिए अनुपातहीन हैं

आय के ज्ञात स्रोत जिनके लिए लोक सेवक कर सकता है

अभियोजन को निम्नलिखित तथ्यों को साबित करना होगा इससे पहले कि वह कर सके एस के तहत एक मामला लाओ। 5 ( 1 ) ( ई), अर्थात्, (1) इसे स्थापित करना चाहिए

कि अभियुक्त लोक सेवक है, (2) प्रकृति और

आर्थिक संसाधनों या संपत्ति का विस्तार जो

उसके कब्जे में पाया गया, (3) यह साबित किया जाना चाहिए कि क्या

उनकी आय के ज्ञात स्रोत थे जो पेशेवरों को ज्ञात थे

प्रतिच्छेदन, और (4) यह काफी निष्पक्ष रूप से साबित होना चाहिए कि

अभियुक्त के कब्जे में पाए गए संसाधन या संपत्ति 259

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [शेट्टी, जे।]

आय के उनके ज्ञात स्रोतों से असमान थे।

एक बार जब ये चार तत्व स्थापित हो जाते हैं, तो

एस के तहत आपराधिक दुराचार। 5 ( 1 ) ( ई) पूर्ण है, जब तक कि

अभियुक्त ऐसे संसाधनों या प्रो के लिए जिम्मेदार होने में सक्षम है।  
प्रति "बोझ तब अभियुक्त को संतुष्ट करने के लिए स्थानांतरित हो जाता है

तोरी, अपने अनुपातहीन कब्जे के लिए जिम्मेदार है

संपत्ति। प्रूफ रेस्टिंग के बोझ की सीमा और प्रकृति  
लोक सेवक के पास अवैध अधिकार पाए जाने पर

एस के तहत परिसंपत्तियों का विभाजन करें। 5 ( 1 ) ( ई) से अधिक नहीं हो  
सकता है

जाहगन के मामले (ऊपर) में न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षण, अर्थात्

उसके मामले को प्रायिकता की प्रधानता से स्थापित करें। कि  
के आदेश के बाद न्यायालय द्वारा परीक्षण निर्धारित किया गया था

वूलमिंगटन बनाम में विस्काउंट सेंकी, एल. सी. निदेशक

लोक अभियोजन "।

वासुदेव रामचंद्र में तर्क की दृढ़ता

कैदलवार मामला (ऊपर) पर संदेह किया गया है। अपीलार्थी के लिए वकील

आग्रह किया कि धारा 5 (3) पर लिए गए दृष्टिकोण को धारा 5 (1) के खंड (ई) में आयात  
नहीं किया जा सकता है और इसलिए निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। लेकिन हमें नहीं  
लगता कि निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 5 (1)  
की धारा 5 (3) और खंड (ई) में उपयोगी समानांतर है। खंड (ई) एक वैधानिक अपराध पैदा

करता है जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया जाना चाहिए। यह अभियोजन पक्ष के लिए है कि

यह साबित करें कि अभियुक्त या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के पास आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक आर्थिक संसाधन या संपत्ति है। जब अभियोजन पक्ष द्वारा उस दायित्व का निर्वहन किया जाता है, तो यह अभियुक्त पर निर्भर करता है कि वह उसके पास मौजूद संपत्तियों की असमानुपातिकता के लिए संतोषजनक रूप से जवाबदेह हो। यह धारा वैधानिक बचाव उपलब्ध कराती है जिसे अभियुक्त द्वारा साबित किया जाना चाहिए। यह एक प्रतिबंधित बचाव है जो आय पर परिसंपत्तियों की अनुचित राष्ट्रीयता के लिए अभियुक्त को दिया जाता है। लेकिन अभियुक्त पर सबूत का कानूनी बोझ अभियोजन पक्ष जितना भारी नहीं है। हालाँकि, यह अभियोजन पक्ष पर कुछ संदेह नहीं डाल रहा है।

सायन। विधायिका ने सलाह दी है कि "संतोषजनक रूप से लेखा" अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाए। "संतोषजनक" शब्द पर जोर दिया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि अभियुक्त को अदालत को संतुष्ट करना होगा कि उसका स्पष्टीकरण स्वीकार करने योग्य है। अभियुक्त पर रखे गए सबूत का बोझ एक साक्ष्य का बोझ है, हालांकि पीछा करने का बोझ नहीं है। अभियुक्त चाहे कभी भी, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य और/या बचाव पक्ष के साक्ष्य से "जांच क्षमताओं के संतुलन पर" सबूत के उस बोझ का निर्वहन कर सकता था।

यह प्रक्रिया [1991] 3 एस. सी. आर. के प्रसिद्ध सिद्धांत के विपरीत हो सकती है।

260

#### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वूलमिंगटन बनाम में निर्धारित आपराधिक न्यायशास्त्र। लोक अभियोजन निदेशक, [1935] ए. सी. 462 ने कहा कि सबूत का भार हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है और कभी भी आरोपी व्यक्ति पर नहीं जाता है। लेकिन संसद कुछ पहलुओं का भार अभियुक्त पर भी डालने के लिए सक्षम है और विशेष रूप से "विशेष रूप से उसके ज्ञान के भीतर" मामलों में। ( साक्ष्य अधिनियम की धारा 106)। चतुराई से, जैसा कि स्वामी मामले (469 पर) में देखा गया है और वासुदेव मामले (683 पर) में दोहराया गया है, अभियोजन पक्ष से, चीजों की प्रकृति में, संपत्ति के संसाधनों के कब्जे में पाए जाने वाले लोक सेवक के मामलों को जानने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

आय के अपने ज्ञात स्रोतों में भाग दें। यह उसे समझाना है। अभियुक्त पर बोझ डालने वाले ऐसे कानून को अनुचित, अन्यायपूर्ण या अनुचित नहीं माना जा सकता है। न ही इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के विपरीत माना जा सकता है जैसा कि अपीलार्थी ने तर्क दिया है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि वूल्लिंगटन मामले में जिस सिद्धांत की पुनः पुष्टि की गई है, वह हर मामले में पालन किया जाने वाला सार्वभौमिक नियम नहीं है। यह सिद्धांत केवल इसके विपरीत वैधानिक प्रावधान के अभाव में लागू किया जाता है। ( रिग में लॉर्ड टेम्पलमैन और लॉर्ड गिर्फिथ्स के अवलोकन देखें। वी. हंट, [1986] 3 डब्ल्यू. एल. आर. 1115 1118 और 1129)।

हालाँकि, अपीलार्थी के वकील ने प्रस्तुत किया कि कोई नहीं है

एक लोक सेवक के पास अपनी संपत्ति होने पर प्रतिबंध लगाने वाली कानून आय के अपने ज्ञात स्रोतों और ऐसे कब्जे के हिस्से को अवैध मानती है।

आपराधिक दुराचार का अपराध तभी बनता है जब अभियुक्त इसका हिसाब देने में असमर्थ होता है। ऐसा लगता है कि वकील केवल बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं

धारा 5 (1) के खंड (ड) के एक भाग पर। धारा 5 (1) के खंड (ई) का पहला भाग, जैसा कि पहले देखा गया है, लोक सेवक के पास मौजूद संपत्ति के प्रमाण से संबंधित है। जब अभियोजन पक्ष साबित करता है कि जनता

नौकर के पास आय के अपने ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक संपत्ति होती है, आपराधिक दुराचार के अपराध का श्रेय लोक सेवक को दिया जाता है। हालाँकि, यह लोक सेवक के लिए खुला है कि वह परिसंपत्तियों की ऐसी असमानुपातिकता के लिए संतोषजनक रूप से जवाबदेह हो। लेकिन यह कहना एक ही बात नहीं है कि जब तक लोक सेवक संपत्ति की अधिकता का हिसाब देने में सक्षम नहीं है, तब तक कोई अपराध नहीं है। यदि किसी के पास अपने वैध साधनों से अधिक संपत्ति है, तो यह कहने की जरूरत नहीं है कि अतिरिक्त राशि गलत तरीके से अर्जित लाभ से है। परिसंपत्तियाँ हवा से नाइट्रोजन की तरह नहीं खींची जाती हैं। इसे प्राप्त करना पड़ता है जिसके लिए साधन आवश्यक हैं। आय के स्रोत या संपत्ति अर्जित करने के साधन को साबित करना लोक सेवक का काम है। यह धारा 5 (1) के खंड (ई) का सार है।

इस दृष्टि से कि हमने अपराध की प्रकृति को लिया है

खंड (ग) के अधीन सृजित, अपराध के घटक से संबंधित अभिकथन की जांच करना आवश्यक नहीं हो सकता है। लेकिन चूंकि आरोप पत्र की वैधता पर महाभियोग चलाया गया है, इसलिए हम उस विवाद से निपटेंगे 261

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [शेड्टी, जे।]

भी। वकील ने उस अभिव्यक्ति पर बहुत जोर दिया जिसके लिए उन्होंने अधिनियम की धारा 5 (1) के खंड (ई) में उपयोग किया गया संतोषजनक खाता। उन्होंने तर्क दिया कि उस शब्द का अर्थ है कि लोक सेवक को जांच अधिकारी के समक्ष स्पष्टीकरण देने का अवसर प्राप्त है।

परिसंपत्तियों और आय के ज्ञात स्रोतों के बीच कथित असमानुपात। जांच अधिकारी को अपने स्पष्टीकरण पर विचार करना आवश्यक है और उसके द्वारा दायर आरोप पत्र में ऐसा कथन होना चाहिए। उस आवश्यकता का उल्लेख करने में विफलता आरोप पत्र को दूषित कर देगी और इसे अमान्य कर देगी। यह निवेदन, यदि हम ऐसा कह सकते हैं, तो जांच अधिकारी की शक्तियों की पूरी तरह से अनदेखी करता है। जांच अधिकारी को केवल यह पता लगाने के लिए सामग्री एकत्र करने की आवश्यकता होती है कि क्या कथित अपराध किया गया प्रतीत होता है। जांच के दौरान, वह अभियुक्त से पूछताछ कर सकता है। वह अपना स्पष्टीकरण मांग सकता है और यदि आवश्यक हो तो वह अपनी आय और संपत्ति के ज्ञात स्रोतों के बारे में उससे पूछताछ कर सकता है। वास्तव में, निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है जैसा कि श्री ए. डी. गिरि ने सही कहा है।

जनरल, कि अभियुक्त को अंधेरे में नहीं रखा जाना चाहिए। यदि वह सहयोग करने को तैयार है तो उसे विश्वास में लिया जाना चाहिए। लेकिन यह कहने के लिए कि सभी सामग्री के संग्रह के बाद जांच अधिकारी को आरोपी को एक अवसर देना चाहिए और उसे आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए। लेखा संतोषजनक है या नहीं, यह जांच अधिकारी को जांच अधिकारी या न्यायाधीश के पद से अलग करना होगा। जांच अधिकारी लोक सेवक के आचरण के खिलाफ जांच नहीं कर रहा है या संपत्ति और अभियुक्त की आय के बीच अनुपातहीनता के संबंध में विवादित मुद्दों का निर्धारण नहीं कर रहा है। वह केवल सभी पक्षों से सामग्री एकत्र करता है और एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसे वह आरोप पत्र के रूप में न्यायालय में दाखिल करता है।

आरोप पत्र और कुछ नहीं बल्कि पुलिस अधिकारी की अंतिम रिपोर्ट है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) के तहत। पी. सी. धारा 173 (2) में प्रावधान है कि जांच पूरी होने पर जांच करने वाला पुलिस अधिकारी

संज्ञेय अपराध एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में होनी चाहिए और उसमें (क) पक्षों के नाम; (ख) सूचना की प्रकृति; (ग) उन व्यक्तियों के नाम जो मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होते हैं; (घ) क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है और, यदि हां, जिनके द्वारा (ङ) आरोपी को गिरफ्तार किया गया है या नहीं; (च) क्या उसे उसके मुचलके पर रिहा किया गया था और, यदि हां, तो जमानत के साथ या बिना; और (छ) क्या

उसे धारा के तहत हिरासत में भेजा गया है। 170. जैसा कि इस न्यायालय ने सत्य नारायण मुसादी और अन्य मामलों में कहा है। वी. बीकर राज्य, [1980] 3 एस. सी. सी. 152 157 पर; कि धारा 173 (2) के तहत रिपोर्ट की वैधानिक आवश्यकता का अनुपालन सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1991] 3 एस. सी. आर.

यदि उसमें निर्धारित विभिन्न विवरण रिपोर्ट में शामिल हैं। यह रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को एक सूचना है कि एक संज्ञेय अपराध की जांच के बाद जांच अधिकारी अपराध की जांच के लिए अदालत के लिए पर्याप्त सबूत जुटाने में सक्षम हो गया है और आवश्यक जानकारी अदालत को भेजी जा रही है। वास्तव में, धारा 173 (2) के तहत रिपोर्ट निवेश करने वाले अधिकारी की राय है कि जहां तक उसका संबंध है, वह अदालत द्वारा अभियुक्त के मुकदमे के लिए पर्याप्त सामग्री प्राप्त करने में सक्षम रहा है। रिपोर्ट तब पूरी होती है जब यह धारा 175 (5) द्वारा आवश्यक सभी दस्तावेजों और गवाहों के बयानों के साथ होती है। जांच अधिकारी की रिपोर्ट में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यह भी आवश्यक नहीं है कि अपराध के सभी विवरण बताए जाने चाहिए। अपराध के विवरण को बाद के चरण में अभियुक्त के सामने अपराध को घर लाने के लिए साबित करने की आवश्यकता होती है, यानी स्वीकार्य साक्ष्य पेश करके मामले की सुनवाई के दौरान। तत्काल मामले में, आरोप पत्र में धारा 173 (2) की सभी आवश्यकताएं शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि जांच से पता चलता है कि 1 मई 1969 और 24 फरवरी 1976 के बीच मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपीलार्थी के पास अपने नाम और अपनी पत्नी और दो बेटों आदि के नाम पर आर्थिक संसाधन और संपत्ति थी, जो ज्ञात व्यक्ति के लिए 6,41 रुपये, 416.36 से अधिक थी।

इसी अवधि में आय के स्रोत और ऐसे असमान आर्थिक संसाधनों और संपत्ति के लिए संतोषजनक रूप से जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं। अपीलार्थी की संपत्तियों और आर्थिक संसाधनों का विवरण भी स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। नहीं, हमारी राय में, आरोप पत्र में और अधिक बताए जाने की आवश्यकता है। यह पूरी तरह से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) की शर्तों के अनुसार है। अधिनियम की धारा 5 (1) के पी. सी. और खंड (ई)।

पूर्वगामी कारणों से, हम अपील को खारिज करते हैं और निचली अदालत को मामले को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश देते हैं। मामला छोड़ने से पहले, हम एक शब्द और कह सकते हैं। इस मामले ने हमें बहुत चिंतित किया है। हमने अपना पूरा ध्यान दिया

सवाल उठाए गए। हमने निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले प्रश्नों की जाँच और पुनः जाँच की है। हम मानते हैं कि एक न्यायाधीश में ईमानदारी के लिए समाज की मांग सटीक और निरपेक्ष है। न्यायपीठ के अंदर और बाहर दोनों जगह न्यायिक व्यवहार के मानक आम तौर पर बहुत उच्च होते हैं। एक न्यायाधीश के लिए ईमानदारी और अनैतिकता के ऐसे मानकों से भटकना उस पर रखे गए विश्वास के साथ विश्वासघात करना है। कोई बहाना या कोई कानूनी सापेक्षता इस तरह के विश्वासघात को माफ नहीं कर सकती है। न्याय के दृष्टिकोण से रिश्वत का आकार या भ्रष्टाचार का दायरा किसी न्यायाधीश के अपमान को मापने का पैमाना नहीं हो सकता है। एक एकल बेईमान न्यायाधीश न केवल 263

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [शर्मा, जे.]

स्वयं का सम्मान करता है और अपने पद का अपमान करता है लेकिन पूरी न्यायिक प्रणाली की अखंडता को खतरे में डालता है।

न्यायिक घोटाले को हमेशा कहीं अधिक निंदनीय माना गया है।

कार्यपालिका या विधानमंडल के किसी सदस्य को शामिल करने वाले घोटाले से सक्षम। न्यायालय में अनियमितता या अनुचितता का थोड़ा सा संकेत बहुत चिंता और चिंता का कारण बनता है। “एक विधायक या एक प्रशासक को स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार का दोषी पाया जा सकता है।”

राज्य की नींव को खतरे में डालना। लेकिन न्यायपालिका की निष्पक्षता और विचाराधीनता को बनाए रखने और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए एक न्यायाधीश को खुद को संदेह से बिल्कुल ऊपर रखना चाहिए।

शर्मा, जे. मैंने श्री के विद्वान निर्णयों का अध्ययन किया है।

न्यायमूर्ति रे, न्यायमूर्ति शेट्टी और न्यायमूर्ति वर्मा। मैं श्री न्यायमूर्ति रे और श्री न्यायमूर्ति शेट्टी से सहमत हूँ कि अपील को खारिज कर दिया जाना चाहिए। अपने विद्वान भाइयों के निर्णयों में तथ्यों और कानून की विस्तृत चर्चा को देखते हुए, मैं उनके साथ विस्तार से बात करने से बच रहा हूँ, और अपने कारणों को संक्षेप में बता रहा हूँ।

2. "लोक सेवक" अभिव्यक्ति का उपयोग रोकथाम में किया जाता है

भ्रष्टाचार अधिनियम, 1947 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) निस्संदेह इतना व्यापक है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित प्रत्येक न्यायाधीश को निरूपित कर सकता है। तर्क यह है कि अधिनियम के प्रावधानों के साथ विचार की गई अधिनियम की भाषा को ध्यान में रखते हुए

विशेष रूप से अधिनियम के अनुच्छेद 124, धारा 5 को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, यह सुझाव और उचित रूप से नहीं दिया गया है कि संसद में उन मामलों में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मुकदमे और दोषसिद्धि के लिए कानून पारित करने में न्यायशास्त्र की कमी है जहां वे आपराधिक अपराध करने के दोषी हैं। तर्क यह है कि अधिनियम की योजना को देखते हुए यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि अधिनियम के दंडात्मक प्रावधान उन पर लागू नहीं होते हैं। धारा 6 पर बहुत अधिक निर्भरता रखी गई है, जिसमें संज्ञान लेने के लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में न्यायाधीश को कार्यालय से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। यह आग्रह किया गया है कि इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि अधिनियम में उच्च न्यायालय के किसी सदस्य का मामला शामिल नहीं है।

कार्यालय में रहते हुए न्यायपालिका और परिणामस्वरूप यह उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी उन पर लागू नहीं किया जा सकता है। इस तर्क के प्रयोजन के लिए यह माना जाता है कि धारा 6 के अर्थ के भीतर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाने के लिए कोई सक्षम प्राधिकारी नहीं है, और इसलिए, उनके खिलाफ अभियोजन शुरू करने की शर्त को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि यह बुनियादी धारणा सही है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1991] 3 एस. सी. आर.

264

3. अधिनियम की धारा 6 (1) (सी) "सक्षम प्राधिकारी" की बात करती है।

उसका कार्यालय। इस संबंध में सटीक रूप से प्राधिकरण कौन है, यह एक ऐसा मामला है, जो मेरे विचार में, वर्तमान मामले में उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या ऐसा प्राधिकरण मौजूद है या नहीं, इसका जवाब हां में दिया जाना चाहिए। 4. अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री सिब्वल ने दृढ़ता से तर्क दिया है कि संविधान में एक स्वतंत्र व्यवस्था की परिकल्पना की गई है।

न्यायपालिका, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि कार्यपालिका और पिछड़ेपन सहित राज्य के अन्य अंगों को ऐसी स्थिति से वंचित किया जाए जहां से न्यायपालिका पर दबाव डाला जा सके।

5. राज्य एक ऐसा संगठन है जो जनता की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है; यह अपने आप में कोई अंत नहीं है। विधायिका सहित इसकी विभिन्न शाखाएँ,

न्यायपालिका और कार्यपालिका का उद्देश्य अलग-अलग निर्धारित महत्वपूर्ण कार्यों को करना है। न्यायपालिका का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति और व्यक्ति के बीच और स्वयं व्यक्ति और राज्य के बीच भी न्याय प्रदान करे। अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम होने के लिए न्यायाधीशों को "भय या पक्षपात, स्नेह या दुर्भावना के बिना" कार्य करना पड़ता है। इसलिए, उन्हें किसी भी हिस्से से प्रेस शयोर से मुक्त होना चाहिए। न्यायपालिका के विचाराधीनता के इस मूल सार से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन न्यायपालिका के वास्तव में प्रभावी होने के लिए, न्याय के प्रशासन में शुद्धता और अदालतों में लोगों का विश्वास भी उतना ही आवश्यक है। यह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए है कि उच्च न्यायपालिका को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति दी गई है। यह आवश्यक हो गया है ताकि एक व्यथित या दुराचारित व्यक्ति अदालत पर ऐसे आक्षेप न लगा सके जो

जनता के विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि समुदाय अदालतों में अपना विश्वास खो देता है, तो उनके अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रहेगा। न्यायसंगत कारण वाला व्यक्ति कानूनी 265 के लिए अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाएगा।

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [शर्मा, जे.]

उपचार, यदि उनके विश्वास के अनुसार न्यायालय का निर्णय बाहरी विचार पर दिया जाएगा न कि उनके दावे के गुण-दोष पर। लोग सड़कों पर अपने विवाद को निपटाने के लिए जंगल के कानून की ओर लौटेंगे। ये पहलू पूरी न्यायपालिका के लिए समान हैं, चाहे वे उच्च हों या अधीनस्थ, और मेरे विचार से एक श्रेणी को दूसरी श्रेणी से अलग करने के लिए किसी भी वर्गीकरण की अनुमति नहीं है।

6. यद्यपि उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश महत्वपूर्ण कार्य करते हैं।

विशेष कार्य और विशेष अधिकार क्षेत्र के साथ निहित हैं। यह नहीं भुलाया जा सकता है कि न्यायिक शक्ति, जहाँ भी निहित हो, एक लोकतांत्रिक संविधान के लिए अभिन्न और बुनियादी

है। बड़ी संख्या में मामलों का फैसला अंततः अधीनस्थ न्यायपालिका के स्तर पर किया जाता है। इसलिए अधीनस्थ न्यायपालिका को भी उसी स्वतंत्रता की आवश्यकता है जो उच्च न्यायपालिका के लिए आवश्यक है। इसलिए, यह मान लेना सुरक्षित नहीं है कि अधिनियम का उद्देश्य अपने अनुप्रयोग में निचली और उच्च न्यायपालिका के बीच कोई भेदभाव करना है। सामान्य रूप से लोक सेवक को अनुच्छेद 311 के तहत सुरक्षा प्रदान की जाती है और अधीनस्थ न्यायपालिका के हित का ध्यान उच्च न्यायालय द्वारा रखा जाता है, और यह पिछली मंजूरी के प्रावधानों के साथ उन्हें अनुचित अभियोजन से बचाता है। इसी तरह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को आरती के प्रावधानों के माध्यम से सुरक्षा उपलब्ध है।

संविधान की धारा 124 (4) और (5)। जहाँ तक इस पहलू का संबंध है, न्यायाधीशों की दो श्रेणियाँ-उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश

एक ओर और दूसरी ओर कानून द्वारा अलग तरीके से व्यवहार नहीं किया गया है। ऐसा कोई तर्कसंगत आधार नहीं हो सकता है जिसके आधार पर उच्च न्यायपालिका के किसी सदस्य को अभियोजन से बचने की अनुमति दी जा सके, जबकि समान परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायपालिका के किसी सदस्य पर मुकदमा चलाया जाता है और उसे दोषी ठहराया जाता है। अधिनियम की इस तरह की व्याख्या इसकी संवैधानिक वैधता के खिलाफ होगी और इसलिए इसे प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए।

#### 7. अभी भी एक और कारण है जो इंगित करता है कि व्याख्या

अपीलार्थी की ओर से सुझाए गए सुझाव को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यदि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि उच्च न्यायपालिका का कोई सदस्य धारा 6 के तहत विवेकपूर्ण मंजूरी की आवश्यकता के कारण धारा 5 के तहत किसी अपराध के लिए अभियोजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो यह होगा कि वह न केवल धारा 5 (1) (ई) के तहत अभियोजन से मुक्त होगा जैसा कि वर्तमान मामला है, बल्कि खंड (ए) से (डी) के तहत अन्य अपराधों के लिए भी। अब तक भारतीय दंड संहिता की धारा 161, 164 और 165 के तहत दंडनीय अपराध

दंड संहिता का संबंध है कि वे भी इस तरह की पिछली सजा के अधीन हैं। परिणाम गंभीर होगा। यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि नहीं

व्यक्ति कानून से ऊपर है और यहां तक कि एक संवैधानिक संशोधन भी प्रधान मंत्री के मामले में अनुच्छेद 329 ए में बंधा हुआ था [1991] 3 एस. सी. आर.

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1976 में (2) एस. सी. आर. 347 470 डिग्री सेल्सियस-डी पर। यह याद रखना होगा कि अनुच्छेद 124 के तहत एक कार्यवाही में एक न्यायाधीश को केवल पद से हटाया जा सकता है। उसका कार्यालय। उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता और दंडित नहीं किया जा सकता। आइए हम एक ऐसे मामले को लें जहां ऐसी कार्यवाही में एक सकारात्मक निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि न्यायाधीश आदतन रिश्वत ले रहा था, और उस आधार पर वह है

उसे कार्यालय से हटा दिया गया। श्री सिब्ल के तर्क पर, मामले को उनके हटाने के साथ बंद करना होगा और वह आपराधिक दायित्व से बच जाएंगे और यहां तक कि गलत तरीके से अर्जित धन को भी जब्त नहीं किया जाएगा। आइए हम एक और स्थिति पर विचार करें जहां एक उकसाने वाला दोषी पाया जाता है

भारतीय दंड संहिता की धारा 165 ए और उसे दोषी ठहराया जाता है। मुख्य अपराधी, न्यायाधीश अपीलार्थी के तर्क पर भाग जाएगा। सभ्य समाज में यह नहीं माना जा सकता कि कानून इस तरह के अशांतिपूर्ण परिणामों की ओर ले जा रहा है।

8. दूसरा दृष्टिकोण अपनाने में मुझे कोई कठिनाई नहीं दिखाई देती है।

या तो योजना या अधिनियम की भाषा या किसी संवैधानिक प्रावधान द्वारा। संधानम समिति की रिपोर्ट में यह बयान कि सदस्यों ने न्यायपालिका को संदर्भ के दायरे में शामिल नहीं किया, बहुत मददगार नहीं है क्योंकि यह अधिनियम अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर लागू होता है। न ही किसी सरकार द्वारा प्रकटीकरण से संबंधित नियम बनाए जा सकते हैं। अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों के सेवक

कानून का दायरा निर्धारित करें। ये नियम स्थान-स्थान पर भिन्न होते हैं और समय-समय पर परिवर्तन के अनुसार संशोधित किए जाते हैं।

आवश्यकताएँ। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाने की शक्ति मौजूद है और इसका उपयोग अनुच्छेद 124 के प्रावधानों के अनुसार उचित परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। इसलिए, यह कहना सही नहीं है कि उसके अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। अधिनियम की धारा 2 भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में दी गई "लोक सेवक" की परिभाषा को अपनाती है, जिसमें "प्रत्येक न्यायाधीश" शामिल है। यदि विधायिका का इरादा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अधिनियम की धारा 5 के क्षेत्र से बाहर करने का होता, तो वह ऐसा स्पष्ट शब्दों में कह सकती थी। भारतीय दंड संहिता में दिए गए "लोक सेवक" शब्द के व्यापक अर्थ को अपनाने के बजाय।

### 9. प्राधिकरण की पहचान के बारे में आगे का सवाल

अधिनियम की धारा 6 में उल्लिखित आवश्यक मंजूरी देने के अधिकार पर मामले की सुनवाई के दौरान तीखी बहस हुई। न्यायमूर्ति श्री शेटी ने अभिनिर्धारित किया है कि चूंकि अंततः यह राष्ट्रपति का आदेश है जो किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए आवश्यक है, इसलिए उसे सक्षम प्राधिकारी माना जाना चाहिए। संविधान द्वारा परिकल्पित न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए, यह आगे कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को के. वीरास्वामी बनाम होना होगा।

यू. ओ. आई. [शर्मा, जे.]

201

मामले में परामर्श लिया जाएगा और उनकी सलाह के अनुसार कदम उठाए जाएंगे। न्यायमूर्ति श्री रे और न्यायमूर्ति श्री वेंकटचलैया इस दृष्टिकोण से सहमत हैं। मेरा मानना है कि ये टिप्पणियां न केवल स्वीकार्य होंगी, बल्कि भारत संघ के लिए स्वागत योग्य होंगी, क्योंकि सुनवाई के दौरान यह विद्वान सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के सुझाव पर था कि निर्णय में उपरोक्त निर्देश की वांछनीयता पर पीठ द्वारा विचार किया गया था। मैं इस बात की भी पूरी तरह से सराहना करता हूं कि यदि कार्यपालिका इस नियम का सख्ती से पालन करती है, तो न्यायाधीशों को अनुचित और अन्यायपूर्ण आपराधिक अभियोजन द्वारा परेशान करने से रोकने के लिए एक और कदम उठाया जाएगा। लेकिन मेरे विचार में इस न्यायालय द्वारा संविधान और अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर ऐसा बाध्यकारी निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है।

### 10. आगे बढ़ने से पहले मैं फिर कहूंगा कि

इस प्रश्न का उत्तर दिया कि क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसी प्राधिकरण द्वारा हटाया जा सकता है, चाहे वह कोई भी हो, सकारात्मक रूप से, आगे के विवाद पर निर्णय लेना आवश्यक नहीं है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। इसलिए, मैं केवल कुछ पहलुओं का संकेत देकर संतुष्ट रहूंगा जो इस मुद्दे के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं, जिस पर बाद में निर्णय लिया जाएगा जब यह सीधे सामने आएगा।

### 11. यदि राष्ट्रपति को उपयुक्त प्राधिकारी माना जाता है -

संसद को निर्देश दिए बिना मंजूरी देते हुए, वह मंत्रिपरिषद से प्राप्त सलाह के लिए बाध्य होगा। इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाएगी। निस्संदेह

यह संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। गंभीर निहितार्थ को महसूस करते हुए भारत संघ की ओर से यह सुझाव दिया गया था कि यह न्यायालय अभियोजन शुरू करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पूर्व अनुमोदन के माध्यम से उपयुक्त शर्तें निर्धारित कर सकता है। मैं पूरी तरह से सराहना करता हूँ

जो विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उनके संतोषजनक समाधान पर पहुंचने के लिए भारत संघ सहित हम सभी की चिंता है, लेकिन अगर हम कानून को पूरक बनाना शुरू करते हैं जैसा कि अभी है, तो हम विधायी क्षेत्र का अतिक्रमण करेंगे। इस आपत्ति को पूरा करने के लिए यह तर्क दिया गया था कि हमारे लिए सुझाए गए निर्देश को जारी करने की अनुमति है क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में अजनबी नहीं हैं; बल्कि वह तस्वीर में बहुत अधिक हैं। अनुच्छेद 124 (2) और 217 (1) के प्रावधानों का संदर्भ दिया गया था। इस तर्क को स्वीकार करने में कठिनाई यह है कि राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उतने ही शामिल हैं। इसलिए हम उपरोक्त अनुच्छेदों का उल्लेख करके समस्या को सरल नहीं बना सकते। मेरे विचार में भारत के मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी 268 पेश की जा सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1991] 3 एस. सी. आर.

केवल संसद द्वारा अभियोजन के लिए एक शर्त के रूप में और इस न्यायालय द्वारा नहीं।

12. तब सवाल यह है कि देश की न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए कानून के तहत क्या सुरक्षा उपलब्ध है जो आज भी मौजूद है। इसका उत्तर अधिनियम की धारा 6 में है, जो हटाने के लिए सशक्त प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी का प्रावधान करती है न्यायाधीश, हमें अनुच्छेद 124, खंड (4) और (5) पर ले जाता है। चूंकि संविधान ने स्वयं इस प्रावधान को शामिल करके न्यायाधीशों के खिलाफ गंभीर आरोपों से निपटने के मामले में इसे पर्याप्त माना है।

गलत समझा जाए, क्योंकि यह किसी भी अवैध परिणाम, असमर्थ स्थिति या बेतुका परिणाम की ओर नहीं ले जाता है। यह सच है कि सजा के अनुदान में तब तक देरी होगी जब तक कि आरोप की जांच के अनुसार अनुच्छेद 124 के खंड (5) के तहत अधिनियमित कानून, लेकिन एक बार जब वह चरण समाप्त हो जाता है और न्यायाधीश के खिलाफ एक निष्कर्ष दर्ज किया जाता है, तो दोनों मामलों को जोड़ने में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए-यानी हटाने और मंजूरी देना जो स्पष्ट रूप से आपस में जुड़े हुए हैं। होना ही चाहिए।

याद रहे कि अधिनियम की धारा 5 (1) के तहत अभियोजन न्यायाधीश द्वारा असमान रूप से बड़ी राशि के संग्रह को संदर्भित करता है।

जिस अवधि में वे पद पर रहे हैं, उस अवधि के दौरान धन। इसलिए, दोनों मामलों-अभियोजन और निष्कासन-को अलग और एक दूसरे से असंबद्ध नहीं माना जाना चाहिए। अन्यथा, संबंधित न्यायाधीश के लिए यह दावा करने की गुंजाइश बचेगी कि भले ही वह अभियोजन का सामना कर रहा हो या मुकदमे के बाद उसे दोषी ठहराया गया हो, फिर भी वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का हकदार न्यायाधीश बना रहेगा, क्योंकि उसे अपने पद से हटाया नहीं गया है। सुनवाई के दौरान यह कहा गया था कि वास्तव में एक अन्य देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जहां एक न्यायाधीश हालांकि कारावास से दंडित था, वह इस बात पर जोर दे रहा था कि वह अभी भी अपने पद पर बना रहे। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है

इस देश में अनुमति है। ऐसी स्थितियों में शामिल विसंगति के. वीरास्वामी बनाम।

यू. ओ. आई. [ वर्मा, जे। ]

269

दोनों मामलों को मिलाकर और संसद से मंजूरी प्राप्त करके संतोषजनक रूप से हल किया जा सकता है। इस अध्याय को समाप्त करने से पहले मैं फिर से दोहराऊंगा कि यह मुद्दा वर्तमान मामले और इच्छा में उत्पन्न नहीं हो रहा है। इस पर विचार किया जाना चाहिए और अंत में निर्णय तभी लिया जाना चाहिए जब यह सीधे सामने आए। हालांकि, जब से राय व्यक्त की गई है, मुझे खेद है कि मैं खुद को साझा करने की स्थिति में नहीं पाता। मैंने अपने विद्वान भाइयों के प्रति बहुत सम्मान के साथ कुछ महत्वपूर्ण विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता ली है, जो मेरे लिए प्रासंगिक प्रतीत होते हैं।

14. श्री सिब्ल ने इसके बाद तर्क दिया कि अपीलार्थी को नहीं बुलाया गया था

उस संपत्ति का हिसाब देना जो उसके कब्जे में पाई गई थी। धारा 5 (1) (ई) के तहत आवश्यक अवयवों में से एक गर्म संतुष्ट है। इस बिंदु पर भी कोई योग्यता नहीं है। इस धारा में अभियुक्त को नोटिस जारी करने पर विचार नहीं किया गया है। यदि अभियोजन प्राधिकारी एक उपयुक्त जांच करने के बाद, प्रासंगिक दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए और संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ करके, यह राय बनाता है कि अभियुक्त अपने कब्जे में आय से अधिक संपत्ति के संचय का संतोषजनक रूप से हिसाब नहीं दे सकता है तो धारा आकर्षित होती है। अभिलेख स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि सभी उचित कदम उठाने के बाद यह कहा गया था कि अपीलार्थी के कब्जे में

उसके अपने नाम और उसकी पत्नी और दो बेटों के नाम पर पाई गई संपत्ति संबंधित अवधि के दौरान उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से 6 लाख रुपये से अधिक की राशि से अधिक थी और जिसे वह "संतोषजनक रूप से लेखा नहीं दे सकता"।

15. चूँकि मुझे आग्रह किए गए किसी भी बिंदु में कोई योग्यता नहीं मिलती है

अपीलार्थी की ओर से यह अपील खारिज कर दी जाती है:

वर्मा, जे. मैंने अपने सेवानिवृत्त भाइयों की राय का अध्ययन किया है।

बहुमत का गठन करते हुए यह विचार रखते हुए कि खाट की रोकथाम: विघटन अधिनियम लागू होता है। मैं इस विचार को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ: मेरी असहमति की राय केवल अकादमिक है: फिर भी, मैं इसे एक अलग दृष्टिकोण लेने के कारणों के साथ दर्ज करना उचित समझता हूँ। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह प्रश्न न्यायिक निर्धारण के लिए उत्पन्न होना चाहिए। हालांकि, सवाल उठने के बाद हम अपनी राय देने के लिए बाध्य हैं। इस बिंदु के महत्व को ध्यान में रखते हुए, मैं ह्यूज की टिप्पणियों से आश्वस्त अपनी सम्मानजनक असहमति दर्ज करता हूँ कि 'यूनानी'। दया जो केवल औपचारिक है, जो मजबूत, परस्पर विरोधी विचारों की कीमत पर दर्ज की जाती है, अंतिम उपाय की अदालत में वांछनीय नहीं है, उस समय जनमत पर जो भी प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंततः जनता के विश्वास में अदालत को जो बनाए रखना चाहिए वह न्यायाधीशों का चरित्र और स्वतंत्रता है। ..... यह बेहतर है कि उनकी स्वतंत्रता को (1991) 3 एस. सी. आर. की तुलना में बनाए रखा जाए और मान्यता दी जाए।

270

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एकर बलिदानक माध्यमसँ एकरूपता सुनिश्चित कयल जाय '। मैं एक परेशान अनुरूपवादी की तुलना में एक ईमानदार अकेला असहमत होना पसंद करूंगा। इसी भावना में, पूरी विनम्रता के साथ, मैं अपनी असहमति दर्ज करता हूँ।

क्या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसके किसी कनिष्ठ न्यायाधीश

विघटन अधिनियम, 1947 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित)? यह इस अपील में निर्णय के लिए उत्पन्न होने वाला मुख्य प्रश्न है। अपीलार्थी, मद्रास उच्च न्यायालय

के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के. वीरास्वामी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक आवेदन दायर किया।

1973 ( 1978 का अपराधिक एम. पी. सं. 265) सी. सी. में कार्यवाही को रद्द करने के लिए।

विशेष न्यायाधीश, मद्रास के न्यायालय में 1977 का सं. 46 एक आरोप-पत्र पर शुरू किया गया जिसमें उन पर अपराधिक दुराचार के अपराध का आरोप लगाया गया था।

अधिनियम की धारा 5 (1) (ई) के तहत दंडनीय, जैसा कि संशोधित किया गया है। 1964 के संशोधन अधिनियम द्वारा। इस मामले की सुनवाई एक पूर्ण पीठ ने की थी

उच्च न्यायालय ने नटराजन और मोहन, जे. जे. की बहुमत राय के अनुसार दिनांक 1 के आदेश द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया, जबकि बालासुब्रमण्यन, जे. ने असहमति जताई। यह अपील कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 132 (1) और 134 (1) (सी) के तहत उच्च न्यायालय द्वारा दी गई एक प्रमाण पत्र द्वारा की गई है।

निर्णय लेने में शामिल।

भौतिक तथ्य कुछ ही हैं। अपीलार्थी बार में शामिल हुआ

वर्ष 1941 में मद्रास से स्नातक किया और एक आकर्षक अभ्यास था। 1953 में उन्हें सहायक सरकारी प्लीडर के रूप में नियुक्त किया गया और 1959 में उन्हें सरकारी वकील नियुक्त किया गया।

मद्रास में प्लीडर। 20.2.1960 पर, उन्हें बेंच में पदोन्नत किया गया था

मद्रास उच्च न्यायालय का उस न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना। आई. डी. 2 पर, उन्हें मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, जिस पद से वे आई. डी. 1 पर सेवानिवृत्त हुए। उस पर

24.2.1976 , दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अपीलार्थी के खिलाफ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और 28.2.1976 पर, प्रथम

अपीलार्थी पर अपराध का आरोप लगाते हुए सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी धारा 5 (1) (ई) के तहत दंडनीय अपराधिक दुराचार

5 ( 2 ) अधिनियम से। 15.12.1977 दिनांकित एक आरोप-पत्र दायर किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि 1.5.1969 और 24.2.1976 के बीच, जबकि अपीलार्थी सार्वजनिक

था। नौकर, उनके पास अपने नाम और अपनी पत्नी श्रीमती के नाम पर आर्थिक संसाधन और संपत्ति थी। एलुथाई अम्मल और उनके

दो बेटे एस/श्री वी. सुरेश और वी. भास्कर, जो 6,41 रुपये की सीमा तक अयोग्य घोषित किए गए थे। उनके ज्ञात स्रोतों के लिए

उस अवधि के दौरान आय और वह संतोषजनक रूप से लेखा नहीं कर सकता है

ऐसे असमान आर्थिक संसाधन और संपत्ति। आरोप पत्र में यह भी विवरण दिया गया है कि किस आधार पर

संपत्ति का आरोप लगाया गया था।

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. 1. [ वर्मा, जे। ]

271

अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका दायर की। पी. सी. में

उच्च न्यायालय ने उपरोक्त आरोप-पत्र पर मद्रास के विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित अभियोजन को रद्द करने के लिए, जिसके परिणाम ऊपर बताए गए हैं। अपीलार्थी की ओर से उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप सहित कई दलीलें दी गईं। हालाँकि, उन सभी को संदर्भित करना अनावश्यक है क्योंकि हमारे समक्ष अपील की सुनवाई में, अपील लैट का मामला केवल इसके बाद बताए गए आधारों तक ही सीमित था और उच्च न्यायालय में कथित दुर्भावनापूर्ण आधार को स्पष्ट रूप से छोड़ दिया गया था।

श्री कपिल सिब्बल, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने दो अग्रिम दिए

केवल तर्क। उनका पहला तर्क यह है कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अधिनियम के दायरे में नहीं हैं, जो लोक सेवकों के लिए लागू एक विशेष अधिनियम है, जिनके मामले में अधिनियम की धारा 6 के तहत मंजूरी के बाद अभियोजन शुरू किया जा सकता है, जो उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों जैसे संवैधानिक अधिकारियों के लिए परिकल्पित योजना से अलग है। उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित भारत के संविधान के विशेष प्रावधान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वे अधिनियम के दायरे में नहीं हैं और निर्धारित तरीके से उनकी नियुक्ति के बाद, वे पूरी तरह से

कार्यकारी प्रभाव से मुक्त हैं, उनका कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित किया जा रहा है, सिवाय अनुच्छेद 124 (4) द्वारा निर्धारित तरीके से हटाने के। श्री सिब्बल का दूसरा तर्क यह है कि अधिनियम की धारा 5 (1) (ई) में परिभाषित आपराधिक दुराचार के अपराध के आवश्यक तत्वों में से एक, जो इसकी धारा 5 (2) के तहत दंडनीय है, आय से अधिक संपत्ति के कब्जे के लिए संतोषजनक रूप से लेखा देने में अभियुक्त की असमर्थता है, जो आरोप पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों से स्पष्ट होना चाहिए ताकि विशेष न्यायाधीश अपराध का संज्ञान ले सकें और यह तभी संभव हो सकता है जब अभियुक्त को आरोप पत्र दाखिल करने से पहले अपना लेखा देने के लिए कहा जाए। इस आधार पर यह तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 6 के तहत मंजूरी देने की प्रक्रिया

जिसके लिए मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को मंजूरी देने से पहले लोक सेवक के स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, यह इसे व्यवहार्य बनाता है, जो वरिष्ठ न्यायाधीशों के लिए भी इसकी अप्रयोज्यता को दर्शाता है, जिनके मामले में ऐसा कोई सेवा रिकॉर्ड या तंत्र प्रदान नहीं किया गया है। एक तरह से श्री सिब्बल का दूसरा तर्क भी उनके पहले तर्क से जुड़ा हुआ है। श्री सिब्बल ने तर्क दिया कि आपराधिक दुराचार के अपराध के आरोपी वरिष्ठ न्यायाधीशों के अभियोजन और मुकदमे का प्रावधान करने वाली कानून बनाने की वांछनीयता के बावजूद, अधिनियम में निहित मौजूदा कानून उनके लिए लागू नहीं है। जवाब में, विद्वान सॉलिसिटर जनरल, [1991] 3 एस. सी. आर.

272

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिनके बाद विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने दृढ़ता से आग्रह किया कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी 'लोक सेवक' होने के कारण अधिनियम के दायरे में आते हैं, जो परिभाषा 'प्रत्येक न्यायाधीश' को शामिल करने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल के मामले में वरिष्ठ न्यायाधीशों के लिए कोई प्रतिरक्षा नहीं है और,

इसलिए, वरिष्ठ न्यायाधीशों को अधिनियम के दायरे से बाहर रखने का कोई कारण नहीं था। वरिष्ठ न्यायाधीशों के अभियोजन के लिए धारा 6 के तहत मंजूरी की कठिनाई और अनुच्छेद 218 के साथ पठित अनुच्छेद 124 के खंड (4) और (5) में निहित विशेष प्रावधानों के कारण, इसे कोई कठिनाई प्रस्तुत नहीं की गई क्योंकि भारत के राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय और

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में अधिनियम की धारा 6 (1) (सी) के अनुसार मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में माना जा सकता था। विद्वान सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने भी आग्रह किया कि इस मामले में पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाएं।

कार्यकारी प्राधिकार के किसी भी दुरुपयोग या स्वतंत्र न्यायाधीशों के उत्पीड़न को रोकने के लिए इस न्यायालय द्वारा दिशानिर्देशों का सुझाव दिया जाना चाहिए। यह सूग था

उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा अभियोजन के लिए मंजूरी देने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से जुड़े कुछ तंत्र, यहां तक कि अपराध की जांच के लिए भी, इस न्यायालय द्वारा सुझाए जा सकते हैं।

कार्यपालिका द्वारा अंतर्निहित अनुपालन। यह तर्क दिया गया था कि इस तरह से

न्यायपालिका की स्वतंत्रता का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकता है जबकि

वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ भी अधिनियम के दायरे में व्यवहार करना ताकि भ्रष्ट लोगों पर मुकदमा चलाया जा सके और उन्हें सजा दी जा सके।

निर्णय के लिए शामिल बिंदु के महान महत्व को देखते हुए

जो पहली बार उठा है, मामले की सुनवाई विचार पर की गई थी

धूसर क्षेत्रों को रोशन करने में सक्षम लंबाई। सुनवाई में सर्वसम्मति

यह था कि इस दुर्भाग्यपूर्ण विवाद की परिकल्पना पहले नहीं की गई थी

अब उत्पन्न हुआ, हो सकता है, यह समय है कि इसके भीतर एक स्पष्ट प्रावधान किया जाए

से निपटने के लिए एक तंत्र प्रदान करने के लिए संवैधानिक योजना

उच्च न्यायपालिका के भ्रष्ट सदस्य, जो स्वयं के लिए आवश्यक है

न्यायपालिका की स्वतंत्रता का संरक्षण। हालांकि, अंतर

कठोरता में अधिनियमित मशीनरी की पर्याप्तता के संबंध में है

कानून के बारे में जो है और जो होना चाहिए उसके बारे में नहीं। इस उद्देश्य के लिए इस मामले को तय करने के लिए, हमें कानून को देखना होगा जैसा कि अब मौजूद है।

विचार के लिए मुख्य बिंदु यह है कि क्या मुख्य न्यायाधीश

और उच्च न्यायालयों के कनिष्ठ न्यायाधीश इसके दायरे में आते हैं -

एक्ट करें। यह निहित है कि यदि उत्तर सकारात्मक है, तो प्रमुख

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और न्यायाधीश भी इसके अंतर्गत आते हैं -  
अधिनियम की परिधि और इसी तरह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी?

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. [ वर्मा, जे.)

और मुख्य चुनाव आयुक्त, जिनके पद के नियम और शर्तें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हैं। यदि किसी कारण से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और मुख्य चुनाव आयुक्त को अधिनियम के दायरे से बाहर माना जाता है, तो यह स्वयं कुछ समान संवैधानिक अधिकारियों को अधिनियम के दायरे से बाहर करने का संकेत देगा। असली सवाल यह है कि क्या इन संवैधानिक कार्यकर्ताओं को 'लोक सेवक' की परिभाषा में शामिल करने का इरादा था, जैसा कि अधिनियम में परिभाषित किया गया है, और मौजूदा अधिनियमित कानून उस प्रभाव के लिए है। सुनवाई में यह पुरजोर आग्रह किया गया कि उन पर लागू होने वाले ऐसे कानून को लागू करने की वांछनीयता, मुख्य रूप से संसद के लिए एक ऐसा मामला होगा जिस पर विचार किया जाए कि क्या मौजूदा कानून उन पर लागू नहीं होता है जैसा कि अधिनियमित किया गया है। यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार एक शरारत थी जिसे ठीक किया जाना था जब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लागू किया गया था। इस कारण से, इस तरह का कानून होने की अब व्यक्त की गई वांछनीयता मौजूदा कानून के निर्माण में सहायता नहीं हो सकती है ताकि इसके दायरे को बढ़ाया जा सके और इन संवैधानिक अधिकारियों को इसके भीतर लाया जा सके।

न्यायिक शिल्प कौशल की आड़ में पूरी तरह से अस्वीकार्य होगा जो एक वर्जित क्षेत्र में कानून का स्थान नहीं ले सकता है। न्यायिक सक्रियता कमियों की आपूर्ति कर सकती है और पहले से मौजूद संरचना में कमियों को भर सकती है जो कुछ मायनों में कम पाई जाती हैं, लेकिन इसे एक नई इमारत का निर्माण करना बंद करना चाहिए जहां कोई नहीं है। वर्तमान जैसे मामले में, एकमात्र उत्तर एक निश्चित 'हां' या निश्चित 'नहीं' हो सकता है, लेकिन अधिनियम में विधायी आवश्यकताओं को जोड़ने के साथ 'हां' नहीं हो सकता है जो पूरी तरह से अनुपस्थित हैं।

और जिसके बिना जवाब 'हां' नहीं हो सकता है। मेरे सुविचारित विचार में दिशानिर्देशों का अंतर्निहित रूप से पालन किया जाना चाहिए, यदि वे हैं। मौजूदा अधिनियम में कोई स्थान नहीं मिलना और उस आधार पर वरिष्ठ न्यायाधीशों को मौजूदा कानून के दायरे में

लाना, मौजूदा कानून के दायरे से बाहर एक नया कानून बनाने के बराबर होगा और न कि केवल कमियों को पूरा करके इसका अर्थ लगाया जाएगा ताकि इसे अपने अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यवहार्य बनाया जा सके। सुनवाई में यह सुझाव दिया गया कि इस प्रकार सुझाए गए और प्रदान किए गए दिशा-निर्देश, जिनकी सहायता से मौजूदा कानून को वरिष्ठ न्यायाधीशों पर लागू किया जा सकता है, एस. पी. संपत कुमार बनाम में प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम से निपटने के दौरान इस न्यायालय द्वारा किए गए अभ्यास के समान होंगे। भारत संघ और अन्य।, [ 1987 ] 1 एससीसी 124। मुझे डर है कि यह समानता उपयुक्त नहीं है क्योंकि दोनों स्थितियों में कोई समानता नहीं है। जैसा कि अधिनियमित किया गया था, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम कुछ दुर्बलताओं से ग्रस्त पाया गया था जो इसे अमान्य बना देगा और इस तरह अपने अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहेगा जब तक कि उसमें कमियों की आपूर्ति नहीं की गई थी। इस स्थिति को दूर करने के लिए ही इस न्यायालय ने संपत कुमार के मामले में उन दुर्बलताओं को दूर करने के तरीके और साधन सुझाए ताकि उस कानून को लागू करने के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके और इस तरह कानून को [1991] 3 एस. सी. आर. के रूप में व्यवहार्य बनाया जा सके।

274

#### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वैध विधान। यहां की स्थिति पूरी तरह से अलग है। यह अधिनियम अपने दायरे में लोक सेवकों के लिए अपने मौजूदा रूप में पूरी तरह से व्यवहार्य है और इसके अधिनियमन के बाद से बड़ी संख्या में लोक सेवकों के लिए इसे लागू करने में कोई बाधा नहीं है। अब केवल एक ही सवाल उठता है: क्या यह विधान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों जैसे कुछ संवैधानिक अधिकारियों पर भी लागू होता है और यदि उत्तर नकारात्मक है, तो अधिनियम का जीवन किसी भी तरह से खतरे में नहीं पड़ता है। एकमात्र परिणाम यह है कि यदि इस समय वरिष्ठ न्यायाधीशों के लिए भी ऐसा विधान आवश्यक माना जाता है, तो संसद उपयुक्त विधान बनाकर अपना कार्य कर सकती है, क्योंकि यह विधान का एक वर्जिन क्षेत्र है। इसलिए, इस तरह के तर्क की सराहना करना मुश्किल है जब हमारे निर्णय का सवाल केवल उस कानून के निर्माण का है जो इसके संचालन के क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

अब कुछ वैधानिक प्रावधानों का संदर्भ दिया जा सकता है

जिसके आधार पर मुद्दा तय किया जाना है। अधिनियम में दी गई 'लोक सेवक' की परिभाषा में 'प्रत्येक न्यायाधीश' शामिल है। अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) अपने कई खंडों में 'आपराधिक दुराचार' को परिभाषित करती है और इसकी उप-धारा (2) आपराधिक दुराचार के अपराध के लिए सजा निर्धारित करती है। धारा 5 ए इस अधिनियम के तहत मामलों की जांच से संबंधित है और धारा 6 अभियोजन के लिए आवश्यक पूर्व मंजूरी का प्रावधान है। इस प्रकार, कोई भी न्यायालय अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, सिवाय इसके कि अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ए), (बी) और (सी) द्वारा सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के साथ। यही कारण है कि धारा 6 का महत्व है -

अधिनियम की प्रयोज्यता क्योंकि अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी आवश्यक है और ऐसी स्थितियों में जहां ऐसी मंजूरी की परिकल्पना नहीं की जा सकती है, अधिनियम को लागू नहीं किया जा सकता है। 1964 के संशोधन के बाद अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को नीचे उद्धृत किया गया है:

" 2. व्याख्या। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "सार्वजनिक

"सेवक" से धारा 21 में परिभाषित लोक सेवक अभिप्रेत है।

भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)।

XXX

XXX

XXX

4. अनुमान जहाँ लोक सेवक कानूनी पारिश्रमिक के अलावा अन्य अनुग्रह राशि स्वीकार करता है। - ( 1 ) जहाँ भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 161 या धारा 165 या अपराध 275 के तहत दंडनीय अपराध के किसी भी मुकदमे में

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [वर्मा, जे. जे.

इस अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (ए) या खंड (बी) में निर्दिष्ट उप-धारा (2) के तहत दंडनीय है। तत्पश्चात, यह सिद्ध किया जाता है कि किसी अभियुक्त व्यक्ति ने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति से कोई संतुष्टि (कानूनी पारिश्रमिक के

अलावा) या कोई मूल्यवान वस्तु स्वीकार की है या प्राप्त की है, या स्वीकार करने के लिए सहमत हुआ है या प्राप्त करने का प्रयास किया है, यह तब तक माना जाएगा जब तक कि इसके विपरीत यह साबित नहीं हो जाता है कि उसने स्वीकार किया है या प्राप्त किया है, या उस संतुष्टि या उस मूल्यवान वस्तु को प्राप्त करने के लिए सहमत हुआ है या प्राप्त करने का प्रयास किया है जो एक उद्देश्य या पुरस्कार के रूप में हो सकता है जैसे कि

उक्त धारा 161 में उल्लिखित, या, जैसा भी मामला हो, बिना किसी विचार के या ऐसे विचार के लिए जिसे वह अपर्याप्त समझता है।

( 2 ) जहाँ के तहत दंडनीय अपराध के किसी भी मुकदमे में

इस अधिनियम की धारा 5 के खंड (ii) या उप-धारा (3) के तहत यह साबित होता है कि कोई भी संतुष्टि (कानूनी छूट के अलावा) पुनरावृत्ति) या किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा कोई मूल्यवान वस्तु दी गई है या देने की पेशकश की गई है या देने का प्रयास किया गया है, यह तब तक माना जाएगा जब तक कि इसके विपरीत यह साबित नहीं हो जाता है कि उसने दिया या देने की पेशकश की है या उस कृतज्ञता या उस मूल्यवान वस्तु को देने का प्रयास किया है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 161 में उल्लिखित उद्देश्य या पुरस्कार के रूप में या, जैसा भी मामला हो, बिना विचार के या उस विचार के लिए हो जिसे वह अपर्याप्त मानता हो।

( 3 ) उप में कुछ भी निहित होने के बावजूद

धारा (1) और (2), न्यायालय उक्त उप-धाराओं में से किसी में भी निर्दिष्ट अनुमान लगाने से इनकार कर सकता है, यदि उसकी राय में, उपरोक्त संतुष्टि या बात इतनी तुच्छ है कि भ्रष्टाचार का कोई निष्कर्ष उचित रूप से नहीं निकाला जा सकता है।

5. अपराधिक दुराचार। - ( 1 ) एक लोक सेवक को कहा जाता है कि

आपराधिक दुराचार का अपराध करना

( क ) यदि वह आदतन स्वीकार करता है या प्राप्त करता है या सहमत होता है किसी भी व्यक्ति से स्वीकार या प्राप्त करने का प्रयास करना

स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, कोई भी संतुष्टि

पुरस्कार जैसे कि धारा 161 में उल्लिखित है

भारतीय दंड संहिता (1860 का 45), या सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1991]  
3 एस. सी. आर.

(ख) यदि वह आदतन स्वीकार करता है या प्राप्त करता है या स्वीकार करने के लिए सहमत होता है या अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो बिना किसी विचार के या किसी ऐसे विचार के लिए जो वह जानता है किसी भी व्यक्ति से अपर्याप्त जिसे वह जानता है

उसके द्वारा लेन-देन किया गया, या अपने या किसी लोक सेवक, जिसके वह अधीनस्थ है, के आधिकारिक कार्यों से कोई संबंध रखने वाला, या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे वह इस तरह से संबंधित व्यक्ति में रुचि रखने या उससे संबंधित होने के लिए जानता है, या

(ग) यदि वह बेईमानी से या धोखाधड़ी से दुरुपयोग करता है या अन्यथा लोक सेवक के रूप में उसे सौंपी गई या अपने नियंत्रण में किसी संपत्ति को अपने उपयोग के लिए परिवर्तित करता है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति देता है, या

(घ) यदि वह भ्रष्ट या अवैध तरीकों से या अन्यथा लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करता है,

स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या

आर्थिक लाभ, या

(ङ) यदि

वह या उसकी ओर से कोई व्यक्ति अपने पद की अवधि के दौरान किसी भी समय आर्थिक संसाधनों या संपत्ति के कब्जे में है या उसके कब्जे में है, जिसके लिए लोक सेवक संतोषजनक रूप से जिम्मेदार नहीं हो सकता है।

अपने ज्ञात स्रोतों से असंगत

आय।

(2) कोई भी लोक सेवक जो आपराधिक दुराचार करता है, वह एक वर्ष से कम की अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, लेकिन जो सात वर्ष तक बढ़ सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा:

बशर्ते कि न्यायालय, लिखित रूप में अभिलिखित किसी विशेष कारण के लिए, कारावास की सजा दे सकता है -

एक वर्ष से कम।

XXX

XXX

XXX

5 ए. इस अधिनियम के तहत मामलों की जांच। - ( 1 )

अपराध संहिता 277 में कुछ भी निहित होने के बावजूद

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [वर्मा, जे.]

एन. ए. एल. प्रक्रिया, 1898 (1898 का 5), पद से नीचे का कोई पुलिस अधिकारी नहीं,

( क ) दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के मामले में

एक पुलिस निरीक्षक का;

( ख ) प्रेसीडेंसी में-कलकत्ता और मद्रास के शहर,

सहायक पुलिस आयुक्त;

पुलिस की प्रवृत्ति; और

( घ)

कहीं और, पुलिस उपाधीक्षक का,

भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 161, धारा 165 या धारा 165 ए के तहत या इस अधिनियम की धारा 5 के तहत राष्ट्रपति मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, जैसा भी मामला हो, दंडनीय किसी भी अपराध की जांच करेगा या वारंट के बिना उसके लिए कोई गिरफ्तारी करेगा:

बशर्ते कि यदि कोई पुलिस अधिकारी के पद से नीचे नहीं है

पुलिस निरीक्षक राज्य सरकार द्वारा अधिकृत होता है।

इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, वह प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, जैसा भी मामला हो, ऐसे किसी भी अपराध की जांच कर सकता है या बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है:

बशर्ते कि खंड में निर्दिष्ट अपराध

( ई ) धारा 5 की उप-धारा (1) की जाँच पुलिस अधीक्षक के पद से कम के पुलिस अधिकारी के आदेश के बिना नहीं की जाएगी।

( 2 ) यदि, प्राप्त या अन्यथा जानकारी से,

पुलिस अधिकारी के पास किसी अपराध के होने पर संदेह करने का कारण है, जिसे वह उप-धारा (1) के तहत जांच करने का अधिकार रखता है और मानता है कि ऐसे अपराध की जांच या जांच के उद्देश्य से किसी भी बैंकर के बही का निरीक्षण करना आवश्यक है, फिर, उस समय लागू किसी भी कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, वह किसी भी बैंकर के बही का निरीक्षण कर सकता है जहां तक वे खातों से संबंधित हैं। उस अपराध को करने के लिए संदिग्ध व्यक्ति का या किसी अन्य व्यक्ति का जो [1991] 3 एस. सी. आर. पर धन रखने का संदेह है।

#### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऐसे व्यक्ति की ओर से, और उससे प्रासंगिक प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतियां लें या लें, और संबंधित बैंक इस उप-धारा के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए बाध्य होगा:

बशर्ते कि रिले में इस उप-धारा के तहत कोई शक्ति न हो

किसी भी व्यक्ति के खातों का प्रयोग पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जब तक कि वह पुलिस अधीक्षक के या उससे ऊपर के पद के पुलिस अधिकारी द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत न हो।

स्पष्टीकरण। इस उप-खंड में, अभिव्यक्तियाँ

" बैंक "और" बैंकरों की पुस्तकों "का वही अर्थ होगा जो उन्हें बैंकरों की पुस्तक साक्ष्य अधिनियम, 1891 (1891 का 18) में दिया गया है।

6. अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी आवश्यक है। — ( 1 )

कोई भी अदालत भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 161 या धारा 164 या धारा 165 के तहत या इस अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3 ए) के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगी, जो एक लोक सेवक द्वारा कथित रूप से किया गया है।

( ए ) एक व्यक्ति के मामले में जो कॉन में कार्यरत है

संघ के मामलों के साथ संबंध और नहीं है

अपने कार्यालय से हटाने योग्य, सैनिक द्वारा या उसके साथ बचाएँ

केंद्र सरकार, केंद्र सरकार

सरकार;

( बी )

एक व्यक्ति के मामले में जो कॉन में कार्यरत है

राज्य के मामलों के साथ संबंध और हटाया नहीं जाता है  
द्वारा या उसकी मंजूरी के साथ अपने कार्यालय से बचत करने में सक्षम

राज्य सरकार, राज्य सरकार की;

(( ग ) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, प्राधिकरण का

उसे अपने कार्यालय से हटाने के लिए सक्षम ।

( 2 ) जहाँ किसी भी कारण से कोई संदेह हो

यदि उप-धारा (1) के तहत अपेक्षित पूर्व मंजूरी केंद्र या राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा दी जानी चाहिए, तो ऐसी मंजूरी उस सरकार या प्राधिकरण द्वारा दी जाएगी जो के. वीरास्वामी v.

यू. ओ. आई. [वर्मा, जे.]

279

लोक सेवक को अपने कार्यालय से हटाने के लिए याचिकाकर्ता

समय जब अपराध का आरोप लगाया गया था

प्रतिबद्ध " ।

भारत के संविधान के प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं:

" 121. संसद में चर्चा पर प्रतिबंध । - कोई डिस्कस नहीं

संघ के संबंध में संसद में बैठक होगी

उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का डक्ट के लिए एक प्रस्ताव को छोड़कर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में

राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हुए एक संबोधन प्रस्तुत करना

न्यायाधीश को हटाना जैसा कि इसके बाद प्रावधान किया गया है।

XXX

XXX

XXX

124. सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और संविधान

अदालत। ( 1 ) ..... ..

XXX

XXX

XXX

( 4 ) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होगा

संसद के प्रत्येक सदन के अभिभाषण के बाद उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित राष्ट्रपति के आदेश को छोड़कर उन्हें अपने पद से हटा दिया गया है ताकि साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर इस तरह के निष्कासन के लिए उसी सत्र में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जा सके।

( 5 ) संसद विधि द्वारा प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है -

खंड (4) के तहत किसी न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच और प्रमाण के लिए एक पते की प्रस्तुति।

XXX

XXX

XXX

148. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक-भारत के।

( 1 ) भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हाथ और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाएगी और उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसी तरह और उसी आधार पर पद से हटाया जाएगा। XXX

XXX

XXX सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1991] 3 एस. सी. आर.

211. विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध। — उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आचरण के संबंध में किसी राज्य के विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं होगी। XXX

XXX

XXX

218. संबंधित कुछ प्रावधानों का अनुप्रयोग

उच्चतम न्यायालय से उच्च न्यायालयों तक। अनुच्छेद 124 के खंड (4) और (5) के प्रावधान उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होंगे क्योंकि वे उच्चतम न्यायालय के संबंध में लागू होते हैं और उच्चतम न्यायालय को किराए के लिए उच्च न्यायालय के संदर्भ के प्रतिस्थापन के साथ लागू होते हैं।

XXX

XXX

XXX

324. निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण

निर्वाचन आयोग में निहित किए जाने वाले कार्य। - ( 1 )

XXX

XXX

XXX

( 5 ) द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन  
संसद, चुनाव आयोगों और क्षेत्रीय आयोग की सेवा की शर्तों और कार्यकाल  
वे ऐसे होंगे जो राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करे:

बशर्ते कि मुख्य चुनाव आयुक्त

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से और समान आधारों के अलावा उसे अपने  
पद से नहीं हटाया जाएगा और मुख्य चुनाव आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद  
उसके नुकसान के लिए बदलाव नहीं किया जाएगा:

बशर्ते कि कोई अन्य चुनाव आयोग

निदेशक या क्षेत्रीय आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा पद से नहीं  
हटाया जाएगा।

XXX

XXX

XXX

361. राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण और  
राजप्रमुख। --- ( 1 ) राष्ट्रपति, या राज्यपाल या 281

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [वर्मा, जे.]

किसी राज्य के राजप्रमुख, किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे।

शक्तियों के प्रयोग और निष्पादन के लिए न्यायालय और

उसके कार्यालय के कर्तव्यों या किए गए या किए जाने वाले किसी कार्य के लिए

उनके अभ्यास और प्रदर्शन में उनके द्वारा किया गया

शक्तियाँ और कर्तव्य:

बशर्ते कि राष्ट्रपति का आचरण हो सकता है

किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या निकाय द्वारा समीक्षा के तहत लाया गया संसद के किसी भी सदन द्वारा नियुक्त या नामित

अनुच्छेद 61 के तहत आरोप की जांच:

बशर्ते कि इस खंड में कुछ भी नहीं होगा

भारत सरकार के खिलाफ उचित कार्यवाही या किसी राज्य की सरकार।

( 2 ) कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं होगी

किसी राज्य की सरकार, उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में कार्यालय।

( 3 ) गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई प्रक्रिया नहीं

राष्ट्रपति, या किसी राज्य का राज्यपाल, किसी से जारी करेगा

उनके कार्यकाल के दौरान अदालत।

( 4 ) कोई दीवानी कार्यवाही नहीं जिसमें राहत का दावा किया गया हो।

राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, के संबंध में किसी भी न्यायालय में अपने पद की अवधि के दौरान स्थापित

उसके द्वारा किया गया या किया जाना अभिप्रेत कोई कार्य

व्यक्तिगत क्षमता, चाहे वह प्रवेश करने से पहले हो या बाद में

राष्ट्रपति के रूप में या ऐसे राज्य के राज्यपाल के रूप में उसका पद, जब तक

लिखित सूचना के बाद अगले दो महीने की समाप्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंप दिया गया है, जैसा कि

मामला हो सकता है, या उसकी प्रकृति बताते हुए उसके कार्यालय में छोड़ दिया जा सकता है

कार्यवाही, इसलिए कार्रवाई का कारण, नाम,

पार्टी का विवरण और निवास स्थान जिसके द्वारा ऐसी कार्यवाहियां शुरू की जानी हैं और राहत जो

वह दावा करता है "।

यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 ने संसद द्वारा प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए

न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या अक्षमता का प्रमाण

न्यायालय या उच्च न्यायालय और [1991] 3 एस. सी. आर. की प्रस्तुति के लिए।

282

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संसद द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित करना और संबंधित मामलों के लिए इसके साथ, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 (5) द्वारा अनुध्यात है। इन प्रावधानों की पृष्ठभूमि में ही हमारे निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले बिंदु पर निर्णय लेना है।

मैं इस स्तर पर उनके द्वारा की गई सिफारिशों का भी उल्लेख कर सकता हूँ।

संथानम समिति जो अधिनियम में 1964 के संशोधन से पहले थी। यह 1964 के संशोधन के परिणामस्वरूप है कि अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) में खंड (ई) जोड़ा गया था ताकि एक लोक सेवक द्वारा आय से अधिक संपत्ति के कब्जे को स्वयं एक मूल संपत्ति बनाया जा सके।

आपराधिक दुराचार का अपराध, जबकि इस संशोधन से पहले ऐसा

प्रावधान केवल धारा 5 की उप-धारा (3) में निहित साक्ष्य का एक नियम था जैसा कि शुरू में अधिनियमित किया गया था जो तब केवल धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (ए) से (डी) में परिभाषित आपराधिक दुराचार के अपराध को साबित करने के लिए उपलब्ध था। संथानम समिति की रिपोर्ट में न्यायपालिका से संबंधित कुछ अंश जो हमारे सामने प्रश्न पर प्रकाश डाल सकते हैं, निम्नानुसार निकाले गए हैं:

" धारा 12

असंसदीय

XXX

XXX

XXX

## 12.2 हमने न्यायपालिका को शामिल नहीं किया

हमारे संदर्भ में। सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर और केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ अधीनस्थ अदालतें,

भारत सरकार का इससे कोई सीधा संबंध नहीं है

की नियुक्ति को छोड़कर न्यायपालिका का प्रशासन

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाते हैं। होना ही चाहिए।

केंद्र और राज्यों को भेज सकते हैं और मनोरंजन कर सकते हैं विशेष रूप से केंद्रीय विषयों से संबंधित मामलों का निर्णय लेना। वहाँ

सबसे पहले, न्यायपालिका की अखंडता सर्वोपरि है यहां तक कि केंद्र सरकार के उचित कामकाज के लिए भी।

हालाँकि हमने कोई सीधी पूछताछ नहीं की, हम थे

सतर्कता सहित जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा सूचित और

विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिकारी कि भ्रष्टाचार मौजूद है

पूरे भारत में न्यायपालिका के निचले पदों पर और कुछ में

स्थानों पर यह उच्च पदों पर भी फैल गया है। हम गहरे थे

इस जानकारी से दुखी हूँ। इसलिए हम सुझाव देते हैं कि मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के मुख्य न्यायाधीश 283

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [वर्मा, जे.]

उच्च न्यायालयों को न्यायपालिका के बीच भ्रष्टाचार की घटनाओं की गहन जांच की व्यवस्था करनी चाहिए और केंद्र और राज्य सरकार के परामर्श से इसका विकास करना चाहिए। इसे

रोकने और समाप्त करने के लिए उचित उपाय। शायद भारत के मुख्य न्यायाधीश के तहत एक केंद्रीय सतर्कता अधिकारी द्वारा समन्वित प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के प्रत्यक्ष नियंत्रण में सतर्कता संगठन की स्थापना एक उपयुक्त तरीका साबित हो सकता है।

XXX

XXX

XXX

निष्कर्ष

और

सारांश

ओ.

सिफारिशें

XXX

XXX

XXX 117. भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की घटनाओं की गहन जांच की व्यवस्था करनी चाहिए और केंद्र और राज्य सरकारों के परामर्श से इसे रोकने और समाप्त करने के लिए उचित उपाय करने चाहिए। शायद भारत के मुख्य न्यायाधीश के तहत एक केंद्रीय सतर्कता अधिकारी द्वारा समन्वित प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के प्रत्यक्ष नियंत्रण में सतर्कता संगठनों की स्थापना एक उपयुक्त तरीका साबित हो सकता है।

( पैरा। 12. 2)

XXX

XXX

XXX

सरकारी सेवाओं पर रिपोर्ट '

नियमों का पालन करें

XXX

XXX

XXX

## नियम 15

## 15. समिति बहुत महत्व देती है कि

सरकार द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण और निपटान से संबंधित मौजूदा नियम 15 में अनुशंसित परिवर्तन वेंट्स। एक ओर, ये रिपोर्ट भ्रष्टाचार के खिलाफ एक रोक के रूप में काम करती हैं और दूसरी ओर, ईमानदार सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रतिबंधों [1991] 3 एस. सी. आर. के अधीन होना परेशान करने वाला हो सकता है।

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अन्य नागरिकों पर थोपा नहीं गया। यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि रिपोर्टें उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हों जिसके लिए वे प्राप्त की गई हैं। इसके अलावा, उन सरकारी कर्मचारियों से कोई रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है जिनके पास गैरकानूनी तरीकों से खुद को समृद्ध करने का कोई अवसर नहीं है।

## 16. कॉम द्वारा किया गया सबसे महत्वपूर्ण बदलाव

इस नियम में निहित राशि परिसंपत्तियों और देनदारियों के पूर्ण आवधिक विवरण द्वारा वार्षिक अचल संपत्ति वापसी का प्रतिस्थापन है। देश में अब प्राप्त होने वाली परिस्थितियों में, अचल संपत्ति वापसी का बहुत अधिक महत्व नहीं रहा है। समिति का मानना है कि सरकार को यह पता लगाने में सक्षम बनाने के लिए कि क्या किसी सरकारी कर्मचारी के पास अनुचित संपत्ति है

आय के अपने ज्ञात स्रोतों के बारे में या चाहे वह कर्ज में डूबा हुआ हो, यह आवश्यक है कि सरकारी कर्मचारी अपनी संपत्ति का पूरा विवरण प्रस्तुत करे और समय-समय पर देनदारियाँ।

## 17. समिति का मानना है कि केवल अधिक

चल संपत्ति की महत्वपूर्ण वस्तुओं को विशेष रूप से सूचित किया जाना चाहिए और यह पर्याप्त होगा यदि सरकारी कर्मचारी दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे कपड़े, बर्तन, क्रॉकरी, किताबें आदि

को छोड़कर अन्य चल संपत्ति के कुल मूल्य की रिपोर्ट करें। लेकिन यह आवश्यक है कि चल संपत्ति का मूल्य परिसंपत्तियों और देनदारियों के विवरण में बताया जाना चाहिए।

#### 18. समिति ने इस तर्क पर विचार किया कि

परिसंपत्तियों और देनदारियों की आवधिक विवरणी जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और यह पर्याप्त होगा यदि ऐसा विवरण प्रविष्टि पर या बाद में एक बार दिया जाए।

इन नियमों की घोषणा और उसके बाद यह पर्याप्त होना चाहिए यदि सरकारी कर्मचारी को अचल संपत्ति में सभी लेनदेन और एक निर्दिष्ट मूल्य से अधिक चल संपत्ति में सभी लेनदेन की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। समिति ने यह सिफारिश करने का निर्णय लिया कि सरकारी कर्मचारियों को परिसंपत्तियों और देनदारियों का आवधिक विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों से लगातार हो रहे सभी असंख्य सक्षम छोटे लेनदेनों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता उचित नहीं होगी। लेकिन चूंकि ये छोटे लेनदेन संचयी रूप से बड़े हो सकते हैं और उनकी वित्तीय स्थिति पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए इसका उद्देश्य 285 होगा।

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [वर्मा, जे.]

बार-बार होना और यह शायद पर्याप्त हो सकता है यदि वे हैं पाँच साल में एक बार प्रस्तुत किया जाता है।

#### 19. एक और बिंदु जिस पर कॉम द्वारा विचार किया गया था

समिति यह थी कि क्या आभूषणों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

चल संपत्ति की परिभाषा। समिति ने माना

मैं सेवक हूँ। लेकिन आभूषण महत्वपूर्ण संपत्ति हैं और यदि चल संपत्ति की परिभाषा से बाहर रखा गया है, तो

सरकारी कर्मचारी द्वारा जमा की गई तुलनपत्र

सही तस्वीर नहीं दी।

( जोर दिया

गया)

आर. एस. नायक बनाम मामले में संविधान पीठ के निर्णय को ध्यान में रखते हुए।

ए. आर. अंतुले, [1984] 2 एस. सी. सी. 183 जिसकी शुद्धता हमारे समक्ष विवादित नहीं थी, हमें इस मामले के उद्देश्य के लिए यह मान लेना होगा कि अपीलार्थी के अभियोजन के लिए अधिनियम की धारा 6 के तहत किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि अपराध का संज्ञान लेने के बाद से

अपीलार्थी ने अपनी सेवानिवृत्ति पर 7.4.1976 पर मुख्य न्यायाधीश का पद धारण करना बंद कर दिया। तथापि, यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपीलार्थी पर अधिनियम के लागू होने के प्रश्न का निर्णय करने के उद्देश्य से, जिस कार्यालय के संदर्भ में अधिनियम के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है, ऐसे पद धारण करने वाले व्यक्ति के अभियोजन के लिए अधिनियम की धारा 6 के तहत मंजूरी देने की व्यवहार्यता पर विचार करना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, तर्क यह है कि इस तथ्य के बावजूद कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति के बाद उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी, अधिनियम की धारा 6 के तहत मंजूरी देने की आवश्यकता और व्यवहार्यता यदि उस पर उसकी सेवानिवृत्ति से पहले मुकदमा चलाया गया था, तो यह एक न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठे व्यक्ति के लिए अधिनियम की प्रयोज्यता निर्धारित करने की परीक्षा है। यह तर्क दिया जाता है कि यदि अपराध के लिए पदधारी के अभियोजन के लिए अधिनियम की धारा 6 के तहत मंजूरी देना संभव या परिकल्पित नहीं है, तो स्पष्ट संकेत यह है कि इस तरह के पद का धारक अधिनियम के दायरे में नहीं आता है। धारा के तहत दंडनीय अपराध के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश के अभियोजन के लिए धारा 6 के तहत मंजूरी देने का सवाल

5 ( 2 ) इसलिए, इस अपील में मुख्य प्रश्न का निर्णय करने के लिए अधिनियम का काफी महत्व है।

/ धारा 6 की उप-धारा (1) में खंड (ए), (बी) और (सी) में [1991] 3 एस. सी. आर. का उल्लेख है।

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह इस प्रकार है कि अधिनियम के दायरे में आने वाले लोक सेवक को निश्चित रूप से धारा 6 की उप-धारा (1) के तीन खंडों में से एक के दायरे में आना चाहिए। यह इस प्रकार है कि किसी पद के धारक को, भले ही अधिनियम की परिभाषा के अनुसार एक लोक सेवक हो, जो धारा 6 की उप-धारा (1) के किसी भी खंड (ए), (बी) या (सी) के अंतर्गत नहीं आता है, इस विशेष अधिनियम के बाद से अधिनियम के दायरे से बाहर माना जाना चाहिए। अधिनियम में लोक सेवक की व्यापक परिभाषा के बावजूद लोक सेवकों की उस श्रेणी को शामिल करने के लिए अधिनियमित नहीं किया गया था: यही एकमात्र तरीका है जिससे अधिनियम के इन प्रावधानों को सुसंगत बनाया जा सकता है और पूर्ण प्रभाव दिया जा सकता है। अधिनियम की योजना यह है कि एक लोक सेवक जो आपराधिक दुराचार का अपराध करता है; जैसा कि कई खंडों में परिभाषित किया गया है

धारा 5 की उप-धारा (1) में अपराध की जांच के बाद धारा 5 की उप-धारा (2) के अनुसार दंडित किया जा सकता है।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित परीक्षण में अधिनियम की धारा 6 के तहत प्राप्त सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के साथ। धारा 6 के तहत पूर्व मंजूरी का अनुदान अधिनियम के दायरे में आने वाले लोक सेवक के अभियोजन के लिए एक पूर्व शर्त होने के कारण, यह पालन करना चाहिए कि एक पद का धारक जो अधिनियम में अभिव्यक्ति की व्यापक परिभाषा के अनुसार एक सार्वजनिक सेवक हो सकता है, लेकिन जिसकी अभियोजन के लिए मंजूरी देने की श्रेणी अधिनियम की धारा 6 द्वारा परिकल्पित नहीं है, वह अधिनियम के दायरे से बाहर है, जिसका उद्देश्य अधिनियम के दायरे में आना नहीं है। यह एकमात्र तरीका है जिसमें उस अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से अधिनियम के प्रावधानों का एक सामंजस्यपूर्ण संविधान बनाया जा सकता है। यह वर्तमान जैसे मामले के लिए भी स्पष्ट निष्कर्ष प्रतीत होता है जहां अंतुले में लिए गए दृष्टिकोण पर अभियोजन के लिए ऐसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, और हमारे सामने चुनौती नहीं दी गई है, कि धारा 6 के तहत अभियोजन के लिए मंजूरी आवश्यक नहीं है जब आरोपी के विचाराधीन पद पर बने रहने के बाद अपराध का संज्ञान लिया जाता है:

इस संदर्भ में, आर. एस. नायक बनाम में की गई धारा 6 के विश्लेषण को याद करना उपयोगी है। ए. आर. अंतुले, [1984] 2 एस. सी. सी. 183, जो इस प्रकार है:

1947 के अधिनियम की धारा 161, 164 और 165 1 पीसी और धारा 3 में निर्धारित अपराधों का लोक सेवक के पद के साथ घनिष्ठ और अविभाज्य संबंध है। एक लोक सेवक पद धारण करता है जो उसे एक लोक सेवक बनाता है और 287

के. वीरास्वामी बनाम। यू. ओ. 1. [ वर्मा, जे। ]

कार्यालय पर कब्जा करने के साथ कार्यालय को प्रदत्त शक्तियां होती हैं। आम तौर पर एक दोहरे व्यक्ति को शक्ति प्रदान नहीं की जाती है। कानून के शासन द्वारा शासित समाज में शक्ति पद पर प्रदान की जाती है या वैधानिक स्थिति द्वारा अर्जित की जाती है और जिस व्यक्ति को पद पर कब्जा है या जिसका दर्जा लाल है, उसे पद की शक्ति या स्थिति से बहने वाली शक्ति प्राप्त होती है। अकेले पद धारक को इसका विरोध करना होगा

कार्यालय का दुरुपयोग या दुरुपयोग करना। ये खंड एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सत्यवाद को संहिताबद्ध करते हैं कि शक्ति में टूटने की प्रवृत्ति होती है। यह पद धारण करना है जो भ्रष्ट उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करने का अवसर देता है। इसलिए, भ्रष्ट आचरण सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और कार्यालय को प्रदत्त शक्ति से प्रवाहित होता है। व्यक्ति और उसके द्वारा धारण किए गए पद के बीच अंतर्संबंध और अंतर्संबंध विचाराधीन है और अलग नहीं किया जा सकता है। धारा 6 की उप-धारा (1) बी. एफ. के तीन खंडों में से प्रत्येक में 'कार्यालय' अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है और मंजूरी देने की शक्ति लोक सेवक को उसके कार्यालय से हटाने के लिए प्राधिकरण को प्रदान की गई है और धारा 6 में लोक सेवक द्वारा किए गए अपराधों का संज्ञान लेने से पहले मंजूरी की आवश्यकता है। लोक सेवक द्वारा पद की शक्ति का दुरुपयोग या दुरुपयोग करके अपराध किया जाएगा और उस पद से प्राधिकरण को उसे हटाने के लिए बाध्य होना चाहिए ताकि वह मंजूरी देने का हकदार हो। हटाए जाने से पद और पद धारक द्वारा दुरुपयोग के बीच अंतर्संबंध समाप्त हो जाएगा। पद से हटाने से दुरुपयोग के अवसर के साथ सत्ता और पद धारक के बीच का संबंध टूट जाएगा। इसलिए, जब किसी लोक सेवक पर अन्य संतुष्टि लेने के अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो उसके लिए कानूनी पारिश्रमिक

एक आधिकारिक कार्य (धारा 161 (आई. पी. सी.) या एक लोक सेवक के रूप में करना या करने के लिए पूर्वाभास करना दंडनीय अपराधों को बढ़ावा देता है। धारा 161 और 163 (आई. पी. सी. की धारा 164) या लोक सेवक के रूप में ऐसे लोक सेवक (आई. पी. सी. की धारा 165) द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही या व्यवसाय में संबंधित व्यक्ति से विचार किए बिना कोई मूल्यवान वस्तु प्राप्त करता है या आपराधिक अपराध करता है।

1947 के अधिनियम की धारा 5 में परिभाषित आचरण, यह विभिन्न अपराधों में निहित है कि लोक सेवक ने लोक सेवक के रूप में अपने द्वारा आयोजित पद की शक्ति का दुरुपयोग या दुरुपयोग किया है। धारा 6 (1) के तीन उपखंडों में 'पद' अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से उस पद को

दर्शाती है जिसका लोक सेवक ने भ्रष्ट उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया या दुरुपयोग किया जिसके लिए उस पर मुकदमा चलाया जाना है और जिसके संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पर मुकदमा चलाने की मंजूरी आवश्यक है।

उसे उस पद से हटाने का अधिकार है जिसका उसने दुरुपयोग किया है। कार्यालय और उसके दुरुपयोग के बीच यह अंतर्संबंध यदि टूट जाता है तो धारा 6 का कोई अर्थ नहीं होगा। और यह अंतर्संबंध स्पष्ट रूप से धारा 6 में प्रावधान की समझ के लिए एक संकेत प्रदान करता है जो एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी प्रदान करता है जो लोक सेवक द्वारा लोक सेवक के खिलाफ अपराधों का संज्ञान लेने के लिए, मंजूरी देकर, प्रतिबंध को हटाने से पहले लोक सेवक की कार्रवाई का न्याय करने में सक्षम होगा। इसलिए, यह निर्विवाद रूप से इस प्रकार है कि मुकदमा चलाने की मंजूरी लोक सेवक को उस पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है जिसका उसने दुरुपयोग किया है, या दुरुपयोग किया है क्योंकि केवल वही प्राधिकारी यह जानने में सक्षम होगा कि क्या लोक सेवक द्वारा पद का दुरुपयोग या दुरुपयोग किया गया है, न कि किसी पद के बाहरी व्यक्ति द्वारा। निर्णयों के एक समूह द्वारा, इसने यह अभिनिर्धारित किया है कि मंजूरी देने के हकदार प्राधिकारी को मंजूरी के अनुसार मामले के तथ्यों, एकत्र किए गए साक्ष्य और अन्य आनुषंगिक तथ्यों पर अपना दिमाग लगाना चाहिए। मंजूरी एक निष्क्रिय औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक गंभीर और पवित्र कार्य है जो तुच्छ अभियोजनों के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा की छत्रछाया को हटा देता है और इसलिए जनता के खिलाफ कोई भी अभियोजन शुरू करने से पहले उपरोक्त आवश्यकताओं का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। ( मोहम्मद को देखें। इकबाल अहमद बनाम। ए. पी. राज्य, [1979] 2 एस. सी. आर. 1007: [ 1979 ] 4 एससीसी 172: [ 1979 ] एससीसी (सी. आर. आई.) 926: ए. आई. आर 1979 एस. सी. 677)। विधायिका ने सलाह देकर शक्ति प्रदान की

लोक सेवक को कार्यालय से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी पर इस स्पष्ट कारण से मंजूरी देने के लिए कि केवल वही प्राधिकारी, जब तथ्य और साक्ष्य उसके सामने रखे जाते हैं, यह निर्णय करने में सक्षम होगा कि क्या कोई गंभीर अपराध किया गया है या अभियोजन पक्ष या तो तुच्छ है या सट्टा है। केवल वही प्राधिकारी यह निर्णय करने में सक्षम होगा कि क्या कथित तथ्यों के आधार पर लोक सेवक द्वारा धारण किए गए पद का दुरुपयोग या दुरुपयोग हुआ है। वह प्राधिकरण यह जानने की स्थिति में होगा कि लोक सेवक द्वारा धारण किए गए पद को कौन सी शक्ति प्रदान की गई थी, उस शक्ति का भ्रष्ट उद्देश्य के लिए दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है और क्या प्रथम दृष्टया ऐसा किया गया है। केवल उसी सक्षम प्राधिकारी को पता होगा कि पद धारण करने वाले लोक सेवक द्वारा किस प्रकार और किस प्रकार कार्य किए जाते हैं और क्या

उनका दुरुपयोग किया गया है या उनका दुरुपयोग किया गया है। यह ऊर्ध्वाधर पदानुक्रम शर्त है जो लोक सेवक को उस पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी और 289 द्वारा आयोजित पद की प्रकृति है।

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [वर्मा, जे.]

लोक सेवक जिनके खिलाफ मंजूरी मांगी जाती है जो

एक पदानुक्रम को इंगित करें और जो इसलिए अनुमति देगा

के कार्यों और कर्तव्यों के बारे में ज्ञान का अनुमान

पद और लोक सेवक द्वारा इसका दुरुपयोग या दुरुपयोग। वह यह है कि

विधानमंडल ने स्पष्ट रूप से यह अधिकार क्यों दिया कि

केवल मंजूरी देने के लिए सक्षम होगा जो है

लोक सेवक को हटाने का अधिकार जिसके खिलाफ बर्खास्त किया जाता है कार्यालय से इसकी मांग की जाती है।

( जोर दिया

गया)

( पैरा 23, पृ.

204-206 )

अंतुले में उपरोक्त उद्धरण से यह महत्वपूर्ण है कि

लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए अधिनियम की धारा 6 के तहत मंजूरी देने का उद्देश्य, 'लोक सेवक को उस पद से हटाने के लिए प्राधिकरण के बीच एक ऊर्ध्वाधर पदानुक्रम और लोक सेवक द्वारा धारण किए गए पद की प्रकृति जिसके खिलाफ मंजूरी मांगी गई है' की स्पष्ट रूप से परिकल्पना की गई है और इसलिए, लोक सेवक को उस पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी को उस पदानुक्रम में ऊर्ध्वाधर रूप से श्रेष्ठ होना चाहिए जिसमें कार्यालय मौजूद है और उसे बर्खास्तगी देकर अवरोधक को हटाने से पहले लोक सेवक की कार्रवाई का न्याय करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, धारा 6 केवल उन मामलों में लागू होती है जहां सार्वजनिक

कार्यालयों का एक ऊर्ध्वाधर पदानुक्रम होता है और लोक सेवक जिसके खिलाफ मंजूरी मांगी जाती है, उस पदानुक्रम में मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के अधीन होता है। यह इस बात का पालन करेगा कि जहां लोक सेवक द्वारा आयोजित पद एक ऊर्ध्वाधर पदानुक्रम का हिस्सा नहीं है जिसमें ऊपर एक प्राधिकरण है

7

उस पदानुक्रम में लोक सेवक का, धारा 6 की योजना द्वारा, कोई आवेदन नहीं हो सकता है और ऐसे पद का धारक जिसके पास ऐसे किसी पदानुक्रम के अभाव में उससे ऊपर कोई ऊर्ध्वाधर नहीं है, अधिनियम के दायरे में नहीं हो सकता है, अधिनियम की परिकल्पना या अधिनियमन ऐसे सार्वजनिक पद के धारक के लिए नहीं किया जा रहा है। इस न्यायालय के निर्णयों ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश एक संवैधानिक पदाधिकारी है, भले ही वह एक सार्वजनिक पद धारण करता हो और उस अर्थ में, 'लोक सेवक' की व्यापक परिभाषा में शामिल किया जा सकता है। यही कारण है कि विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने ऐसा नहीं किया

वर्तमान मामले में धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ए) और (बी) पर भरोसा करें, लेकिन इसके खंड (सी) पर भरोसा करें, यह तर्क देने के लिए कि इसके तहत न्यायाधीश या न्यायाधीश के अभियोजन के लिए बर्खास्तगी प्राप्त की जा सकती है।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को क्योंकि इस तरह के पद के धारक को संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (4) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए यह एकमात्र तर्क है और इसलिए, इसकी दृढ़ता का परीक्षण किया जाना चाहिए।

धारा 6 (1) (सी) किसी भी [1991] 3 एस. सी. आर. के मामले में पूर्व मंजूरी का प्रावधान करती है।

290

#### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अन्य व्यक्ति, उसे अपने पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी का '। अनुच्छेद 124 के खंड (4) और (5) जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू होते हैं, उन्हें उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर लागू किया जाता है -

अनुच्छेद 218 का गुण। तैयार संदर्भ के लिए इन्हें यहाँ फिर से उद्धृत किया जा सकता है:

" 124. उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन।

( 1 ) ... ..

XXX

XXX

XXX

( 4 ) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होगा

राष्ट्रपति के आदेश को छोड़कर अपने पद से हटा दिया गया  
संसद के प्रत्येक सदन द्वारा एक संबोधन के बाद पारित किया गया

कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा समर्थित

सदन और कम से कम दो तिहाई के बहुमत से

उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य पहले से रहे हैं  
उसी सत्र में राष्ट्रपति को इस तरह के लिए भेजा गया

साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर चल।

( 5 ) संसद विधि द्वारा प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है -

पता प्रस्तुत करना और जाँच करना और  
न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या अक्षमता का प्रमाण

खंड (4)।

XXX

XXX

XXX

218. संबंधित कुछ प्रावधानों का अनुप्रयोग

उच्चतम न्यायालय से उच्च न्यायालयों तक। खंडों के प्रावधान

( 4 ) और अनुच्छेद 124 का (5) उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होगा।

न्यायालय के रूप में वे उच्चतम न्यायालय के संबंध में आवेदन करते हैं

रेफरी के लिए उच्च न्यायालय के संदर्भों का प्रतिस्थापन उच्चतम न्यायालय को किराए पर देता है "।

अनुच्छेद 124 (4) के अनुसार, एक न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है।

राष्ट्रपति के आदेश से संसद के प्रत्येक सदन द्वारा एक संबोधन के बाद पारित किया गया, जो साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर निर्धारित बहुमत द्वारा समर्थित था। चूंकि ऐसे मामले में हटाने का आदेश राष्ट्रपति द्वारा दिया जाना है, इसलिए विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी

धारा 6 (1) (सी) द्वारा अपेक्षित ऐसा न्यायाधीश राष्ट्रपति है और इस तरह से धारा 6 (1) (सी) को आकर्षित किया जाता है। सवाल यह है कि क्या यह तर्क मान्य है।

291

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [यर्मा, जे.]

इस तर्क में कई खामियां हैं। धारा 6 (1) (सी)

हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की बात करता है जो स्पष्ट रूप से हटाने के लिए प्राधिकारी की मूल क्षमता को इंगित करता है, न कि केवल इसके प्रक्रियात्मक या औपचारिक भाग को। दूसरे शब्दों में, प्राधिकरण को स्वयं हटाने या हटाने के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए सक्षम होना चाहिए, न कि जो केवल किसी अन्य प्राधिकरण के निर्णय का पालन करता है या उसे लागू करता है। इस निष्कर्ष को अंतुले निर्णय के उपरोक्त उद्धरण से बल मिलता है, जो लोक सेवक को हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी और लोक सेवक द्वारा धारण किए गए पद की प्रकृति के बीच ऊर्ध्वाधर पदानुक्रम की बात करता है, जिसमें यह संकेत दिया गया है कि हटाने वाले प्राधिकारी को यह निर्णय लेने के उद्देश्य से उसके सामने रखी गई सामग्री पर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए कि क्या लोक सेवक जिसके खिलाफ मंजूरी मांगी गई है, वह प्रथम दृष्टया अपने पद के दुरुपयोग का दोषी है या नहीं ताकि पद के धारक द्वारा उसे हटाकर पद और दुरुपयोग के बीच अंतर्संबंध को समाप्त करने का अवसर मिले। जाहिर है, इसके द्वारा परिकल्पित सक्षम मंजूरी प्राधिकरण एक ऊर्ध्वाधर है

लोक सेवक के कामकाज पर अधीक्षण की कुछ शक्ति रखने वाले पदानुक्रम में श्रेष्ठ। जहाँ किसी ऊर्ध्वाधर पदानुक्रम के अभाव में ऐसा कोई संबंध मौजूद नहीं है और सार्वजनिक पद का धारक एक संवैधानिक पदाधिकारी है जो की शक्ति के अधीन नहीं है

किसी भी वरिष्ठ के अधीक्षण, धारा 6 का उसमें संलग्न योजना के आधार पर कोई आवेदन नहीं हो सकता है। धारा 6 (1) (सी) के तहत 'हटाने' के लिए सक्षम अभिव्यक्ति प्राधिकरण, जब तक कि इस तरीके से इसका अर्थ नहीं लगाया जाता है, धारा 6 पर किए गए निर्माण के साथ गलत होगा और

अंतुले निर्णय में योजना।

एस. पी. गुप्ता और अन्य में। आदि। वी. भारत संघ और अन्य। आदि।,

[ 1982 ] 2 एस. सी. आर. 365 में यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश एक उच्च संवैधानिक पदाधिकारी होता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से निपटने के लिए कानूनी मंजूरी रखने वाले तंत्र के सवाल पर विचार करते समय, जिनके खिलाफ अंतर-संबंध की कमी और भ्रष्टाचार के आरोप थे।

बनाया गया, इसे निम्नानुसार कहा गया था:

गन्दे शब्दों में कहें तो सवाल यह है: क्या एक अड्डी होना चाहिए

राष्ट्रीय न्यायाधीश जिनका दुर्व्यवहार या ईमानदारी की कमी है सामने आते हुए वह एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में बने रहे या

स्थायी न्यायाधीश के रूप में पुष्टि? सबसे पहले जवाब

आवेग और सही नकारात्मक में होगा लेकिन सवाल

इस पर गहन विचार की आवश्यकता है। यदि दुर्व्यवहार या

सत्यनिष्ठा की कमी स्पष्ट रूप से स्वयं का प्रश्न है

निरंतरता स्पष्ट रूप से उत्पन्न नहीं हो सकती है और सभी संभावनाओं में

नियुक्ति प्राधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1991] 3 एस. सी. आर. का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा।

क्योंकि, ऐसी स्थिति में संबंधित न्यायाधीश स्वयं इस्तीफा दे देगा, लेकिन जब हम एक अतिरिक्त न्यायाधीश की ओर से दुर्व्यवहार या ईमानदारी की कमी की बात करते हैं, तो बड़े पैमाने पर मामले संदिग्ध दुर्व्यवहार और/या ईमानदारी की कमी के हैं, हालांकि जिम्मेदार और सम्मानजनक हलकों में व्यक्त की गई राय के आधार पर और जो गंभीर सवाल उठता है वह यह है कि क्या ऐसे मामलों में संबंधित अतिरिक्त न्यायाधीश को केवल राय सामग्री या ठोस तथ्यों पर हटा दिया जाना चाहिए और दुर्व्यवहार और/या ईमानदारी की कमी के आरोपों के संबंध में सामग्री पर जोर दिया जाना चाहिए? मेरे विचार में चूंकि यह प्रश्न उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश जैसे उच्च संवैधानिक पदाधिकारी के बने रहने से संबंधित है, इसलिए यदि केवल राय सामग्री के आधार पर कार्रवाई की जाती है तो यह उनकी सुरक्षा और न्यायिक स्वतंत्रता को खतरे में डाल देगा। इसके अलावा, अनुच्छेद में दर्शाई गई हटाने की नियमित प्रक्रिया को छोड़कर और संविधान या संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में दुर्व्यवहार और या अंतरंगता की कमी के आरोपों पर संबंधित न्यायाधीश के खिलाफ अनुशासनात्मक या अन्यथा जांच करने के लिए इसके पीछे कानूनी मंजूरी रखने वाला कोई तंत्र नहीं है। 124 ( 4 ) और (5) कला के साथ पढ़ें। 218 और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968। इसलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न

संदिग्ध दुर्व्यवहार के ऐसे मामलों में उत्पन्न होने वाली स्थिति

और/या ईमानदारी की रिपोर्ट की गई कमी यह है कि कौन निर्णय लेगा और कैसे कि क्या संबंधित न्यायाधीश वास्तव में किसी दुर्व्यवहार या भ्रष्टाचार के कार्य में लिप्त है? की अनुपस्थिति में कथित दुर्व्यवहार या भ्रष्टाचार के कार्य पर सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कानूनी मंजूरी रखने वाला संतोषजनक तंत्र, उसे हटाने का निर्णय केवल राय, रिपोर्ट, अफवाहों या गपशप के आधार पर किया गया होगा और उसके लिए अनुचित और अन्यायपूर्ण होने के अलावा ऐसा पाठ्यक्रम न्यायिक स्वतंत्रता की जड़ पर प्रहार करने के बराबर होगा। दूसरा विकल्प, अर्थात्, उसे किसी अन्य कार्यकाल के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जारी रखना या यदि कोई रिक्ति उपलब्ध है तो उसे स्थायी बनाना और फिर कला में दर्शाई गई नियमित प्रक्रिया के तहत उसे हटाने के लिए कार्रवाई करना। 124 ( 4 ) और (5) कला के साथ पढ़ें। 218 और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 बेटुका लग सकता है लेकिन इसे अपरिहार्य माना जाना चाहिए यदि

न्यायिक स्वतंत्रता, जो हमारे संविधान की एक प्रमुख आस्था है, को संरक्षित और संरक्षित किया जाना है। एक भ्रष्ट न्यायाधीश या दुर्व्यवहार करने वाले न्यायाधीश का न होना निर्विवाद रूप से सार्वजनिक हित में है, लेकिन साथ ही न्यायिक विचाराधीनता को संरक्षित करना सर्वोच्च सार्वजनिक हित में है। यह 293 का सवाल है।

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [वर्मा, जे.]

कम बुराई को चुनना और अनिवार्य रूप से होना चाहिए  
भ्रष्ट या बेईमानों की सुरक्षा के लिए नहीं अपनाया गया

न्यायाधीश लेकिन कई अन्य ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ लोगों की रक्षा करने के  
लिए

और मेहनती न्यायाधीश अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए;

यह एक ऐसी कीमत है जिससे समाज को इससे बचने के लिए भुगतान करना  
पड़ता है।

यदि न्यायिक स्वतंत्रता का त्याग कर दिया जाता है तो जो बुराई होगी।

जनहित के दृष्टिकोण से प्रश्न पर विचार करना।

इसलिए, मेरा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि

वर्तमान अतिरिक्त न्यायाधीशों के बने रहने का सवाल

अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में उनके प्रारंभिक कार्यकाल की समाप्ति

या स्थायी न्यायाधीशों के रूप में उपयुक्तता की कसौटी पर विचार किया

गया

द्वारा विचार की गई निकट महाभियोग प्रक्रिया से कुछ

कला. 124 ( 4 ) और संविधान के (5) "।

( तुलजापुरकर, जे.) (पीपी।

920-21 )

जैसा कि अब कानून है, यह किसी के लिए भी खुला  
नहीं है।

एकल व्यक्ति, चाहे वह राष्ट्रपति हो या प्रमुख

भारत का न्याय या कोई और किसी का संज्ञान लेने के लिए

न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या असमर्थता के आरोप और न्यायाधीशों के अधीन उनके आधार पर कोई भी कानूनी कार्रवाई करना।

( जांच) अधिनियम, 1968। लोक के सौ सदस्य

केवल राज्यसभा या पचास सदस्य ही ऐसा कर सकते हैं।

ऐसे आरोपों पर कोई भी कार्रवाई शुरू करें। स्वाभाविक रूप से, अन्य सभी

उनका संज्ञान लेने और उन पर कार्रवाई करने से बाहर रखा गया है

उन्हें। ....

( वेंकटरमैया, जे.) (पीपी। 1338-

39 )

( जोर दिया

गया)

भले ही उपरोक्त अवलोकन के संदर्भ में किए गए थे

उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर बने रहना और न्यायाधीशों का दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण, फिर भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की प्रकृति और आरोपों की स्थिति में भी उनसे निपटने के लिए मौजूदा कानून के तहत उपलब्ध एकमात्र कानूनी मंजूरी भ्रष्टाचार को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया था। यह इंगित किया गया था कि आम तौर पर अपने खिलाफ ठोस सामग्री का सामना करने वाला ऐसा व्यक्ति इस्तीफा दे देगा, लेकिन यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो एकमात्र उपाय उपलब्ध है कि उसे अनुच्छेद 124 के खंड (4) और (5) के अनुसार अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1991] 3 एस. सी. आर. के साथ पढ़ा जाए।

294

218 कानूनी मंजूरी के साथ एक उपयुक्त प्रावधान किए जाने तक संविधान का। यह भी बताया गया कि इस तरह से कार्य करने का उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संरक्षित करना और भ्रष्ट न्यायाधीश की रक्षा करना नहीं था, जो एक अपवाद थे। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए मौजूदा कानून की योजना पर विस्तार से विचार किया गया और यह भी माना गया कि संविधान के

अनुच्छेद 222 के तहत किसी अन्य उच्च न्यायालय को हस्तांतरित करने की शक्ति का प्रयोग भी इन कारणों से नहीं किया जा सकता है।

इस संदर्भ में अनुच्छेद 124 का खंड (5) भी काफी महत्वपूर्ण है। अधिनियम के प्रावधानों का निर्माण किया जाना चाहिए

एक सामंजस्यपूर्ण योजना प्रस्तुत करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 218 के साथ पठित अनुच्छेद 124 के खंड (4) और (5) की योजना के साथ भी फिट बैठता है। अनुच्छेद 124 का खंड (5) संसद द्वारा एक विशेष कानून के अधिनियमन को सक्षम बनाता है जो एक पते की प्रस्तुति की प्रक्रिया को विनियमित करने और खंड (4) के तहत एक न्यायाधीश के 'दुर्व्यवहार' या अक्षमता के 'जांच' और 'सबूत' के लिए है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 लागू किया है। वह यह है

यह महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 124 का खंड (5) एक न्यायाधीश के 'दुर्व्यवहार' के 'जांच' और 'सबूत' के क्षेत्र को शामिल करता है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि 'दुर्व्यवहार' अभिव्यक्ति का व्यापक महत्व है और

अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) में परिभाषित आपराधिक दुराचार इसके दायरे में शामिल है और साथ ही आपराधिक दुराचार से चूकने वाले न्यायाधीश का कम दुराचार भी शामिल है। न्यायाधीश के दुर्व्यवहार से निपटने के लिए अनुच्छेद 124 (5) द्वारा परिकल्पित विशेष कानून में 'दुर्व्यवहार' की 'जांच' और 'सबूत' के क्षेत्र को शामिल किया गया है और पद से हटाने के अनुच्छेद 124 (4) द्वारा प्रदान की गई एकमात्र सजा है। इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता कि अनुच्छेद 124 (5) इतना व्यापक है कि इसके दायरे में एक न्यायाधीश के हर आचरण को शामिल किया जा सकता है, जिसमें आपराधिक दुराचार भी शामिल है और प्रक्रिया निर्धारित की जाती है।

जाँच आ ओकर प्रमाण लेल। इस प्रकार, एक न्यायाधीश के किसी भी दुर्व्यवहार की जांच की प्रक्रिया के साथ-साथ इसके सबूत के लिए भी, संवैधानिक योजना में परिकल्पित अनुच्छेद 124 (5) के तहत संसद द्वारा अधिनियमित एक कानून। न्यायाधीशों के रूप में ऐसा कानून (जांच)

अधिनियम, 1968 और उसके तहत बनाए गए नियम अधिनियमित किए गए हैं। ये संविधान और उसके तहत कानून में प्रावधान किए गए थे

जब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 कानून में था

किताब। भ्रष्टाचार की रोकथाम का पूर्व अधिनियम और अस्तित्व जिस समय संविधान के अनुच्छेद 124 का खंड (4) और (5) बनाया गया था, उस समय का अधिनियम, 1947 संवैधानिक योजना का संकेत देता है कि

जाँच और सबूत से निपटने के लिए एक अलग संसदीय कानून

एक न्यायाधीश के दुर्व्यवहार पर स्पष्ट रूप से विचार किया गया था

इस श्रेणी के संवैधानिक अधिकारियों के लिए विशेष तंत्र 295

के. वीरास्वामी बनाम डी. ओ. आई [वी. ई. आर. एम, जे.]

सामान्य रूप से लोक सेवकों के लिए उपलब्ध और लागू सामान्य कानून के बावजूद, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 शामिल था। यदि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए संवैधानिक योजना में अनुच्छेद 124 के खंड (4) और (5) और संविधान के अनुच्छेद 218 के रूप में विशेष प्रावधान और अनुच्छेद 124 (5) के तहत संसद द्वारा विशेष अधिनियम का प्रावधान किया गया था, तो यह मानने का कोई वैध कारण नहीं हो सकता है कि वे केवल उनके लिए अधिनियमित इन विशेष प्रावधानों के अलावा सामान्य प्रावधानों द्वारा शासित हैं। इन विशेष प्रावधानों की आवश्यकता सामान्य प्रावधानों के उनके लिए अप्रयोज्य होने की दिशा में एक स्पष्ट संकेत है।

अन्य सार्वजनिक पदों पर आसीन लोक सेवकों पर लागू होता है, न कि संवैधानिक अधिकारियों के रूप में। राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में मानते हुए विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा सुझाए गए अधिनियम की धारा 6 (1) (सी) का निर्माण संविधान के अनुच्छेद 218 के साथ पठित अनुच्छेद 124 के खंड (4) और (5) में अधिनियमित प्रावधानों के साथ होगा। इस तरह का है निर्माण निस्संदेह बचने के लिए। यह और भी अधिक है, क्योंकि इस तरह के तर्क की अस्वीकृति किसी भी तरह से अधिनियम के प्रावधानों को खतरे में नहीं डालेगी क्योंकि इसके परिणामस्वरूप केवल उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों जैसे संवैधानिक अधिकारियों को उस अधिनियम के दायरे में लाने का प्रयास विफल हो जाएगा, जबकि यह अधिनियम सामान्य रूप से उन लोक सेवकों पर लागू होता रहेगा जो अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी देने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 6 की योजना के भीतर आते हैं जो उस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के संज्ञान के लिए एक पूर्व शर्त है।

यह भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि संधानम समिति

रिपोर्ट में न्यायपालिका को अपने दायरे में नहीं लिया गया था और इसने केवल गलती करने वाले न्यायाधीशों के मामलों से निपटने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने वाली एक प्रणाली तैयार करने के लिए कुछ सिफारिशों की थीं। संधानम समिति की सिफारिशों के अनुसरण में अधिनियम में किए गए 1964 के संशोधन ने अधिनियम में कोई संशोधन नहीं किया ताकि यह संकेत दिया जा सके कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी अधिनियम के दायरे में लाया गया था। इसके बाद न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1963 और उसके तहत बनाए गए नियमों को संविधान के अनुच्छेद 124 (5) के अनुसार न्यायाधीश के दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच और सबूत प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। एस. पी. गुप्ता में निर्णय बहुत बाद में दिया गया था और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार सहित दुराचार के आरोपों से उत्पन्न स्थितियों से निपटने के दौरान, यह माना गया था कि कानूनी मंजूरी के साथ एकमात्र तंत्र अस्तित्व में है जो संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (4) और (5) के तहत सक्षम है। यह मान लेना उचित है कि एस. पी. गुप्ता, 296 में निर्णय देते समय

[ 1991 ] 3 एस सी आर।

#### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जहां कुछ न्यायाधीशों के साथ व्यवहार करने का प्रश्न, जिनके खिलाफ सत्यनिष्ठा और भ्रष्टाचार की कमी का आरोप भी लगाया गया था और सवाल उनसे निपटने के लिए उपलब्ध तंत्र का था, विद्वान न्यायाधीश अधिनियम के प्रावधानों से अनजान नहीं हो सकते थे, यह विचार रखते हुए कि मौजूदा कानून के तहत उपलब्ध एकमात्र कानूनी तंत्र संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (4) और (5) के अनुसार है। ये यह ठहराने के लिए मजबूत कारण हैं कि अधिनियम की धारा 6 (1) (सी) उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए लागू नहीं है और इस कारण से इस तरह के संवैधानिक कार्य

ये अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं।

अधिनियम के अप्रयोज्य होने का संकेत देने वाला एक अतिरिक्त कारण है

अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (ई) में परिभाषित आपराधिक दुराचार को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लागू करने में व्यावहारिक कठिनाई। अधिनियम में 1964 के संशोधन द्वारा इस खंड को शामिल करने का इतिहास सर्वविदित है। जो पहले अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) में साक्ष्य का नियम था, उसे इस संशोधन द्वारा धारा 5 की उप-धारा (1) में खंड (ई) अंतःस्थापित करके आपराधिक दुराचार का एक ठोस अपराध बना दिया गया था। अपीलार्थी के विद्वान वकील के तर्क के अलावा कि असमर्थता

आय से अधिक परिसंपत्तियों के कब्जे के लिए संतोषजनक लेखा खंड (ई) में अपराध का एक घटक है, इस खंड की व्यावहारिक आवश्यकता उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लागू न होने का संकेत देने के लिए एक और संकेत है। तथ्य यह है कि अधिनियम की धारा 6 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी के अनुसार,

तम्बू प्राधिकरण को आय से अधिक संपत्ति के कब्जे के लिए संतोषजनक रूप से लेखा देने में लोक सेवक की असमर्थता के बारे में खुद को संतुष्ट करना पड़ता है। के रूप में

अंतुले में आयोजित, सक्षम प्राधिकारी को मंजूरी देने से पहले अपने दिमाग को लागू करना होगा और उसके सामने रखी गई सामग्री के आधार पर लोक सेवक के अभियोजन के लिए प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व के बारे में संतुष्ट होना होगा। एक वस्तुनिष्ठ राय बनाने के लिए, सक्षम प्राधिकारी के पास निस्संदेह जनता का संस्करण होना चाहिए।

संथानम समिति की रिपोर्ट से स्पष्ट करें कि नियम। अपने आचरण को विनियमित करने वाले लोक सेवकों पर लागू होता है

उन्हें अपनी परिसंपत्तियों की आवधिक जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है जो उनके सेवा रिकॉर्ड का एक हिस्सा बनाते हैं। की सिफारिशें

संथानम समिति जिसके बाद 1964 का संशोधन शामिल किया गया

धारा 5 की उप-धारा (1) में खंड (ई) बनाया गया था, कुछ सुझाव देते हैं लोक सेवकों के आचरण को नियंत्रित करने वाले नियमों में संशोधन

उनकी सभी संपत्तियों की आवधिक जानकारी देना। उप निर्धारित करना उसी योजना के एक भाग के रूप में खंड (ई) को सम्मिलित करके स्थायी अपराध

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई. (वर्मा, जे.)

संशोधन उस तरीके का भी सुझाव देता है जिसमें लोक सेवक पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा संतोषजनक रूप से लेखा देने में असमर्थता के अपराध की इस आवश्यकता की जांच की जा सकती है। खंड (ड) के इन शब्दों को कुछ ऐसा अर्थ दिया जाना चाहिए जो अभियोजन पक्ष पर, चाहे वह कितना भी हल्का क्यों न हो, अधिनियम की धारा 6 के तहत सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला बनाने का बोझ डाले और यह केवल तभी किया जा सकता है जब इसे उस योजना के एक हिस्से के रूप में पढ़ा जाए जिसके तहत लोक सेवक से अपनी संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है जिसके संदर्भ में अप्रमाणित भाग और संतोषजनक लेखा देने में उसकी असमर्थता का अनुमान लगाया जा सकता है। लोक सेवक सरकार के मामले में इस आवश्यकता को आसानी से पूरा किया जा सकता है, जिसमें उन्हें अपनी परिसंपत्तियों की आवधिक विवरणी प्रस्तुत करने और प्रत्येक भौतिक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के पदानुक्रम में वरिष्ठ को सूचित करने की आवश्यकता होती है, ताकि उसके सेवा रिकॉर्ड में हर समय उसकी ज्ञात परिसंपत्तियों का विवरण हो। ऐसे लोक सेवकों के मामले में जब भी अधिनियम की धारा 6 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी जाती है, तो सक्षम प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए लोक सेवक के सेवा रिकॉर्ड सहित उपलब्ध सामग्री के आधार पर अपेक्षित राय बना सकता है कि क्या खंड (ई) के तहत आय से अधिक संपत्ति रखने का अपराध, जिसे लोक सेवक संतोषजनक रूप से लेखा नहीं दे सकता है, प्रथम दृष्टया बनाया गया है। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में, उनकी संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने के किसी भी प्रावधान के तहत ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है ताकि उसका रिकॉर्ड प्रदान किया जा सके जिसके संदर्भ में ऐसी राय बनाई जा सके और संबंधित न्यायाधीश से जानकारी प्राप्त करने के लिए कानूनी प्राधिकरण के साथ कोई ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह भी इस दिशा में एक संकेत है कि संथानम समिति की रिपोर्ट के बाद 1964 के अधिनियम के संशोधन के बाद भी जब अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) में खंड (ई) डाला गया था, तो विधानमंडल का उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शामिल करने का इरादा नहीं था।

न्यायालय और उच्चतम न्यायालय अधिनियम के दायरे में आते हैं।

यदि अधिनियम उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर लागू होता है और

सर्वोच्च न्यायालय, यह स्पष्ट है कि यही बात भारत के मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और मुख्य चुनाव आयुक्त पर भी लागू होनी चाहिए। इस तरह की घटना में असंगत परिणाम सामने आएंगे, यह मानते हुए भी कि विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा सुझाए गए दिशानिर्देशों को इन पदों पर आसीन व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते समय अधिनियम में निहित माना जाता है। अधिनियम में इन दिशानिर्देशों को लागू करने की कानूनी अनुमति के अलावा,

स्पष्ट व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता है। पक्ष में प्रस्तुत दिशा-निर्देशों में, यह सुझाव दिया गया था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी को हमेशा [1991] 3 एस. सी. आर. शुरू करने के लिए भी पढ़ा जाना चाहिए।

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

298 अपराध की जाँच और राष्ट्रपति, धारा 6 (1) (सी) के तहत मंजूरी देते समय, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर भी कार्य करेंगे। यह मानते हुए कि अधिनियम में इस तरह के किसी भी प्रावधान के अभाव में ऐसा करने की अनुमति है, समस्या जो हमें सामने से घूरती है, वह यह है कि क्या किया जाना चाहिए जहां स्वयं भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ ऐसी कार्रवाई पर विचार किया जाता है। कोई भी प्रावधान जो भारत के मुख्य न्यायाधीश पर लागू नहीं हो सकता है, स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू नहीं हो सकता है; या उस मामले के लिए यहां तक कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी, यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश उनमें से किसी से ऊर्ध्वाधर नहीं है, तो ऐसा कोई ऊर्ध्वाधर पदानुक्रम नहीं है और भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी अधीक्षण की कोई शक्ति नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से बहुत कम: भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय का झुकाव सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अपने सहयोगियों पर केवल नैतिक अधिकार का प्रयोग करता है।

न्यायाधीश, जिनके पास इसके पीछे कानूनी मंजूरी है, इसे न्यायसंगत बनाते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और मुख्य चुनाव आयुक्त के मामले में स्थिति और अधिक रोचक होगी। जाहिर है; भारत के मुख्य न्यायाधीश उनसे संबंधित प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं और उस स्थिति में उस भूमिका को भरने के लिए कोई और नहीं है। संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि उनकी स्थिति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगी, लेकिन उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से उच्च पद पर रखने का इरादा नहीं हो सकता था। विद्वान महान्यायवादी द्वारा प्रस्तुत इस तर्क की दुर्बलता उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ अधिनियम के तहत विचारशील कार्रवाई की प्रक्रिया में भारत के मुख्य न्यायाधीश से जुड़े कुछ निहित दिशानिर्देशों की सहायता का आह्वान करने से अधिक प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं जिनका यह उत्तर देता है। इसके अलावा, यदि इस अधिनियम को इन संवैधानिक अधिकारियों पर लागू करने का इरादा था, तो इसे ऐसी खामियों को छोड़कर अधिनियमित नहीं किया जा सकता था जो इस उद्देश्य के लिए एक व्यापक योजना प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं।

सुनवाई में यह भी सुझाव दिया गया कि आवश्यकता की अनुपस्थिति

जनता के बाद अधिनियम की धारा 6 के तहत अभियोजन के लिए सजा

नौकर अंतुले में आयोजित पद धारण करना बंद कर देता है, इस मामले में निर्माण के सवाल का जवाब देता है। ऐसा प्रतीत नहीं होता। सार्वजनिक पद के धारक पर मुकदमा चलाने के लिए धारा 6 के तहत मंजूरी की आवश्यकता यह तय करने के लिए अधिनियम के निषेध और दायरे को इंगित करती है कि क्या सार्वजनिक पद का धारक अधिनियम के दायरे में आता है। निस्संदेह, जैसा कि अंतुले में कहा गया है, लोक सेवक के पद धारण करना बंद करने के बाद धारा 6 के तहत अलगाव के लिए मंजूरी की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सार्वजनिक पद का प्रत्येक धारक उस पद को धारण करना बंद करने के बाद अधिनियम के दायरे में है, भले ही कार्यालय में कार्यकाल के दौरान, केवल वे लोक सेवक 299 हैं।

के. वीरास्वामी बनाम 0. 1 यू. ( वर्मा, जे ]]

इसके दायरे में जिसके मामले में मंजूरी धारा 6 प्राप्त की जानी चाहिए। अधिनियम के दायरे का निर्धारण लोक सेवक द्वारा धारण किए गए सार्वजनिक पद के आधार पर किया जाना है, जिसके बारे में आरोप है कि अपराध करने के लिए कार्यकाल के दौरान किस पद का दुरुपयोग किया गया था।

अधिनियम के तहत आपराधिक कदाचार होता है और यह उस पद पर बने रहने या इसे रखना बंद करने का तथ्य नहीं है जो अधिनियम के दायरे को तय करता है। दूसरे शब्दों में, यदि कार्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान किसी सार्वजनिक पद के धारक पर मंजूरी के बिना मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, तो धारा 6; तब; जैसा कि अंतुले में अभिनिर्धारित किया गया है, पद धारण करना बंद करने के बाद उसके अभियोजन के लिए मंजूरी आवश्यक हो सकती है, लेकिन उसका अभियोजन इसलिए किया जाता है क्योंकि कार्यालय में रहते हुए उस पर पूर्व मंजूरी के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है।

धारा 6. इसके विपरीत, यदि किसी सार्वजनिक पद के धारक पर उस पद पर बने रहने के दौरान धारा 6 की अप्रयोज्यता के कारण इस अधिनियम के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और इसलिए, धारा 6 के तहत अभियोजन के लिए पूर्व-विवेकपूर्ण मंजूरी की गैर-व्यवहार्यता, तो उसके पद पर बने रहने पर, उसे अधिनियम के दायरे में केवल इसलिए लाया जाता है क्योंकि अंतुले निर्णय लेता है कि उसके तहत अभियोजन के लिए मंजूरी दी गई है। सार्वजनिक पद के धारक के उस पद पर बने रहना बंद करने के बाद धारा 6 की आवश्यकता होती है। अधिनियम के

प्रावधानों का अर्थ निकालने और उसके दायरे और दायरे को निर्धारित करने और यह तय करने के उद्देश्य से कि क्या सार्वजनिक पद का धारक अधिनियम के दायरे में आता है, अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी की व्यवहार्यता और अधिनियम की धारा 6 की प्रयोज्यता महत्वपूर्ण है: संक्षेप में, यह अधिनियम के प्रावधानों के निर्माण और इसके दायरे को निर्धारित करने के उद्देश्य से है कि धारा 6 जो आपराधिक अपराध के लिए अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी की शर्त को निर्धारित करती है।

अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत दंडनीय अवैध दुराचार, वह कुंजी रखता है जो अधिनियम के वास्तविक परिदृश्य को खोलता है।

एक वरिष्ठ द्वारा अभियोजन के लिए मंजूरी की अवधारणा इतनी अक्षम है

अधिनियम के कपड़े में त्रिगुणित रूप से बुना गया है कि पैटर्न है

इसके बिना अधूरा। स्पष्ट विधायी आशय यह है कि अधिनियम केवल उन लोगों पर लागू होता है जिनके मामले में इस तरह की मंजूरी की अवहेलना की जाती है और जिनके लिए मंजूरी का प्रावधान पूरी तरह से लागू नहीं हो सकता है, वे इसके दायरे से बाहर हैं। मंजूरी के लिए प्रावधान अधिनियम के मेहराब में मुख्य पत्थर की तरह है। एस. ए. एच. सी. टी. एन. और मेहराब के टुकड़ों को हटा दें।

यह निष्कर्ष कि अधिनियम इन संविधानों पर लागू नहीं होता है

राष्ट्रीय पदाधिकारी, अर्थात् उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और मुख्य चुनाव आयुक्त, को अधिनियम के दायरे से उनके बहिष्कार के रूप में माने जाने पर संदेह के साथ देखने की आवश्यकता नहीं है जैसे कि वे सामान्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1991] 3 एस. सी. आर. हैं।

अपने दायरे में। एक उचित धारणा यह इंगित करेगी कि इन संवैधानिक अधिकारियों का उद्देश्य कभी भी अधिनियम के दायरे में आना नहीं था जैसा कि शुरू में 1947 में अधिनियमित किया गया था, जब भारत सरकार अधिनियम, 1935 में संविधान के अनुच्छेद 124 (4) और (5) के समान प्रावधान मौजूद थे, और न ही संथानम की रिपोर्ट के बाद 1964 में अधिनियम में संशोधन करके ऐसा कोई प्रयास किया गया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में समिति और वही स्थिति बनी हुई है। यदि अब ऐसी स्थिति के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता महसूस की जाती है, तो उपाय इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त संसदीय कानून में निहित है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता को एक उचित और पर्याप्त तंत्र प्रदान करते हुए संभावित कार्यकारी प्रभाव से मुक्त रखना।

ऐसे संवैधानिक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच और जांच के बाद उनके मुकदमे और सजा के लिए। इसका उपाय यह नहीं है कि मौजूदा कानून का विस्तार किया जाए और इसमें कुछ दिशानिर्देशों को पढ़कर इसे व्यवहार्य बनाया जाए, जिनका इसमें कोई आधार नहीं है, क्योंकि इस अधिनियम का उद्देश्य उन पर लागू होना नहीं था। मौजूदा कानून की प्रयोज्यता की कसौटी प्रस्तावित दिशानिर्देशों की कानूनी मंजूरी और न्यायसंगतता होगी, जिसके बिना ऐसे व्यक्तियों के मामले में यह काम नहीं कर सकता है। वास्तव में, मौजूदा कानून में प्रस्तावित दिशानिर्देशों को निहितार्थ से पढ़ने की आवश्यकता एक स्पष्ट संकेत है कि जो कानून मौजूद है वह उन पर लागू नहीं होता है। सुझाए गए दिशा-निर्देशों की सहायता से कानून को लागू करना न्यायिक शिल्प कौशल के क्षेत्र में नहीं है, बल्कि एक वर्जिन क्षेत्र में विधायी शक्ति का गन दुरुपयोग है।

ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के निर्माता, व्यवहार करते हुए

ऐसे संवैधानिक अधिकारियों के साथ, केवल उनके बारे में विचार किया गया

एकमात्र सजा के रूप में अनुच्छेद 124 (4) में प्रदान किए गए तरीके से पद से हटाना; और अनुच्छेद 124 (5) के तहत संसद द्वारा अधिनियमित एक विशेष कानून, यहां तक कि सामान्य कानून के बजाय एक वरिष्ठ न्यायाधीश के खिलाफ कथित दुर्व्यवहार की जांच और सबूत के लिए भी स्पष्ट रूप से देखा गया था जब कथित दुर्व्यवहार उनके कार्यालय से जुड़ा हुआ है। एक वरिष्ठ न्यायाधीश के खिलाफ अपने पद का दुरुपयोग करके आपराधिक कदाचार के बराबर भ्रष्टाचार का आरोप निश्चित रूप से अनुच्छेद 124 (5) के तहत विचार किए गए दुर्व्यवहार के दायरे में आएगा, क्योंकि अपने पद का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार के रूप में एक न्यायाधीश का दुर्व्यवहार एक भ्रष्ट न्यायाधीश को दंडित करने के लिए अन्य कानूनी मंजूरी, यदि कोई हो, के बावजूद, उसे पद से हटाने को उचित ठहराते हुए घोर दुर्व्यवहार का कार्य होगा। यह कल्पना नहीं की जा सकती है कि संविधान के निर्माताओं ने एक वरिष्ठ न्यायाधीश को दुर्व्यवहार के कम आधार पर हटाने का प्रावधान किया था, लेकिन न ही भ्रष्टाचार के घोर दुर्व्यवहार के लिए। इस निष्कर्ष से बचने की कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी न्यायाधीश के भ्रष्टाचार का घोर दुर्व्यवहार निस्संदेह उसके अधिकार को उचित ठहराने वाले अनुच्छेद 124 (5) के दायरे में आना चाहिए।

अनुच्छेद 124 (4) में उपबंधित तरीके से निष्कासन। अनुच्छेद 124 (5) कॉन 301

के. वीरास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [वर्मा, जे.]

जाँच के लिए भी संसद द्वारा अधिनियमित एक विशेष कानून का प्रारूप तैयार करता है।

दुर्यवहार के किसी भी आरोप में शामिल होना जिसमें एक आरोप शामिल होना चाहिए भ्रष्टाचार। तो क्या यह कहा जा सकता है कि जाँच के दौरान

के तहत हटाने के उद्देश्य से भ्रष्टाचार के आरोप में

अनुच्छेद 124 (4) में आरती के तहत संसद द्वारा बनाए गए एक विशेष कानून की आवश्यकता है। क्ल 124 (5), यह उसके अभियोजन के लिए ऐसा नहीं है जो के तहत किया जा सकता है

मौजूदा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधान? ऐसा प्रतीत होता है।

कि संविधान निर्माताओं ने इसकी आवश्यकता पर विचार नहीं किया

उस स्तर पर एक न्यायाधीश का अभियोजन और उम्मीद की जाती है कि एक वरिष्ठ न्यायाधीश आरोपों के समर्थन में विश्वसनीय सामग्री का सामना करने पर इस्तीफा दे देंगे

दुर्यवहार, और यदि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तो अनुच्छेद के तहत उन्हें हटा दिया गया

124 ( 5 ) स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त होगा। उसकी आवश्यकता

अभियोजन की कल्पना नहीं की गई थी और इसलिए, में प्रावधान नहीं किया गया था

के तहत न्यायपालिका के कामकाज के कुछ समय के लिए अनुभव संविधान। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968,

बहुत बाद में संविधान के अनुच्छेद 124 (5) के तहत अधिनियमित किया गया था और

अधिनियम के 1964 के संशोधन के बाद। कि संसद ने किया

तब भी आरोपों की जांच के लिए कोई अन्य कानून नहीं बनाया गया एक वरिष्ठ न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार और उसके मुकदमे और सजा के लिए

उस अपराध के लिए और केवल न्यायाधीशों को अधिनियमित करने के साथ शेष सामग्री

( जांच) अधिनियम, 1968, एक को हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान करने के लिए

अनुच्छेद 124 (4) के तहत न्यायाधीश इस दिशा में एक स्पष्ट संकेत है कि

संसद ने अभी तक ऐसा कोई कानून बनाना समीचीन नहीं माना है। किसी वरिष्ठ के भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमे और सजा के लिए

न्यायाधीश, सिवाय निर्धारित तरीके से उसे पद से हटाने के। यह.

यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि न्यायाधीश (जांच) अधिनियम के प्रावधान,

1968, जांच के लिए प्रक्रिया और एक एल्लेगा का प्रमाण प्रदान करें एक वरिष्ठ न्यायाधीश के विरुद्ध भ्रष्टाचार की स्थिति और यदि उन पर भ्रष्टाचार अधिनियम लागू होता है, तो दो होंगे निवेश के लिए इन दोनों अधिनियमों के तहत अलग-अलग प्रक्रियाएं एक ही चार्ज में गैशन। क्या यह विसंगति और विसंगति हो सकती है?

अधिनियम बनाते समय संसद के एक सचेत कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराया गया

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968, अधिनियम में 1964 के संशोधन के बाद।

शायद, अब मुकदमे और दंड का प्रावधान करने वाले कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही है एक वरिष्ठ न्यायाधीश, जिस पर अपने पद का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार के आपराधिक कदाचार का आरोप लगाया जाता है। यदि ऐसा है, तो संसद एकमात्र मध्यस्थ होने के नाते, यह संसद पर है कि वह कदम उठाए और संवैधानिक योजना के अनुरूप उपयुक्त कानून बनाए जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए अनुकूल है और यह इस न्यायालय के लिए नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1991] 3 एस. सी. आर. को शामिल करने के लिए मौजूदा कानून के संचालन के क्षेत्र का विस्तार करे।

302

वरिष्ठ न्यायाधीश निहितार्थ द्वारा मौजूदा कानून में पढ़े जाने वाले दिशानिर्देशों को लागू करने के विधायी कार्य को हड़पकर, क्योंकि प्रस्तावित दिशानिर्देशों के बिना मौजूदा कानून उन पर लागू नहीं हो सकता है। न्यायालय द्वारा इस तरह की कवायद का अर्थ एम्बी नहीं है

इसके अधिनियमन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए गॉस प्रावधान, लेकिन यह कानून के एक वर्जिन क्षेत्र पर शिकंजा कसने और मौजूदा कानून के दायरे में इसके बाहर के व्यक्तियों की एक श्रेणी को लाने का कार्य होगा, जिनके लिए यह लागू करने का इरादा नहीं था जैसा कि शुरू में अधिनियमित किया गया था या जब बाद में संशोधित किया गया था।

इस संदर्भ में यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि

दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का एक और आयाम भी है। संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी कि वरिष्ठ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संवैधानिक योजना यह सुनिश्चित करेगी कि सभी संवैधानिक अधिकारियों द्वारा एक वरिष्ठ न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया में अपने दायित्व का ईमानदारी से पालन करके, भ्रष्टाचार के कार्य के लिए ऐसे उच्च पद पर किसी भी नियुक्त व्यक्ति पर मुकदमा चलाने और उसे दंडित करने का कोई अवसर नहीं होगा। वरिष्ठ न्यायाधीशों की नियुक्ति कानूनी पेशे में ज्ञात पृष्ठभूमि और प्रतिष्ठा वाले परिपक्व आयु के व्यक्तियों में से होती है। उस उम्र तक व्यक्तित्व पूरी तरह से विकसित हो जाता है और नियुक्त व्यक्ति की प्रवृत्ति और पृष्ठभूमि सर्वविदित हो जाती है। एक वरिष्ठ न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए उप-उपकर में शामिल संवैधानिक अधिकारियों के व्यापक व्याख्यात्मक ज्ञान से यह सुनिश्चित होने की उम्मीद है कि लोग

इन उच्च पदों पर केवल निर्विवाद सत्यनिष्ठा की नियुक्ति की जाती है

और कोई संदिग्ध व्यक्ति प्रवेश नहीं करते हैं। किसी भी देरी से शुरू होने या अपवाद के मामले में, अनुच्छेद 124 (5) के तहत निर्धारित प्रक्रिया को अपनाकर अनुच्छेद 124 (4) के अनुसार हटाने की शक्ति न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए असाधारण खतरे को खत्म करने के लिए पर्याप्त होने की उम्मीद थी। यदि यह योजना वर्तमान संदर्भ में अपर्याप्त पाई जाती है, तो यह नियुक्तियों की प्रक्रिया में शामिल संवैधानिक राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के विश्वास को पूरा करने में विफलता का भी संकेत है। यह संभावना नहीं है कि इस दायित्व के निर्वहन में उनसे अपेक्षित देखभाल और ध्यान सभी मामलों में नहीं दिया गया है। इसलिए अब इस तरह के कानून की आवश्यकता पूरी तरह से इसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं होगी, बल्कि इस संविधान के उचित निर्वहन की विफलता के कारण भी होगी।

दायित्व और संवैधानिक योजना में कोई दोष नहीं। यह समय आ गया है कि वरिष्ठ न्यायाधीशों की नियुक्ति पर लगे उपकर में शामिल सभी संवैधानिक अधिकारियों को अपने संवैधानिक दायित्व के गंभीर निहितार्थ के प्रति पूरी तरह से सचेत रहना चाहिए और इसके निर्वहन में उत्साही होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी संदिग्ध नियुक्ति नहीं की जा सकती है, भले ही कभी-कभी कोई अच्छी नियुक्ति न हो। इसे हासिल करना मुश्किल नहीं है। नियुक्ति प्रक्रिया का कार्य 303 है।

इस प्रश्न से जुड़ा मामला और इससे अलग नहीं हुआ। सबसे अधिक अक्सर, यह केवल एक खराब नियुक्ति होती है जिसे टाला जा सकता था जो इस तरह के कानून की आवश्यकता पर

सवाल उठाने वाली स्थिति को जन्म देती है। इसलिए, उपचारात्मक उपाय करते समय भी रोकथाम पर उचित जोर दिया जाना चाहिए।

यह नियुक्ति पेशेवर के काम करने पर एक दुखद टिप्पणी है।

सामान्य तौर पर न्यायिक समुदाय के लिए यह एक दुखद दिन होगा कि वह संदिग्ध बन जाए और उसे सही रास्ते पर रखने के लिए इस तरह के कानून की आवश्यकता हो। हालाँकि, यह वह कीमत है जो पूरे समुदाय को चुकानी पड़ती है यदि नैतिक और सामाजिक मंजूरी के रूप में इसकी आंतरिक जांच में कमी पाई जाती है और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अपर्याप्त पाई जाती है जिसे केवल कानूनी मंजूरी ही रोक सकती है। इसके लिए है। संसद यह निर्णय करेगी कि क्या वह स्तर उच्चतर न्यायपालिका में पहुंच गया है, जब केवल कानूनी मंजूरी ही उच्चतर न्यायपालिका की अखंडता में जनता के विश्वास को बनाए रखने का उपाय हो सकती है, जिसके बिना न्यायपालिका की स्वतंत्रता ही खतरे में पड़ जाएगी।

यह विचार कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश

ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के दायरे से बाहर हैं, संवैधानिक योजना के साथ मेल खाते हैं और वरिष्ठ न्यायाधीशों से संबंधित संपूर्ण मौजूदा कानून की कई बारीकियों के अनुरूप भी हैं, जबकि इसके विपरीत कई मौकों पर इसके साथ गड़बड़ करते हैं और कई अंतराल छोड़ देते हैं जिन्हें न्यायिक अभ्यास से भरा नहीं जा सकता है। विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा सुझाए गए दिशानिर्देशों को प्रस्तावित करने का पैच वर्क एक अस्वीकार्य न्यायिक अभ्यास होने के अलावा, एक पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण तस्वीर भी प्रस्तुत नहीं करता है और कई स्पष्ट प्रश्नों के उत्तर प्रदान करने में विफल रहता है जो उत्पन्न होते हैं। अपरिहार्य कॉन [1991] 3 एस. सी. आर.

अतः यह अटकल है कि 1964 के संशोधन द्वारा संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू नहीं होता है। न्यायिक रूप से यह निष्कर्ष अभिशाप नहीं होना चाहिए जैसा कि सुबह 46 बजे कहा गया है। जुर। 2 डी। एस. 84 :

" एक कानून के अभाव में, एक न्यायिक की कदाचार अधिकारी आपराधिक अपराध नहीं है, महाभियोग है अनन्य उपचार "। ये शब्द उन वरिष्ठ न्यायाधीशों के मामले में वास्तविक कानूनी स्थिति का सारांश देते हैं जिन्हें संवैधानिक योजना में ही अलग से वर्गीकृत किया गया है।

योजना के बाद से उपरोक्त दृष्टिकोण में कुछ भी अजीब नहीं है। कुछ अन्य देशों में भी ऐसा ही प्रतीत होता है। हाल के वर्षों में कुछ देशों में ऐसे उदाहरण थे जिन्होंने इस विषय पर एक मजबूत बहस को उकसाया और स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न उपायों की वकालत की गई। यह

उल्लेख किया जा सकता है कि पिछली शताब्दियों में लॉर्ड बेकन के अभियोग सहित भ्रष्टाचार के लिए सजा के उदाहरण इस कारण से उपयुक्त नहीं हैं कि उस समय की स्थिति उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भारतीय संविधान की योजना और न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें दिए गए संरक्षण के समान नहीं थी।

जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, उपचारात्मक उपायों को अपनाते हुए रोग, भविष्य में इसकी रोकथाम पर नए सिरे से जोर दिया जाना चाहिए

दिमाग में रखा। इस संदर्भ में, उस उच्च सम्मान को याद करना उपयोगी है जिसमें हमारे राष्ट्र के प्रमुख निर्माताओं द्वारा उच्च न्यायपालिका को उसके प्रारंभिक चरण में रखा गया था। 18 दिसंबर, 1947 को लिखे एक पत्र में,

प्रधानमंत्री, पं. जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश सरदार वल्लभभाई पटेल ने कहा:

" संविधान अधिनियम के तहत प्रावधान किए जा सकते हैं। नियुक्ति, वेतन, पेंशन, छुट्टी और न्यायाधीशों को हटाना। इसके अलावा, मुझे लगता है कि यह होगा अधिनियम के तहत कोई प्रावधान सम्मिलित करना या उसे तैयार करना वांछनीय है। अधिनियम के तहत वैधानिक नियम, संबंधों के दांव को परिभाषित करता है न्यायपालिका और कार्यपालिका को कमजोर करें। सभी संचार नियुक्तियों और शिकायतों के संबंध में, यदि कोई हो, न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश से आना चाहिए

प्रांतीय उच्च न्यायालय, राज्यपाल के माध्यम से और इसके माध्यम से नहीं प्रांत का गृह विभाग। मैं समझता हूँ कि गवर्नर-जनरल या राष्ट्रपति, जो निर्वाचित होगा व्यक्ति, 305 के अनुसार मंत्रिमंडल से परामर्श करना होगा

केंद्रीय सरकार के काम करने के लिए बनाए गए कार्य के नियम मन में। हालाँकि, मुझे लगता है कि यह मौलिक रूप से आवश्यक है। कि उच्च न्यायालय, संघीय न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय (जब स्थापित हो) को एक हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए। कार्यपालिका के किसी भी विभाग का या उसके अधीन कार्य करना भारत सरकार। यह एक स्वतंत्र शाखा होनी चाहिए

सरकार सीधे राज्यपाल के संपर्क में है। भारत अधिराज्य के जनरल या राष्ट्रपति। मुझे विश्वास है कि मंत्रिमंडल इस सिद्धांत पर सहमत होगा - न्यायपालिका को निष्पादन के नियंत्रण से मुक्त रखना आप। इस उच्च परंपरा को बनाए रखने का कर्तव्य और श्रेय

सरकार अस्तित्व में है जब संविधान और वैधानिक नियम बनाए गए हैं, और मैंने यह लिखा है आपको विश्वास के साथ उम्मीद है कि आप सुरक्षित रहने की मेरी इच्छा को साझा करते हैं

न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करें और इस मामले में आवश्यक कार्य करें। सरदार वल्लभभाई पटेल ने तुरंत भारत के मुख्य न्यायाधीश को जवाब दिया यह कहते हुए कि आपके विचार हमसे निपटने में बहुत मददगार होंगे

विषय '।

संविधान निर्माताओं ने उच्च स्तर की कल्पना की थी

न्यायपालिका में कई ऐसे लोग शामिल हैं जो मजबूत नैतिक और नैतिक फाइबर के हैं जो स्वतंत्र भारत के समाज में नैतिक नेतृत्व प्रदान करेंगे और राज्य के अन्य अंगों के प्रहरी के रूप में कार्य करेंगे जिनकी उन्हें आवश्यकता नहीं है।

स्वयं की जाँच करें। हमारा संविधान संविधान की मूल संरचना के आवश्यक सिद्धांतों में से एक के रूप में न्यायिक समीक्षा के साथ राज्य की तीन शाखाओं की शक्तियों को अलग करने का प्रावधान करता है। इस प्रकार यह न्यायपालिका है जिसे संविधान की व्याख्या करने और यह सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है कि अन्य दो शाखाएं संविधान द्वारा उनके लिए निर्धारित सीमा को पार न करें। उच्च न्यायपालिका को सौंपे गए इस कर्तव्य के साथ, यह उम्मीद करना स्वाभाविक था कि उच्च न्यायपालिका को इस पर नजर रखने के लिए किसी अन्य एजेंसी की आवश्यकता नहीं होगी और समुदाय की नैतिक मंजूरी से बहने वाला आंतरिक अनुशासन इसे किसी भी बाहरी जांच की आवश्यकता के बिना सही रास्ते पर रखने के लिए पर्याप्त होगा, जिसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति हो सकती है, जो इसके संवैधानिक दायित्व के उचित प्रयोग के लिए एक आवश्यक संगत है। यही कारण है कि उच्च न्यायपालिका के साथ 307 में अलग व्यवहार किया गया था।

संविधान नियुक्ति करने के लिए तंत्र को पूर्व लेखन में दी गई बहुत सावधानी और ध्यान का संकेत देता है। यह उम्मीद की गई थी कि उस स्तर पर सत्य के मार्ग से कोई भी विचलन एक दुर्लभ घटना होगी और असाधारण स्थिति के लिए अनुच्छेद 124 के खंड (4) के अनुसार हटाने का प्रावधान किया गया था, उस पाठ्यक्रम को अपनाने में कठिनाई स्वयं उस दुर्लभता का संकेत है जिसके साथ इसे लागू करने की उम्मीद की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उस स्तर पर एक दुर्लभ विसंगति के लिए, जब तक कि उन्होंने ऐसी स्थिति का सामना करने पर इस्तीफा नहीं दिया, अनुच्छेद 124 (4) के अनुसार पद से हटाने की परिकल्पना एकमात्र कानूनी मंजूरी के रूप में की गई थी। अगर यही उम्मीद थी

स्वतंत्र भारत में न्यायपालिका के उच्च स्तर, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है उन्हें रोकथाम के दायरे में लाने की चूक भ्रष्टाचार अधिनियम, 1947, या उनके लिए इसी तरह के कानून का अभाव अकेले। जाहिर है, विचार-विमर्श के दौरान भी यह स्थिति बनी रही।

1964 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि इसने न्यायपालिका को बाहर माना है उसके विचार-विमर्श का दायरा। स्पष्ट रूप से, यह उम्मीद की गई थी कि उच्च न्यायपालिका जिसका शब्द सभी कानूनों की व्याख्या में अंतिम होगा संविधान सहित, इसमें नेतृत्व करने वाले पुरुष शामिल होंगे आत्म-त्याग की भावना अपने दायित्वों से अधिक संबंधित है अधिकार, ताकि किसी और के बैठने का अवसर न मिले उन पर निर्णय लें। यदि यह माना जाए कि स्थिति बदल गई है। उच्चतम स्तर पर न्यायाधीशों के आचरण की जांच की आवश्यकता होती है।

और यह संसद को तय करना है, फिर उपाय यह उस उद्देश्य के लिए सुरक्षित प्रावधान करने के लिए उपयुक्त कानून बनाने में निहित है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए रक्षक क्योंकि मौजूदा कानून करता है उस स्थिति के लिए प्रदान न करें। न्यायाधीशों को लाने का कोई भी प्रयास पूर्ववर्ती के दायरे में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय एक प्रतीत होने वाली निर्माणात्मक कवायद द्वारा भ्रष्टाचार अधिनियम का गठन अधिनियम, मुझे, पूरी विनम्रता में, एक वर्ग में फिट होने के लिए एक अभ्यास प्रतीत होता है एक गोल छेद में खूटी जब दोनों का कभी मिलान करने का इरादा नहीं था।

इसलिए, मैं बहुमत से भी अपील की अनुमति दूंगा। देखें कि यह विफल होना चाहिए।

आदेश

बहुमत के फैसलों को देखते हुए, अपील खारिज कर दी जाती है।

याचिका

खारिज कर दी गई।

आर. पी.